निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी दैनिक

नवबिहार टाइम्स

• बोकारो, शनिवार, 23 अगस्त 2025 • वर्ष : 09 • अंक : 97 • पृष्ठ : 12 • मूल्य : 3.00 रु. • RNI No. : JHAHIN2017/72655 • बोकारो व औरंगाबाद से प्रकाशित

देश और दुनिया के इतिहास में आज की प्रमुख घटनाएं

1976: चीन में भूकंप से हजारों लोगों की मौत।

2003: पाकिस्तान के राष्ट्रपति पने पाकिस्तान में न्यूनतम सुरक्षात्मक हथियार क़ायम रखने की घोषणा की।

2007: यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियाँ शामिल की गईं।

2007: पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाज शरीफ़ को स्वदेश वापसी की अनुमति दी।

संक्षिप्त समाचार

जाली नोट तस्कर को किया गिरफ्तार

साहिबगंज(नबिटा ब्यूरो)। पश्चिम बंगाल वैष्णव नगर थाना क्षेत्र बांग्लादेश बॉर्डर से साहिबगंज बरहरवा जीआरपी पुलिस ने जाली नोट तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के वैष्णव नगर थाना अंतर्गत हटाकपारा बौछा पारा, जो बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है, वहां से जाली नोट तस्कर रंजन मंडल को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 500 रुपए के पांच हजार रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं।

अनियंत्रित कार तालाब में घुसी, युवती की मौत

गिरिडीह(नबिटा ब्यूरो)। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कर्णपुरा एसआर पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर पानी से भरे तालाब में जा घुसी। हादसे में कार सवार एक युवती की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। मृतका की पहचान कोमल सिन्हा के रूप में की गई है। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार बेंगाबाद से गिरिडीह की ओर जा रही थी। इसी क्रम में सामने से आ रहे वाहन की तेज रोशनी से चालक चौंक गया जिससे कार सीधे तालाब में जा गिरी।

मेडिकल के छात्र ने की आत्महत्या

जमशेदपुर (नबिटा ब्यूरो)। झारखंड के जमशेदपुर स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की सूचना मिलने के 45 मिनट बाद तक एंबुलेंस नहीं पहुंची। सुसाइड करने वाले छात्र का नाम दिव्यांशु पांडे (21) है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद आनन-फानन में एंबुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन 45 मिनट भी एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद छात्र को प्राइवेट कार से मर्सी अस्पताल ले जाया गया जहां से डॉक्टरों ने उसे टीएमएच रेफर कर दिया। टीएमएच में डॉक्टरों ने जांच के बाद दिव्यांशु को मृत घोषित कर दिया।

पीएलएफआई सुप्रीमो पर कसा इडी का शिकंजा

रांची(नबिटा ब्यूरो)। दुर्दांत उग्रवादी और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ अब ईडी का शिकंजा कसने लगा है। ईडी ने दिनेश गोप के द्वारा खौफ के बल पर कमाई गई अकूत संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में ईडी ने दो दिन पूर्व दिनेश गोप को गिरफ्तार किया था। ईडी के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के सुप्रीमो दिनेश गोप को हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, आपराधिक गतिविधियों तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दर्ज मामले से संबंधित धन-शोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

कोलकाता में पीएम मोदी ने 5,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास-उदघाटन

शहरी परिदृश्य को नई पहचान दे रहा आधुनिक भारत : मोदी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोलकाता जैसे शहर भारत के इतिहास और भविष्य दोनों का समृद्ध प्रतीक हैं और जैसे-जैसे भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वैसे-वैसे दमदम और कोलकाता जैसे शहर इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नोआपाड़ा से जय हिंद एयरपोर्ट तक मेट्रो यात्रा का अनुभव साझा किया और बताया कि लोगों ने सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण को लेकर खुशी जताई। उन्होंने 13.61 किमी लंबे नए मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया, जिसमें नोआपाड़ा-जय हिंद एयरपोर्ट, सियालदह-एस्प्लानेड और बेलघरिया-हेमंत मुखोपाध्याय खंड की सेवाएं शुरू हुईं। इससे हवाई अड्डे तक पहुंच आसान होगी, सियालदह-एस्प्लानेड यात्रा समय 40 मिनट से घटकर 11 मिनट रह जाएगा और आईटी हब से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर नव-निर्मित सबवे का भी उद्घाटन किया और कहा कि अब हावड़ा और सियालदह जैसे देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशन मेट्रो से जुड़ गए

हैं, जिससे पहले डेढ़ घंटे की दूरी कुछ ही मिनटों में तय की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जो 2014 से पहले 250 किलोमीटर था और आज 1,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। कोलकाता मेट्रो में लगभग 14 किलोमीटर की नई लाइनें और 7 स्टेशन जोड़े जा रहे हैं, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी की परिवहन प्रणाली की मांग करता है, इसलिए देशभर में रेल, सड़क, मेट्रो और एयरपोर्ट को आधुनिक बनाया जा रहा है और उन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री ने कोना एक्सप्रेसवे के छह लेन वाले 7.2 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत 1,200 करोड़ रुपये है। इससे हावड़ा, कोलकाता और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, यात्रा समय घटेगा और क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अब 100 प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण पूरा करने वाले राज्यों में शामिल है, पुरुलियाऽहावड़ा मेमू ट्रेन की मांग पूरी कर दी गई है और राज्य में 9 वंदे भारत तथा 2 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि आज का यह कार्यक्रम सिर्फ मेट्रो का उद्घाटन या हाइवे का शिलान्यास नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक भारत अपने शहरी परिदृश्य को नई पहचान दे रहा है और ग्रीन मोबिलिटी, वेस्ट टू वेल्थ जैसी योजनाओं के जरिए सतत विकास की ओर बढ़ रहा है।

झारखंड विधानसभा में 4296 करोड़ 62 लाख का अनुपूरक बजट पेश

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

रांची। झारखंड विधानसभा में आज से पूरक मानसून सत्र की कार्यवाहा शुरू हो गई है। इस सत्र में 4296 करोड़ 62 लाख रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। सरकार की ओर से सदन के पटल पर 4296 करोड़ 62 लाख का अनुपूरक बजट रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसपर वाद विवाद सदन में आगे होगा। अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए सर्वाधिक राशि का प्रावधान किए जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस संदर्भ में मैं शुरू से कहता रहा हूं कि झारखंड की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना अनिवार्य है। जब तक ग्रामीण क्षेत्र मजबूत नहीं होगा तब तक झारखंड का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र मजबूत नहीं होगा। यही वजह है कि मूल बजट हो या फिर

अनुपूरक बजट में फंडिंग दिखेगी। चालू वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने सर्वाधिक ग्रामीण विकास विभाग को राशि देने का प्रावधान किया है। इसके तहत 96889.72 लाख की राशि दी गई है। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 41700 लाख रुपया दिया गया है। अनुपूरक में पंचायती राज विभाग को 9856 लाख रुपये, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक एवं शिक्षा मद में 42000 लाख रुपये, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को 6205.87 लाख रुपये, विधि विभाग को 2962.45 लाख रुपये, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को 3024.50 लाख रुपये, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 7915.57 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को 44863.30 लाख, वित्त विभाग को 83583.48 लाख, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को 20243.52 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बहरहाल सरकार द्वारा पेश अनुपूरक पर सोमवार 25 अगस्त से सदन में वाद-विवाद होगा तत्पश्चात इसे पारित किया जायेगा। सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित स्पीकर कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो का अभिनंदन किया।

दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राजधानी में बनेगा स्मृति स्थल

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

रांची। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राज्य सरकार भव्य स्मृति पार्क बनाने का निर्णय लिया है। विधानसभा परिसर में इसकी औपचारिक घोषणा नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने की है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में दिशोम गुरु के जीवन से संबंधित स्मृति पार्क बनाया जाएगा, इसके लिए जमीन चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही स्थान का चयन करके इसे मूर्तरूप देने का काम किया जाएगा ताकि यहां आनेवाले बाहर के लोग भी दिशोम गुरु के जीवन और उनके संघर्ष को जान सके। विधानसभा परिसर में पूरक मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। स्मृति पार्क में गुरुजी की आदमकद प्रतिमा, उनके संघर्ष और आंदोलन से जुड़ी तस्वीर के साथ पार्क और हॉल का निर्माण होगा जिससे यहां आनेवाले पर्यटकों को आसानी से गुरुजी शिबू सोरेन के बारे में जानकारी मिल सके। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर स्मृति पार्क राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित बाईपास में बनाए जाने

की संभावना है। प्रस्तावित निर्माण स्थल के लिए नगर विकास विभाग ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड से जमीन मांगी है। आवास बोर्ड ने जमीन चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है। आवास बोर्ड जल्द ही नगर विकास विभाग को जमीन मुहैया कराएगा। संभावना है कि रांची के बाईपास रोड में डीपीएस स्कूल के पास स्थित भुसूर मौजा में गुरुजी का स्मृति स्थल बनाए जाने पर मुहर लग जाए। इस मुख्य मार्ग पर स्थित भुसूर मौजा में कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है। हालांकि इसके लिए अंतिम मुहर कैबिनेट के निर्णय के बाद होगा जिसमें इसके निर्माण पर होनेवाले खर्च एवं अन्य राशि निर्धारित होगी।

यूरिया लदे ट्रक को घेरकर किसानों ने किया प्रदर्शन

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

गढ़वा। जिला के श्रीबंशीधर नगर क्षेत्र के किसान इन दिनों यूरिया खाद की भारी कमी से जूझ रहे हैं। शुक्रवार को गोसाईबाग मैदान में यूरिया से भरा एक ट्रक पहुंचा जिसे सात डीलरों के बीच बांटा जाना था। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना किसानों को मिली, सैकड़ों की संख्या में किसान मौके पर इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब खेतों में धान की फसल को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है तब यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद की आपूर्ति में गड़बड़ी हो रही है और इसका लाभ वास्तविक किसानों तक नहीं पहुंच रहा। कई किसानों ने बताया कि वे लगातार डीलरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। इससे

उनकी धान की फसल पर संकट मंडरा रहा है। किसानों के आक्रोश को देखते हुए स्थानीय थाना पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और स्थिति को शांत कराया गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सभी जरूरतमंद किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। किसानों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि यूरिया की किल्लत को तुरंत दूर किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में खाद का वितरण कराया जाए ताकि फसल बच सके और उनकी मेहनत पर पानी न फिरे। इस मामले को लेकर डीसी दिनेश यादव ने शख्त लहजे मे कहा कि अभी धन रोपनी का समय है। ऐसे में समय से यूरिया खाद्य उपलब्ध कराया जा रहा है जो डीलर लापरवाही करेंगे उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कारोबारी के घर से 32 लाख की चोरी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

गिरिडीह। जिले के सरिया थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने गुरुवार रात एक गल्ला व्यवसायी के घर से 17 लाख रुपए नगदी समेत लगभग 32 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने घर बनाने और बिजनेस के लिए बैंक से रुपए निकालकर घर में रखे थे। घटना की सूचना मिलने पर सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। सरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत अंतर्गत पेठियाटांड़ निवासी गल्ला व्यापारी कैलाश मंडल के यहां चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने रांची-दुमका मेन रोड को सड़क जाम कर चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग की। गल्ला व्यापारी कैलाश मंडल ने बताया कि मेन गेट के ताले को तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने सुबह उठकर देखा तो ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था। मकान में 17 लाख रुपए नगद और करीब 15 लाख रुपए की ज्वलेरी रखी हुई थी। जिसे चोर अपने साथ ले गए। इधर व्यवसायिक संघ और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर घटना का विरोध किया है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए ताकि घटनाओं पर नियंत्रण हो सके।

पांकी अंचलाधिकारी जय कुमार का निधन

पांकी (पलामू)। पांकी अंचलाधिकारी जयकुमार राम का निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। पांकी के सीओ रहे राजकुमार का तबादला होने के बाद जय कुमार राम की पोस्टिंग पांकी अंचल अधिकारी के रूप में हुई थी। तबीयत खराब रहने के कारण जय कुमार राम ने पांकी में काम ही नहीं किया। अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान वे मेदिनीनगर सदर प्रखंड पदाधिकारी के पद पर भी कार्य कर चुके थे। उन्हें सुगर सहित अन्य कई बीमारियां थी।

रांची में 19 बालू घाटों की नीलामी जल्द

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

रांची। झारखंड में बालू के अवैध कारोबार पर लगाम कसने और सरकारी खजाने को मजबूत करने के लिए हेमंत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब रांची जिले में 19 बालू घाटों की ई-नीलामी की जाएगी। इस कदम से न सिर्फ बालू माफियाओं की कमर टूटेगी बल्कि राज्य सरकार को सालाना करोड़ों रुपये का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। जिला खनन कार्यालय द्वारा जारी इस सूचना के बाद से खनन क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय झारखंड बालू खनन नियमावली, 2025 के तहत लिया गया है, जिसे हाल ही में लागू किया गया है। नियमावली के अनुसार चिह्नित किए गए 19 घाटों को कैटेगरी-2 में रखा गया है। पूरी प्रक्रिया

ऑनलाइन होगी, ताकि कोई भी इसमें गड़बड़ी न कर सके। खनन के इच्छुक आवेदक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ई-बोली की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रणाली सरकार को पूरी प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम बनाएगी जिससे भ्रष्टाचार और कालाबाजारी खत्म होगी। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में घाटों की नीलामी पारदर्शी तरीके से की जा रही है। नीलामी के लिए चुने गए घाटों में कांछी, रारु, पाकरो, सुवर्णरेखा, चट्टी और सपही जैसी प्रमुख नदियों के किनारे स्थित घाट शामिल हैं। कांची नदी के लोहातु, चुरगी, चिलुटीकर, सरजामडीह, अनरेदीह, करम्बू, पांगुरा, बरेदीह, तुनजू, एरकिया, सुमंडीह, सुतिलौंग, बादला, गोमियाडीह, हराडीह, दारूआरा, सोमाडीह, रारु नदी के श्यामनगर, बिरदीडीह, करेयाडीह, इचाहातु, पाकरो नदी के बसंतपुर, स्वर्णरेखा नदी के श्यामनगर, चोकेसेरंग, डुमरबेरा, सुंदील, चट्टी नदी के लपरा एवं सपही नदी के चूरी व राय घाटों की निलामी की जायेगी। अधिकारियों ने बताया कि ई-नीलामी का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। गौरतलब हो कि यह कदम न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा बदलाव लाएगा।

FOR REGISTRATION : ISO, TRADE MARK, PATENT

DESIGN AND COPYRIGHT, ATTORNEY

GLOBAL VISION

(A Complete Solution in Professional Services)

: Regd. Office/ Head Office :
Manaitand, Near Water Tank
Dhanbad, Jharkhand- 826001
Command Office : Jagat Trade Centre, Patna

Contact No.- 9835333441, 8210823092

E-Mail : globalvision96@yahoo.in

संक्षिप्त समाचार

जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू, 252 मौजों में भौतिक निरीक्षण अनिवार्य

बक्सर, एजेंसी। जिला निबंधन कार्यालय ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं।अब जिले के 252 मौजों में जमीन की रजिस्ट्री से पहले भौतिक निरीक्षण अनिवार्य होगा। इस संबंध में गुरुवार को निबंधन कार्यालय के सूचना पट्ट पर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सभी निबंधनार्थियों को सूचित किया गया है।जारी नोटिस के अनुसार, बक्सर, इटाढ़ी और चौसा अंचल के 252 मौजों को स्थल जांच के दायरे में शामिल किया गया है। पहले यह नियम केवल शहरी क्षेत्रों से सटे मौजों पर लागू था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।निबंधनार्थियों को रजिस्ट्री से तीन से चार दिन पहले निबंधन कार्यालय में एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके बाद कार्यालय के कर्मचारी संबंधित जमीन का स्थल निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।जिला निबंधन पदाधिकारी आसीत कुमार सिंह ने बताया कि यह निर्णय विभागीय आदेश के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि बक्सर, चौसा और ईटाढ़ी अंचल के 252 मौजों को स्थल जांच के दायरे में शामिल किया गया है ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो।यह नया नियम जमीन के स्वामित्व और दस्तावेजों की सत्यता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। निबंधनार्थियों से अपील की गई है कि वे रजिस्ट्री से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म समय पर जमा करें ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।

पटना में फेयर प्राइस डीलरों का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठियां भांजी और वाटर कैनन का किया इस्तेमाल

पटना, एजेंसी। बिहार फेयर प्राइस विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हाथापाई हुई. इस दौरान पुलिस ने डीलर एसोसिएशन पर लाठीचार्ज किया. भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा.

पटना में लाठीचार्ज- मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि हर कोई विरोध करता है, लेकिन वह शांतिपूर्ण होनी चाहिए. डीएसपी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला क्रॉसिंग को दोनों तरफ से जाम कर दिया था.डीएसपी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को गर्दनीबाग जाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे थे.

समस्तीपुर बाइपास में मॉनिंग वॉक कर रहे अधिवक्ता अचानक गिर गए, मौत

समस्तीपुर, एजेंसी। शहर के एक अधिवक्ता की मौत शुक्रवार की सुबह सात बजे के करीब बाइपास सड़क पर धमक चौक के नजदीक मार्निंग वाक के दौरान हो गई। आसपास के लोगों ने उन्हें सड़क पर मृत देख सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। अधिवक्ता की पहचान बहादुरपुर मोहल्ले में रहने वाले मनोज कुमार महतो के रूप में हुई। वे मूल रूप से खानपुर थाना के शोभन गांव के निवासी थे।

बताया गया कि वे अलसुबह प्रत्येक दिन की भांति मार्निंग वाक पर निकले थे। इसी दौरान हृदयाघात होने की वजह से सड़क किनारे गिर पड़े। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

सुबह अन्य लोगों ने जब एक व्यक्ति को अचेतावस्था में गिरा देखा तो सूचना पुलिस को दी। थानाध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया।

उनकी पहचान होने के बाद स्वजन भी भागे भागे सरस्वती अस्पताल पहुंचे। इधर, मौत की जानकारी मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। सभी अस्पताल परिसर में ही रोने बिलखने लगे। वहीं एफएसएल की टीम ने घटना की छानबीन की है।

बिहार में मुर्गा चोरी करने पर युवक की हत्या !, रिश्तेदार ने घटना को दिया अंजाम

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि मुर्गा चोरी के आरोप में युवक को मौत के घाट उतारा गया है. मृतक युवक की पहचान संजय सहनी उम्र 40 साल के रूप में हुई है. ये घटना आज रामपुर हरि थाना क्षेत्र के कोइली गांव में घटी है.

अहले सुबह शौच करने गए थे संजय- मृतक की पत्नी पार्वती देवी ने बताया कि मेरे पति रोज की तरह सुबह करीब पांच बजे शौच के लिए घर से निकले थे. थोड़ी देर बाद ग्रामीणों से सूचना मिली कि उनकी लाश गांव के ही एक बगीचे में मिली है.

अब जेल जाने वाला कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, पीएम मोदी का बिहार से सख्त संदेश

गया, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं. इस दौरान उन्होंने गया से हुंकार भरी. विपक्षी को निशाने पर लिया. साथ ही कह दिया कि कोई जेल में रहता है तो सरकार कैसे चला सकता है, इसीलिए सरकार द्वारा कानून लाया गया है.नए कानून पर विपक्ष को घेरा - पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रखा जाए तो वह अपने-आप निलंबित हो जाता है. लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, मंत्री है या प्रधानमंत्री है, तो वह जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है.हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश जारी किए जा रहे थे. नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा, तो

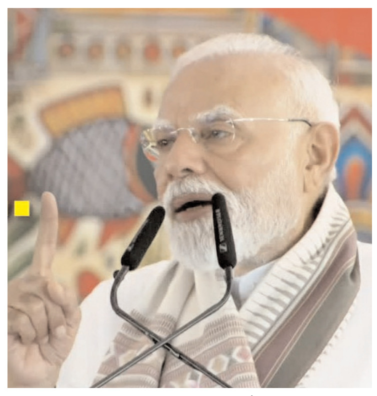

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्रीपीएम मोदी ने आगे कहा संविधान की मर्यादा तार तार हो, ये हमलोग नहीं देख सकते है. इसलिए केन्द्र की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा कानून लेकर आई, जिसमें कोई नहीं बच सकता है. चाहे वो देश का पीएम हो या फिर मुख्यमंत्री या मंत्री. कानून बनने के बाद गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर जमानत लेनी होगी. अगर बेल नहीं मिली तो कुर्सी छोड़नी होगी. लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं.

केन्द्र ने लाया है 130वां संविधान संसोधन विधेयक - बता दें कि केन्द्र सरकार ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में 130वें संविधान संसोधन विधेयक को पेश किया. इसके बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया है. इस कानून के बनने के बाद अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, अगर वह अपना पदत्याग नहीं करता है तो अपने आप उसकी कुर्सी चली जाएगी.हालांकि इस विधेयक में यह भी साफ है कि आरोप मुक्त होकर वह निकलते हैं तो उन्हें फिर से सत्तासीन किया जा सकता है. वैसे इस मामले से विधायक और सांसद को अलग रखा गया है. वैसे पहले से कानून है कि किसी पर अगर आरोप सिद्ध होता है और दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है.

प्रधानमंत्री ने इस दौरान आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, आप याद कीजिए, लालटेन राज में यह क्षेत्र लाल आतंक में जकड़ा हुआ था. माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना-जाना मुश्किल हो जाता था. बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते थे. उन्हें गरीब के सुख-दुख, गरीब के मान-सम्मान से कोई मतलब नहीं था.गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे. हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे. लालटेन राज ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था. न शिक्षा थी, न रोजगार, बिहार की कितनी ही पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था.- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पहले परियोजनाओं को लटकाया जाता था - प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि हमारे देश में चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसों का मोल नहीं समझा. इनके लिए जनता के पैसों का मतलब सिर्फ अपनी तिजोरी भरना रहा है. इसी वजह से इनकी सरकारों में सालों-साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थीं. कोई योजना जितनी लटकती थी, ये उतना ही पैसा उसमें कमा लेते थे.

राजद को बड़ा झटका : गया में पीएम के साथ दिखे मंच पर आरजेडी के दो विधायक

पटना, एजेंसी। पीएम मोदी की गया में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के मंच पर दिखे राजद के दो विधायक। जिससे कयास लगाया जा रहा है कि ये दोनों एनडीए का दामन थाम सकते है। पर अभी तक ऑफिसियल सूचना नहीं मिली है। ये दोनों विधायक नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर हैं, जो पीएम मोदी की गया में आयोजित सभा में भाजपा के मंच पर मौजूद थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर आए। यहां पीएम मोदी ने गयाजी जिले के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को करीब 13 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। नवादा से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक विभा देवी है जो दुष्कर्म पीड़ित राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी है। राजवल्लभ यादव हाल ही में जेल से बाहर आये है और रजौली से विधायक प्रकाश वीर भी मंच पर है।

25 साल बाद सुल्तानगंज-देवघर रेल परियोजना को मंजूरी, बाबा बैद्यनाथ धाम और अजगैवीनाथ धाम जुड़ेंगे

सुल्तानगंज/देवघर, एजेंसी। 25 साल पुरानी और लंबित सुल्तानगंज (अजगैवीनाथ धाम)-देवघर रेल परियोजना को गति मिली। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ धाम और बिहार के अजगैवीनाथ के बीच सीधी रेल परियोजना पर केंद्र सरकार ने अपना मन बना लिया है। अजगैवीनाथ से देवघर के बीच इस रेल परियोजना का सपना 25 साल पहले देखा गया था, लेकिन आज तक यह लंबित था।सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने इसके लिए लगातार पहल किया। इसके बाद रेल मंत्रालय ने इस परियोजना को आगे बढ़ा दिया है। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंग प्रदेश और खासकर गोड्डा लोकसभा के साथ साथ संताल परगना को 25 साल पुराना लंबित रेल परियोजना दिया है।

जिस रेल परियोजना का सपना पूर्व रेल राज्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देखा था। प्रधानमंत्री ने उसे आज पूरा किया है। मोदी हैं तो मुमकिन है।सांसद ने इस परियोजना के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

को जहां बधाई दिया है। वहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पूरे अंग प्रदेश की जनता की ओर से अभिवादन किया।

जानकारी हो कि संताल परगना में रेल और रेल परियोजना नहीं थी। देवघर से गोड्डा की सीधी रेल लाइन नहीं थी। एक साल पहले 2024 में पीएम गति शक्ति योजना के तहत देवघर से मोहनपुर के बीच नयी रेल लाइन का उदघाटन प्रधानमंत्री ने किया इसके बाद देवघर से गोड्डा सीधी रेल लाइन चालू हो गया और गोड्डा तक ट्रेन जाने लगी।जिस गोड्डा में एक भी ट्रेन नहीं जा रही थी वहां से दिल्ली, पटना, रांची और अन्य गंतव्य के लंबी दूरी की ट्रेन चल रही है। अब सुल्तानगंज-देवघर नयी रेल परियोजना से उत्तरवाहिनी गंगा के तट से बाबाधाम का तट सीधा जुड़ जाएगा।अजगैवीनाथ धाम, सबौर, कहलगांव व पीरपैंती सहित छोटे स्टेशन पर टीटीई व सीआईटी की पोस्टिंग नहींअजगैवीनाथ धाम, नाथनगर, सबौर, कहलगांव, पीरपैंती सहित किसी भी स्टेशनों पर टीटीई की पोस्टिंग नहीं है। इन स्टेशनों पर क्यावयड चेकिंग टीम टिकटों की चेकिंग करती है। सीएमआई फुल कुमार शर्मा के अनुसार, टीटीई और सीआइटी की पोस्टिंग भागलपुर, जमालपुर, किऊल, साहिबगंज, मालदा जैसे बड़े जंक्शन स्टेशन पर ही पोस्टिंग होती है। अन्य स्टेशनों पर टीसी की प्रतिनियुक्ति होती है।अजगैवीनाथ धाम स्टेशन पर टीसी की प्रतिनियुक्ति है। टीसी की ड्यूटी सहयोग (पूछताछ केंद्र) में होती है। वहीं, कहलगांव, पीरपैंती, सबौर में स्टेशन मास्टर के कक्ष में ही सहयोग की व्यवस्था है। स्टेशन मास्टर ही ट्रेनों बारे में एनाउंसमेंट करते हैं। यात्रियों को ट्रेनों के बारे में जानकारी देते हैं। यही नहीं बांका और गोड्डा में भी यही व्यवस्था है। गोड्डा से भागलपुर के टीटीई ही ट्रेन लेकर आते हैं।

इन स्टेशनों पर स्क्वायड टीम द्वारा ही चेकिंग कराई जाती है। चेकिंग टीम के आधार पर ही सीआईटी का परफामेंस होता है। इसलिए कि सीआइटी के नेतृत्व में टिकट चेकिंग कराई जाती है। इसी के आधार पर भागलपुर के सीआइटी दिलीप कुमार चौरसिया को बेहतर कार्य के सम्मानित किया गया।

बिहार में श्वह्न की बड़ी कार्रवाई, अवर निबंधक विनय सौरभ के कई ठिकानों पर छापेमारी ; जानें क्या-क्या मिला

भागलपुर, एजेंसी। बिहार पुलिस की आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग की टीम ने भागलपुर के जिला अवर निबंधक विनय सौरभ के भागलपुर समेत कई ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की है।शुक्रवार की सुबह से आरंभ हुई यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ी है। भागलपुर में तैनात विनय सौरभ के विरुद्ध भ्रष्ट और अवैध तरीके से आय के स्रोतों से 1 करोड़ 43 लाख 78 हजार रुपये मूल्य की परिसंपत्ति अर्जित की है।जो उनके आय से करीब 188.23 प्रतिशत अधिक बताई गई है। इसी आरोप में आर्थिक अपराध थाना, पटना में 21 अगस्त 2025 को केस संख्या 21-2025 दर्ज की गई थी।विनय सौरभ के रोहतास, सासाराम के सनुआर शिव सागर स्थित पैतृक आवास, भागलपुर के खंजरपुर, बरारी स्थित अभिनव एनक्लेव के अलावा पूर्णिया में बाईपास स्थित पैनोरमा सिटी वाले आवास के अलावा भागलपुर स्थित उनके अवर निबंधक कार्यालय स्थित कक्ष में भी एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है।छापेमारी एवं तलाशी अभियान न्यायालय से जारी आदेश पर आर्थिक अपराध इकाई की आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग की टीम ने की है। तलाशी अभियान सभी ठिकानों पर तेजी से अधिकारियों की टीम कर रही है।सुरक्षा दृष्टिकोण से बरारी के खंजरपुर स्थित अभिनव एनक्लेव वाले फ्लैट पर काफी संख्या में पुलिस जवानों को लगाया गया है। निबंधन कार्यालय के बाहर भी किसी को जवान प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं।अंदर से कोई बाहर और बाहर से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत वहां तैनात सुरक्षाकर्मी नहीं दे रहे हैं। प्रारंभिक छापेमारी में तीन करोड़ से अधिक अर्जित संपत्ति का पता चला है।अभिनव एनक्लेव स्थित फ्लैट से विभिन्न बैंकों और बीमा कंपनी से जुड़ी डिपाजिट स्कीम के दस्तावेज, बांड और जमीन, फ्लैट के भी दस्तावेज मिले हैं। टीम को सोने और हीरे जड़े जेवरात भी मिले हैं।टीम उनका मूल्यांकन कर रही है। छापेमारी को अंदर गई टीम अपने साथ नोट गिनती करने वाली मशीन भी अंदर ले गई है। टीम के अंदर जाने के करीब दो घंटे बाद बोतल बंद पानी और नास्ते का पैकेट सुरक्षा में लगे जवान अंदर ले गए।

तेज प्रताप का सनसनीखेज खुलासा, पांच परिवारों पर राजनीतिक करियर खत्म करने का आरोप

पटना, एजेंसी। लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने सनसनीखेज दावा किया है. उनका कहना है कि उनकी राजनीतिक और पारिवारिक जिंदगी को खत्म करने की कोशिश पांच परिवारों ने मिलकर की.मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया- तेज प्रताप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा कि उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया. इसके बावजूद कुछ प्रभावशाली परिवार लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं.साजिश का पर्दाफाश करने का ऐलान- तेज प्रताप ने साफ कहा कि अब वे चुप नहीं रहेंगे. उन्होंने लिखा कि ÷कल मैं इन पांच परिवारों के चेहरे और उनके असली व्यक्तित्व को जनता के सामने लाऊंगा.÷ उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.चुनाव से पहले बड़ा दांव- जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप का यह खुलासा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है. खासकर तब, जब वे पहले ही आरजेडी से अलग होकर टीम तेज प्रताप यादव नाम से नई राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

नीतीश की राजनीति और जेडीयू का पिंडदान करने गयाजी आ रहे मोदी, बोले लालू यादव

पटना, एजेंसी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गयाजी दौरे को लेकर सियासी तापमान चढ़ गया है. आरजेडी प्रमुख लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीखा हमला बोला है. उन्होंने तंज कसते हुए पीएम के दौरे को जुमलेबाजी और राजनीतिक ड्रामे का हिस्सा बताया है.लालू का तंज पिंडदान करने आ रहे पीएम- लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा कर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि गयाजी पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है

और पीएम वहां नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी जेडीयू का ÷पिंडदान÷ करने आ रहे हैं.लालू यादव का केंद्र सरकार पर आरोप- लालू ने केंद्र सरकार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने, गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने डबल इंजन सरकार को बिहार में गरीबी और अपराध बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया है.तेजस्वी ने लगया झूठ और जुमले का आरोप- नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी के दौरे पर

निशाना साधते हुए इसे ÷झूठ और जुमलों की दुकान÷ करार दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक गाना शेयर किया, जिसमें पीएम पर झूठे वादों और जुमलेबाजी का आरोप लगाया गया. तेजस्वी ने पीएम से 11 साल की उनकी सरकार और नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार का हिसाब मांगा.आरजेडी जनता के मुद्दे उठाने में जुटी- आरजेडी ने पीएम के दौरे को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है. पार्टी का कहना है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने बिहार को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया है. लालू और तेजस्वी दोनों ने बिहार की बदहाल अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और अपराध को मुद्दा बनाते हुए जनता से एनडीए सरकार को घेरने की अपील की है. आरजेडी का यह हमला चुनाव से पहले मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.पीएम का बिहार दौरा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गयाजी और बेगूसराय के दौरे पर रहेंगे.

इस दौरान वे बोधगया में एक सभा को संबोधित करेंगे और लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे. पीएम का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है.चुनावी माहौल में बढ़ती सियासी सरगमी- बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पीएम मोदी के लगातार बिहार दौरे और विकास परियोजनाओं के ऐलान को एनडीए की ओर से अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. दूसरी ओर, आरजेडी इन दौरों को जुमलेबाजी करार देकर जनता के बीच सरकार की कथित नाकामियों को उजागर करने में जुटी है.

70 शराब दुकानों के लिए 477 लोगों ने किया आवेदन, 4 साल 7 महीने के लिए मिलेगी दुकान

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पलामु। झारखंड में 1 सितंबर से नयी उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री होगी। इससे पूर्व राज्यभर में आज 22 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से शराब दुकानों का आवंटन किया जायेगा। पलामू जिले में 1 सितंबर से लॉटरी के माध्यम से कुल 70 शराब दुकानें खोली जायेगी। लॉटरी के माध्यम से जिस व्यक्ति को भी दुकान मिलेगी। उसे चार साल सात महीने के लिए दुकान दिया जायेगा। अभी केवल सात महीने के लिए ही दिया जायेगा। प्रतिवर्ष दुकान का रिन्यूअल कराना होगा। रिन्यूअल के समय 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जिस व्यक्ति के नाम से दुकान मिलेगी, वह दुकान किसी अन्य को नहीं दे सकता है।

जिस व्यक्ति का नाम वही खोलेगा दुकान इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक संजीत कुमार देव ने बताया कि जिस व्यक्ति के नाम से दुकान है। यदि वे शराब दुकान नहीं चलाना चाहते हैं। तो वे अपने बेटा, बेटी, पत्नी या पति को दे सकते हैं। लेकिन इसे सब लेट नहीं किया जा सकता है। बताया कि जिस व्यक्ति को लॉटरी के माध्यम से दुकान मिलेगा। उसे 12 प्रतिशत का रिटेल मार्जिन दिया जायेगा।

दुकान खोलने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

सरकार ने पलामू जिले से सात महीने में 112 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है। दुकान सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 तक ही खोल सकते हैं। दुकान प्रत्येक वर्ष होली, मोहर्रम, रामनवमी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, और गांधी जयंती पर बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी दुकान पर महिला शराब बेचने का काम नहीं कर सकती है। जबकि दुकान का लाइसेंस महिला के नाम से हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभी पूरे जिले में करीब 43 शराब की दुकान खुली हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से भी आये आवेदन पलामू में 28 ग्रुप में बांटे गये 70 शराब की दुकानों के लिए कुल 477 आवेदन पड़े हैं। झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश के लोगों ने भी शराब दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रुप 21 के पांकी व चक दुकान के लिए 69 आवेदन पड़े हैं जबकि शहर के जेलहाता से साहित्य समाज चौक के बीच पड़ने वाले दुकान के लिए 34 आवेदन आये हैं। मोहन सिनेमा हॉल के पास बस स्टैंड शराब दुकान के लिए 31, सरकारी बस स्टैंड के पास शराब दुकान के लिए 29, चियांकि हवाई अड्डा, सतबरवा व पोलपोल के लिए 14 आवेदन पड़े हैं।

कहां खुलेगी कितनी दुकानें ?

इसके अलावा ग्रुप 20 के पड़वा व उंटारी में शराब दुकान के लिए 28 आवेदन दिया गया हैं। एफसीआई से लेकर बैरिया चौक एक दुकान के लिए 25 आवेदन दिया आये हैं। वहीं ग्रुप 15 रेड़मा की दुकान के लिए तीन आवेदन पड़े हैं, जिसमें से सात देसी व 63 कंपोजिट दुकान खोले जायेंगे। मालूम हो पहले तीन तरह की दुकानें खोली जाती थी, जिसमें विदेशी, देसी व कंपोजिट दुकानें शामिल होती थी। इस बार 70 दुकानों को 28 समूहों में बांटा गया है। वापस मिलेगा पैसा उल्लेखनीय है 8 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच शराब दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन किये गये हैं। शराब दुकान की लॉटरी के लिए एक टिकट न्यूनतम 5 लाख व अधिकतम 25 लाख में खरीदा जायेगा। इनमें से जिन व्यक्तियों को लॉटरी के माध्यम से शराब दुकान नहीं मिल पायेगा। उन्हें आवेदन शुल्क व जीएसटी का पैसा काट कर वापस कर दिया जायेगा।

राज्य स्तरीय गतका प्रतियोगिता में संत मरियम स्कूल के 11 खिलाड़ियों का चयन

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

मेदिनीनगर (पलामू)। धनबाद के अमाघाटा क्रेडो वर्ल्ड स्कूल में 23 से 24 अगस्त तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय गतका प्रतियोगिता में संत मरियम स्कूल के 11 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। चयन पलामू जिला गतका संघ द्वारा किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में अंडर-11 टीम सिंगल सोती में आर्यन कुमार, कुशाग्र शुक्ला, रोहित कुमार पासवान, राजवीर पासवान, अंडर-11 इंडिविजुअल सिंगल सोती में अर्पित तिवारी, अंडर-11 इंडिविजुअल फरी सोती में अभिनव सिंह, अंडर-14 गर्ल्स टीम फरी सोती में रिया कुमारी, अंडर-14 ब्वॉयज इंडिविजुअल फरी सोती में पुष्कर कुमार, अंडर-14 ब्वॉयज टीम फरी सोती में अतुल सिंह, अंडर-17 गर्ल्स इंडिविजुअल सिंगल सोती में खुशबू कुमारी, अंडर-17 ब्वॉयज टीम फरी सोती में रोशन कुमार मांझी के नाम शामिल है। विद्यालय के खेल प्रशिक्षक सुमित वर्मन ने कहा कि उनके नेतृत्व में सभी खिलाड़ी शुक्रवार की रात धनबाद स्पेशल ट्रेन से धनबाद के लिए रवाना होंगे। इसके पूर्व विद्यालय के प्राचार्य आदर्श कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि यह हमारे विद्यालय के लिए गौरव का विषय है कि 11 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। उन्हें विश्वास है कि उनके स्कूल के खिलाड़ी अपने अनुशासन, लगन व खेल भावना से विद्यालय, जिला व पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता व टीम भावना विकसित करने का साधन है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों की सफलता की शुभकामनाएं दी ।

कैमरून में फंसे मजदूरों का बकाया भुगतान, 17 की शनिवार को वतन वापसी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

विष्णुगढ़। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 19 प्रवासी मजदूरों को आखिरकार बकाया वेतन का भुगतान हो गया है। इनमें से 17 मजदूरों की शनिवार को वतन वापसी तय हो गई है, जबकि शेष दो मजदूर 26 अगस्त को स्वदेश लौटेंगे। चार महीने से वेतन न मिलने के कारण मजदूरों को खाने-पीने में भारी परेशानी हो रही थी। हालात बिगड़ने पर मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई, जिसका वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार हरकत में आई। भारतीय दूतावास की मध्यस्थता से कंपनी और मजदूरों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद बकाया भुगतान और वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया। इस खबर से प्रवासी मजदूरों के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार, मीडिया और प्रवासी मजदूरों की मदद में जुटे समाजसेवी सिकंदर अली के प्रति आभार जताया है।

जानकारी के अनुसार, हजारीबाग और बोकारो जिले के कुल 19 मजदूर ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे। इनमें 11 मजदूरों को चार माह से और आठ मजदूरों को दो माह से वेतन नहीं मिला था।

शनिवार को लौटने वाले मजदूरों की सूची इस प्रकार हैः

हजारीबाग (विष्णुगढ़): आघनू सोरेन (भेलवारा), अशोक सोरेन (खरकी), चेतलाल सोरेन (खरकी), महेश मरांडी (खरकी), रामजी मरांडी (खरकी), लालचंद मुर्मू (खरकी), बुधन मुर्मू (नरकी), जिबलाल मांझी (चानो)। हजारीबाग (टाटीझरिया): छोटन बासके, राजेंद्र किस्कू। बोकारो (गोमिया): प्रेम टुडू (चिलगो), सिबोन टुडू (चिलगो), सोमर बेसरा (करी खुर्द), पुराण टुडू (करी खुर्द), रामजी हांसदा (बड़की सिधाबारा), विरवा हांसदा (बड़की सिधाबारा), महेंद्र हांसदा (बड़की सिधाबारा)।

कांग्रेस केंद्र सरकार के कुचक्र से निपटने को जन आवाज के पक्षधर संगठनों को करेगी एकजुट : गोपाल सिंह

केंद्र सरकार खोखला करने में लगी हुई है लोकतंत्र की आत्मा : कांग्रेस

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

मेदिनीनगर (पलामू)। भारतीय लोकतंत्र आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार लोकतंत्र की आत्मा को खोखला करने में लगी हुई है। उक्त बातें पलामू जिला कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि सत्ता के मद में चूर केंद्र सरकार ने न केवल संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया बल्कि चुनाव आयोग जैसे तटस्थ माने जाने वाले संस्थान को भी अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ इसके जीते- जागते उदाहरण हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। जब उनकी भूमिका समाप्त हो गई तो उन्हें पूरी तरह हाशिये पर धकेल दिया। देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद उपेक्षा का शिकार हो गया। ऐसे में आम नागरिकों के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनहीनता को समझना कठिन नहीं है। कहा कि इससे भी बड़ा खतरा हाल ही में संसद में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक से पैदा हुआ है। प्रस्तावित संशोधन में यह प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिन तक जेल में बंद रहता है तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। पहली नज़र में यह प्रावधान प्रशासनिक शुचिता का प्रतीक लग सकता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं अधिक खतरनाक है। वर्तमान स्थिति में जब ईडी, सीबीआई व अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां सत्ता की कठपुतली बन चुकी हैं, तब यह प्रस्तावित संशोधन विपक्षी नेताओं को कुचलने का सबसे आसान हथियार बन सकता है। भाजपा सरकार किसी भी विपक्षी नेता पर झूठे आरोप लगाकर व मनगढ़ंत मामलों में फंसाकर जेल भेज सकती है। 30 दिन पूरे होने पर उनका पद छीन सकती है। कहा कि फिलहाल यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास विचारार्थ भेजा गया है। लेकिन इस प्रस्ताव ने लोकतंत्र प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है। भाजपा के पिछले रिकार्ड को देखते हुए यह आशंका स्वाभाविक है कि इसे विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए एक तानाशाही हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर बोलते हुए गोपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस कुचक्र से निपटने के लिए जन आवाज़ के पक्षधर संगठनों को एकजुट करेगी। संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मुद्दे को व्यापक जनांदोलन से जोड़ा जाएगा। इससे जनता यह समझ सके कि यह सिर्फ नेताओं का सवाल नहीं बल्कि उनके मताधिकार व लोकतांत्रिक अस्तित्व का सवाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्यायपालिका, प्रेस व सिविल सोसाइटी पर भरोसा रखती है।इनके सहयोग से इस तानाशाही प्रयास को विफल करेगी। यदि विपक्ष बिखर गया तो सत्ता की चाल सफल हो जाएगी। लेकिन यदि विपक्ष व जनता एकजुट हो गए तो कोई भी तानाशाह लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकता। गोपाल सिंह ने कहा कि जनता के सामने भाजपा बार-बार झूठे वायदों का पुलिंदा खोलती रही है। लेकिन असलियत यह है कि वह लोकतंत्र की बाध्यता को समाप्त कर एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहती है, जहां चुनाव केवल दिखावा हो व सत्ता पर पूंजीपतियों का कब्ज़ा मजबूत हो। चुनाव आयोग की कमजोरी ने इस साजिश को और आसान बना दिया है। जब संस्थाएं सवाल नहीं पूछेंगी तो सत्ता के मनमाने फैसले कौन रोकेगा? कहा कि आज जनता और समाज का एक वर्ग जो भाजपा का प्रवक्ता बनकर उसकी प्रवृत्तियों को वैधता देने में जुटा है। वह यह भूल रहा है कि यह पूंजीवादी व दमनकारी सरकार अंततः उन्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। लोकतंत्र की जड़ें खोदने वाले ये कदम न केवल विपक्ष बल्कि आम जनता की आवाज़ को भी कुचल देंगे।

समाहरणालय में जनता दरबार आयोजित

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

नवादा। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रखंडों से आए आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों का ऑन स्पॉट समाधान किया। जनता दरबार में विद्युत, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड तथा राजस्व संबंधी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। कुल 56 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से कई का वहीं पर निपटारा कर दिया गया एवं शेष मामलों को संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई हेतु भेजा गया। जनता दरबार में अंचल-सिरदला, मौजा-धिरौंध के ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमणमुक्त कराने, ग्राम-बेरमी के मिन्टु प्रसाद द्वारा जमाबंदी नहीं होने, साकिन-लक्ष्मी विगहा की सुशीला देवी द्वारा घर निर्माण कार्य रोकने, ग्राम-करनपुर के नरेश प्रसाद द्वारा जान से मारने की धमकी देने, ग्राम-पचरूखी के जयप्रकाश प्रसाद द्वारा चहारदिवारी निर्माण रोकने, साकिन-पकरीबरावां के सुरेन्द्र यादव द्वारा जमाबंदी से संबंधित समस्या, राजस्व कर्मचारी अकबरपुर श्रीकांत प्रसाद द्वारा भविष्य निधि जीवन बीमा का बिल अग्रसारित नहीं करने तथा पोस्टमार्टम रोड, शिवनगर निवासी आरती कुमारी द्वारा न्याय मित्र के पद पर नियोजन हेतु काउन्सेलिंग से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से कुछ मामलों का निपटारा जिला पदाधिकारी द्वारा मौके पर ही संबंधित पदाधिकारी से बात कर किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता और तत्परता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार आम लोगों की सरकार तक सीधी पहुंच है। इसका उद्देश्य जन समस्याओं का समाधान त्वरित और पारदर्शी तरीके से करना है। जनता दरबार में अपर समाहर्त्ता अनिल कुमार तिवारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शम्भू शरण पांडेय, गोपनीय शाखा प्रभारी राजीव कुमार,

राजकीय उच्च विद्यालय गाल्होवार में 108 छात्र-छात्राओं को साइकिल का वितरण

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

विष्णुगढ़। प्रखंड अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय गाल्होवार में शुक्रवार को कक्षा 8 के छात्र-छात्राओं के बीच मुखिया मंजू देवी ने 108 साइकिल का वितरण किया। साइकिल पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और वे बेहद उत्साहित नजर आए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखिया मंजू देवी ने कहा कि झारखंड सरकार गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रही है। साइकिल योजना उसी कड़ी का हिस्सा है, जिससे छात्र-छात्राएं समय पर विद्यालय पहुंच सकें और पढ़ाई में बाधा न हो। मुखिया प्रतिनिधि छोटी शर्मा ने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक जो पढ़ाते हैं, उसे मन लगाकर अपनाएं और मेहनत से पढ़-लिखकर गांव व राज्य का नाम रोशन करें। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इस मौके पर किशोर कुमार महतो, प्रदीप राम, माणिकचंद दास, साबिर अंसारी, रोहित महतो, संतोष कुमार रजक, धानेश्वर महतो, द्वारिका प्रसाद महतो, दशरथ महतो, रेनु देवी, महादेव प्रजापति, प्रभु राम, वकिल प्रजापति समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और अभिभावक उपस्थित थे।

पूर्व रेलवे

निविदा सूचना सं.: एडीएल-एमईसीएच-डीएमडब्ल्यूपी-2-25-26, दिनांक: 20.08.2025। वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता (डीजल), पूर्व रेलवे, आसनसोल, स्टेशन रोड, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: **केस संख्या: एडीएल - एमईसीएच - डीएमडब्ल्यूपी - 2 - 25-26। कार्य का नाम:** खुली निविदा के आधार पर डीजल शेड, अंडाल में संग्रह एवं डिस्पेंसिंग प्रणाली सहित 1200 एलपीएच की क्षमता वाले डबल आरओ आधारित डीएम वाटर प्लांट की आपूर्ति, स्थापना एवं शुरुआत। **निविदा मूल्य:** ₹ 27,17,250। **बयाना राशि:** ₹ 54,400। **निविदा दस्तावेज की कीमत:** शून्य। **कार्य पूरा करने की अवधि:** 0 4 महीना। **ठेके की अवधि :** 12 महीना। **निविदा बंद होने तथा खुलने की तारीख एवं समय:** 10.09.2025 को सुबह 10.30 बजे। सम्पूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

(ASN-161/2025-26)

निविदा सूचना वेबसाइट: **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in** पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

दक्षिण पूर्व रेलवे-निविदा

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (जी)/आद्रा, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा यहां नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार विद्युतीय कार्यों के निष्पादन के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं: **क्रमांक एवं निविदा सूचना सं., कार्य का विवरण, निविदा मूल्य: (1) ईलेक्ट-जी-एडीए-2025-33, दिनांक 21.08.2025;** दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में तीन (03) अदद लेवल क्रॉसिंग गेटों (बीआर-47, जेसी-24, एएम-38) की इंटरलॉकिंग के लिए विद्युतीय कार्य; रु. 13,62,195; **(2) ईलेक्ट-जी-एडीए-2025-34, दिनांक 21.08.2025;** आद्रा मंडल में 11 केवी रेटिंग की ओवरहेड पावर लाइन क्रॉसिंग का पावर लाइन क्रॉसिंग (पीएलसी) के भूमिगत केबल में सुधार एवं ऊर्जितकरण के लिए विद्युतीय कार्य (फेज-डी); रु. 1,15,41,686; **(3) ईलेक्ट-जी-एडीए-2025-35, दिनांक 21.08.2025;** आद्रा मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 15 स्टेशनों के विकास के लिए साइनेज कार्य हेतु विद्युतीय कार्य (फेज-1); रु. 1,98,15,000; **ई-निविदाओं के बंद होने की तारीख एवं समय** प्रत्येक के लिए 15.09.2025 को दोपहर 12.00 बजे है तथा प्रत्येक के लिए **निविदाएं** दिनांक 15.09.2025 को दोपहर 12.30 बजे के उपरांत **खोली** जाएंगी। उपरोक्त ई-निविदाओं का विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखे जा सकते हैं। **(PR-553)**

ई-निविदा सूचना सं. ई-डीआरएम-इंजी-आद्रा-68-74-25, दिनांक 21.08.2025; भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से मंडल रेल प्रबंधक (इंजी.)/आद्रा, दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **क्रमांक एवं निविदा सं.; कार्यों का विवरण; निविदा मूल्य** निम्नलिखित हैं: **(1) ई-डीआरएम-इंजी-आद्रा-68-25, दिनांक 21.08.2025,** आद्रा मंडल में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/पी.वे/पश्चिम/आद्रा के अधिकार क्षेत्र के अधीन यार्ड के सुधार कार्य के संबंध में कंक्रीट ड्रेन के निर्माण के साथ विविध कार्य; रु. 2,51,21,862.84; **(2) ई-डीआरएम-इंजी-आद्रा-69-25, दिनांक 21.08.2025,** आद्रा मंडल में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/पी.वे/पुरुलिया एवं वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (पी.वे)/चांडिल के अधिकार क्षेत्र के अधीन यार्ड के सुधार कार्य के संबंध में कंक्रीट ड्रेन के निर्माण के साथ विविध कार्य; रु. 5,78,71,070.76; **(3) ई-डीआरएम-इंजी-आद्रा-70-25, दिनांक 21.08.2025,** आद्रा मंडल में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/पी.वे/दामोदर के अधिकार क्षेत्र के अधीन यार्ड के सुधार कार्य के संबंध में कंक्रीट ड्रेन के निर्माण के साथ विविध कार्य; रु. 2,56,23,628.51; **(4) ई-डीआरएम-इंजी-आद्रा-71-25, दिनांक 21.08.2025,** आद्रा मंडल के तहत आद्रा में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/पी.वे/जयचंडीपहाड़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन यार्ड के सुधार कार्य के संबंध में कंक्रीट ड्रेन के निर्माण के साथ विविध कार्य; रु. 2,95,03,997.24; **(5) ई-डीआरएम-इंजी-आद्रा-72-25, दिनांक 21.08.2025,** आद्रा मंडल में (1) वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/(पी.वे)/दामोदर, (2) आद्रा में वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/पी.वे/जयचंडीपहाड़ तथा (3) वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/(पी.वे)/पश्चिम/आद्रा के अधिकार क्षेत्र के अधीन यार्ड का सुधार; रु. 4,28,22,366.12; **(6) ई-डीआरएम-इंजी-आद्रा-73-25, दिनांक 21.08.2025,** आद्रा मंडल में बॉक्स पुशिंग पद्धति द्वारा आसनसोल-चांडिल अनुभाग के बीच किमी. 324/19-21 पर मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेट सं. जेसी-18 के उन्मूलन के लिए आरयूबी/सबवे का निर्माण; रु. 7,27,00,369.68; **(7) ई-डीआरएम-इंजी-आद्रा-74-25, दिनांक 21.08.2025,** आद्रा मंडल में बागिला-कुसतौर (बीजीए-केएसयू) अनुभाग के बीच किमी. 310/8-10 पर मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेट सं. जेसी-11 के उन्मूलन के लिए आरयूबी/सबवे का निर्माण; रु. 7,15,43,772.11; **ई-निविदाओं के बंद होने की तारीख एवं समय:** दिनांक 22.09.2025 को अपराह्न 3.00 बजे है। ऊपरोक्त ई-निविदाओं के विस्तृत विवरण के लिए कृपया वेबसाइट **www.ireps.gov.in** देख सकते हैं। **(PR-555)**

हर घर नल का जल योजना ग्रामीणों के लिए वरदान : श्रवण कुमार

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बिहारशरीफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी सात निश्चय-1 के तहत हर घर नल का जल योजना अब नालंदा जिले के और अधिक गांवों तक पहुंच रही है। शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं सांसद कौशलेंद्र कुमार ने वेन प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कुल 6 करोड़ 76 लाख 76 हजार रुपये की लागत से स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास किया। योजना के तहत वेन प्रखंड के ग्राम पंचायत एकसारा, नोहसा, आंट, अकौना, अरावां, वेन, मैजरा, खैरा और बारा पंचायतों के 36 वार्डों में छूटे हुए टोलों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही सिलाव–मैजरा रोड से सीकरी तक 31 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य तथा दया बिगहा पक्की सड़क से मैजरा मध्य विद्यालय तक सड़क निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार ने गांवों को स्मार्ट बनाने का कार्य किया है। वर्ष 2005 से पहले केवल 6% परिवारों को नल का जल उपलब्ध था, जबकि आज 97% परिवार शुद्ध पेयजल का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में बिहार ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार 50% तक अनुदान देकर स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रही है। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि आज बिहार के विकास कार्यों की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और लोग गर्व से कहते हैं कि वे बिहारी हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष अरविन्द पटेल, जदयू जिला प्रवक्ता डॉ. धनंजय कुमार देव, लक्ष्मण प्रसाद, नवीन सिंह, टुनटुन सिंह, जितेंद्र सिंह, तुलसी मांझी, कृष्ण कुशवाहा, पप्पू मुखिया, राजा मुखिया, उत्तम पटेल, संतोष मुखिया, शंभू पासवान, रामेश्वर केवट, भागेरण पाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पूर्व रेलवे

ई-निविदा सूचना सं.: ओ/एसी/टी/85-86/ 25-26 (ओपन), दिनांक: 20.08.2025। मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल, स्टेशन रोड, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा (खुली) आमंत्रित की जाती है: **क्र. सं.: 1। केस संख्या: ओ-एसी-टी-85-25-26। कार्य का नाम:** वरिष्ठ डीईएन/1/आसनसोल के अधीन एईएन/मुख्यालय/आसनसोल के अधिकार क्षेत्र में डीआरएम कार्यालय में परिचालन, कार्मिक, सुरक्षा, अभियांत्रिकी अनुभाग के पूर्ण नवीनीकरण और टीपीसी को स्थान देने के लिए मंडल नियंत्रण के विस्तार हेतु खुली निविदा। **निविदा मूल्य:** ₹ 2,20,06,025.64। **बयाना राशि:** ₹ 2,60,000। **कार्य पूरा करने की अवधि:** 09 महीना। **क्र.सं.: 2। केस संख्या: ओ-एसी-टी-86-25-26। कार्य का नाम:** सीतारामपुर (छोड़कर) से प्रधानखूंटा (छोड़कर) खंड में सीतारामपुर से प्रधानखूंटा तक सभी क्षेत्रीय कार्यों हेतु खुली निविदा। इसमें 01.07.2025 से 30.06.2026 तक की अवधि के लिए आसनसोल मंडल के ज़ोन संख्या 6 में एसएसई/वर्क्स/सीतारामपुर के अधीन सभी सेवा भवन और कॉलोनियाँ आदि सहित छोटी सड़कें, लकड़ी के काम, पाइप बिछाने और स्वच्छता स्थापना कार्य शामिल हैं। **निविदा मूल्य:** ₹ 75,00,000। **बयाना राशि:** ₹ 1,50,000। **कार्य पूरा होने की अवधि:** 10 महीने। **बंद होने की तारीख और समय:** 15.09.2025, को दोपहर 12:00 बजे (क्रम संख्या 1 और 2 प्रत्येक के लिए)। सम्पूर्ण विवरण रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है।

(ASN-160/2025-26)

निविदा सूचना वेबसाइट: **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in** पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

आजादी के 79 वर्ष बाद भी गोगो गांव में नहीं बनी सड़क

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

औरंगाबाद। नबीनगर विधानसभा क्षेत्र के टेंगों पंचायत के उतरी व दक्षिणी गोगो गांव में आजादी के 79 वर्ष बाद भी ग्रामीणों को सड़क नहीं बन सकी है। ग्रामीण कच्ची सड़क से होकर गुजरने को विवश हैं। गांव में पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासकर बारिश के दिनों में परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे खाट पर टांग कर डेढ़ से दो किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को होती है। कच्ची सड़क होने के कारण स्कूल बस गांव तक नहीं आती है। जिसके कारण बच्चों को प्रतिदिन डेढ़ से दो किलोमीटर की पैदल चलकर विद्यालय जाना पड़ता है। कई बार सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से मांग ले लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। थक हारकर ग्रामीणों ने इस बार के विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने सड़क की समस्या को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि उनके इलाके में गोगो से बदल बिगहा पांच किमी, कोईरीडीह मेन रोड से नोनिया बिगहा दो किमी और राटा बिगहा से लक्ष्मीपुर दो किमी जाने वाली सड़क आजादी के बाद से आजतक नहीं बनी है। तीनों सड़के आज भी कच्ची है, जिससे 10 से 12 हजार की आबादी प्रभावित है। जब वर्षा होती है तो सड़कें तालाब में तब्दिल हो जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय विधायक विजय कुमार सिह उर्फ डब्ल्यू सिह की उदासीनता के कारण तीनों सड़कों का अबतक पक्कीकरण नहीं हो पा रहा है। जबकि चुनाव से पहले और विधायक बनने के बाद भी सड़क बनवाने का आश्वासन दिया था। सड़क नहीं बनने पर ही चुनाव बहिष्कार का कड़ा फैसला लिया है। बताया कि अब जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा तब तक हम वोट देने बूथ पर नहीं जाएंगे। चाहे इसके लिए हमें कितना भी चुनाव क्यों न इंतजार करना पड़े। यह फैसला तभी टलेगा जब चुनाव से पहले गांव में सड़क का निर्माण किया जाएगा। नहीं तो चुनाव बहिष्कार करेंगे।

New page 4_page 12 29.05.2025.qxd 22-08-2025 21:35 Page 1

रिश्वत लेते बीसीएम चढ़ा निगरानी के हत्थे

आशा चयन में 40 हजार रुपये की की थी मांग

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बिहारशरीफ। इस्लामपुर प्रखंड में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर (बीसीएम) आशुतोष कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ दबोच लिया।

निगरानी के डीएसपी श्यामबाबू प्रसाद ने बताया कि इस्लामपुर वार्ड संख्या 20 की रशीदा परवीन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आशा कार्यकर्ताओं की बहाली प्रक्रिया के दौरान बीसीएम ने उनसे चयन सुनिश्चित करने के लिए 40 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत की जांच के बाद आरोप सही पाए गए।

इसके बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते ही आरोपी अधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर आशुतोष कुमार को पटना स्थित मुख्यालय भेज दिया। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और स्थानीय स्तर पर भी इस प्रकरण की चर्चा जोर पकड़ रही है। बता दें कि आशुतोष कुमार थरथरी थाना क्षेत्र के राजा बाद गांव के रहने वाले हैं, पहले एकंगरसराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पदस्थापित रहे हैं। इस छापेमारी टीम में डीएसपी श्याम बाबू, के अलावे डीएसपी नागेंद्र कुमार, निरीक्षक योगेंद्र कुमार , सहायक अवर निरीक्षक रविशंकर, मणिकांत एवं राकेश कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां

पटना। पुलिस ने आज राशन डीलर पर जमकर लाठियां भांजी। यह घटना डाकबंगला चौराहा की है, जब आज राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिसमें कई लोग घायल हो गये। आज हजारों की संख्या में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले राशन डीलर विक्रेता सड़कों पर आकर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें स्थायी किया जाए। इस दौरान पुलिस ने पहले भीड़ को तीतर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब भीड़ उग्र हो गई, तब पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज कर दिया। राशन डीलरों ने बिहार सरकार से अपील करते हुए कहा कि हमारी मांगों को सरकार पूरा करे। सरकार ने हमें बार-बार सिर्फ आश्वासन ही दिया है, लेकिन हमारी मांगों के संबंध में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों की मांग है कि जन वितरण प्रणाली से जुड़े सभी राशन डीलरों को नियमित किया जाए एवं सभी को वेतनमान दिया जाए, जिससे हम सब का पालन पोषण भरपूर हो सके।

सिंहवाड़ा बीडीओ के विरूद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

दरभंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण आवास सहायक से रुपये मांगने के मामले में सिंहवाड़ा बीडीओ को प्रमंडलीय आयुक्त से राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में बीडीओ की मुश्किलें बढ़ गई है। लोक शिकायत निवारण कोषांग, आयुक्त कार्यालय ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता अनिल कुमार के आदेश पर ही मुहर लगा दी है। ऐसे में लोक प्राधिकार डीडीसी को विधिनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

ऐसी स्थिति में बीडीओ पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। हालांकि, तीस दिनों के अंदर कार्रवाई से बचने के लिए बीडीओ अपने विभाग के प्रधान सचिव के यहां अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन वहां भी राहत मिलने की उम्मीद काफी कम है।

बता दें कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने लोक प्राधिकार उपविकास आयुक्त को बीडीओ अमरेंद्र पंडित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रपत्र "क" भरते हुए जिला पदाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया था। साथ ही तत्काल प्रभाव से बीडीओ को पद से भी हटाने की अनुशंसा की थी।

पूरे मामले की विवेचना उपरांत आदेश की प्रति सभी संबंधितों विभागों सहित जिला पदाधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग, पटना को अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया था।

मामला पीएम आवास योजना का

कहा था कि लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन और परिवादी के आवेदन के साथ उपलब्ध कराए गए डिजिटल साक्ष्य ऑडियो क्लिप का अवलोकन से पीएम आवास योजना के लाभुकों को योजना का लाभ देने हेतु बीडीओ अमरेन्द्र पंडित द्वारा आवास सहायकों से राशि मांगने की पुष्टि होती है।

बता दें कि बनौली गांव निवासी रामबाबू कुशवाहा ने पीएम आवास योजना में फैले भ्रष्टाचार के ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच कर दोषी बीडीओ के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर परिवाद दायर किया था। इसमें आवास सहायक सैयद करार हुसैन और ग्रामीण कुशवाहा के बीच हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।

आवास सहायक इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि बीडीओ ने आवास सहायकों को अपने कार्यालय चेंबर में काफी दबाव देकर डंट-फटकार व बेइज्जत कर कह रहे हैं। कहते हैं जितने भी पीएम आवास सहायक योजना के लाभार्थियों हैं उससे तुम लोगों को खुलेआम प्रत्येक घर तीन-तीन हजार रुपये वसूल कर देना होगा । इस आलोक में 60 से 90 हजार नकदी रुपये वसूल कर देने की बात भी कही है।

गयाजी में भाजपा के मंच पर दिखे राजद विधायक

बिहार में सियासी हलचल हुई तेज

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। पीएम मोदी की गया में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के मंच पर दिखे राजद के दो विधायक। जिससे कयास लगाया जा रहा है कि ये दोनों एनडीए का दामन थाम सकते है। पर अभी तक ऑफिसियल सूचना नहीं मिली है। ये दोनों विधायक नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर हैं, जो पीएम मोदी की गया में आयोजित सभा में भाजपा के मंच पर मौजूद थे।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर आए। यहां पीएम मोदी ने गयाजी जिले के बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को करीब 13 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे।

कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि गया में पीएम मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर दिखे दो राजद विधायकों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ₹चुनाव नजदीक आ रहे हैं और लोकतंत्र में हर किसी को कहीं भी जाने की आजादी है... भाजपा के कई नेता भी हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उसी पार्टी से रिटायर होता है जिससे उसने अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत की थी।

इधर दूसरी ओर बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। गयाजी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर राजद के दो विधायकों के दिखने से राजनीतिक गलियारों में चचाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है।

मेंस हॉकी हीरो एशिया कप-2025 की ट्रॉफी गौरव यात्रा पहुंची औरंगाबाद

डीएम श्रीकांत शास्त्री ने किया गर्मजोशी से ट्राफी का स्वागत

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

औरंगाबाद। मेंस हॉकी हीरो एशिया कप-2025 की ट्रॉफी गौरव यात्रा का औरंगाबाद आगमन हुआ। समाहरणालय परिसर में डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया। ट्रॉफी के आगमन पर समाहरणालय परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। कार्यक्रम के दौरान ट्रॉफी के साथ आए विशिष्ट दल तथा जिले के खिलाड़ियों ने हाकी स्टिक से बाल पास कर खेल भावना और टीम वर्क का परिचय दिया।

जिले के अनेक खेल प्रेमियों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों ने भी इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर अपनी सहभागिता दर्ज की। बताया गया कि खेल विभाग बिहार सरकार एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के संयुक्त तत्वावधान में मेंस हॉकी हीरो एशिया कप-2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राज्य खेल अकादमी राजगीर (नालंदा) में किया जा रहा है। इस आयोजन में एशिया की प्रमुख टीमें भाग लेंगी।

खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने एवं युवाओं को खेल की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी 38 जिलों में ट्रॉफी गौरव यात्रा आयोजित की जा रही है। औरंगाबाद जिले में ट्रॉफी आगमन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए खिलाड़ी, छात्र-छात्राएं एवं खेल संघों के प्रतिनिधियों ने ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाकर इस गौरवपूर्ण अवसर को यादगार बनाया।

अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, जिला खेल पदाधिकारी कुमार पप्पू राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रत्ना प्रियदर्शनी सहित जिले के अनेक अधिकारी, कर्मचारी, खेल संघों के पदाधिकारी एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। डीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और यह गर्व की बात है कि बिहार मेंस हाकी हीरो एशिया कप 2025 जैसे अंतरर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी गौरव यात्रा से जिले के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा वे खेल के प्रति अधिक प्रेरित होंगे और औरंगाबाद के खिलाड़ी भी भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।

फौजी की मां के साथ मारपीट, पुलिस नहीं सुन रही शिकायत

बेटा कर रहा सरहद की रक्षा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के पताही इलाके में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों से घायल हुए लोग इलाज के लिए माडल अस्पताल पहुंचे।

गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती उमलावती देवी ने बताया कि उनका बेटा आर्मी में है और जम्मू कश्मीर में तैनात है। महिला ने कहा कि पड़ोसियों से कई दिनों से उनका भूमि विवाद का मामला चल रहा था।

पड़ोसी को कहा कि जब बेटा आएगा, तब जमीन की मापी करवाई जाएगी। लेकिन पड़ोसी बात मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच विवाद बढ़ा और पड़ोसी शंकर साह और उसके परिवार से कई लोग लाठी-डंडे के साथ पहुंच गए और हमला कर दिया। बीच बचाव में उमलावती के रिश्तेदार आए तो उन्हें भी मारपीट किया गया। इसमें कई लोगों को गंभीर चोट लगी। उमलावती के स्वजन ने बताया कि पड़ोसी अक्सर जमीन को लेकर विवाद करते है।

सदर थाना में अब तक दो बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी।

पीड़ित पक्ष से आवेदन मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर, घटना के दौरान लाठी-डंडे से लैस लोगों का मारपीट करते एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

मामले में सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने कहा कि पताही में पहले से चले आ रहे भूमि विवाद में झड़प हुई है। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी।

जमीन रजिस्ट्री में करोड़ों के घालमेल का पर्दाफाश

25 लोगों के खिलाफ कुर्की-जब्ती

वर्ष 2016 से चल रहा है गोरखधंधा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

आरा। भोजपुर जिले में विगत नौ वर्षों से जमीन रजिस्ट्री में प्रकृति छिपाकर राजस्व चोरी करने का धंधा चल रहा था। इस मामले का खुलासा होने के बाद निबंधन विभाग इन सभी से राशि की वसूली करने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है।

इसे लेकर भोजपुर जिले में लगभग दो करोड़ राजस्व चोरी करने वाले 25 लोगों के खिलाफ कुर्की जब्ती और नोटिस देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में यह मामला वर्ष 2016 से अब तक का जुड़ा हुआ है। राजस्व चोरी करने के मामले में महिलाएं सबसे आगे हैं। जिन छह लोगों की संपत्ति की कुर्की होनी है उनमें पांच महिलाएं शामिल हैं।

इस मामले में जमीन रजिस्ट्री करने वालों के द्वारा किसी जमीन की प्रकृति व्यवसायिक या विकासशील है, लेकिन उसे कृषि भूमि बता रजिस्ट्री कराई गई है। रजिस्ट्री करा लेने के बाद इस मामले की शिकायत मिलने पर सहायक महानिदेशक पटना प्रमंडल और भोजपुर डीएम के द्वारा सुनवाई की गई। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है।

इस मामले में भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 47 ए के अंतर्गत यह कार्रवाई हो रही है। इसके बाद मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क के तय किए जाने के बाद जमा नहीं करने पर लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अंतर्गत नीलामवाद की कार्रवाई शुरू की गई है।

चंद्रावती देवी पति कमलेश सिंह स्टेशन रोड बिहिया 1.65 लाख, अधिकारो देवी पति जानकी राय बचरी पीरो 10.85 लाख, मोनाको देवी पति स्वर्गीय केशव सिंह पकड़ी आरा दो कागजात 12 लाख, प्रेमशिला देवी पति मनोज कुमार सुमन अनाइठ नवादा 2.24 लाख, गायत्री देवी पति अवध बिहारी सिंह मोर्या जगदीशपुर 13.89 लाख।

इन सभी के खिलाफ अचल संपत्ति कुर्की जब्ती करने का आदेश निकला है। ये सबसे पुराने बकायेदार हैं।

भोजपुर जिले में निबंधन विभाग का राजस्व चोरी करने वाले सबसे बड़े बकायदारों में एसएमभीडी रियल स्टेट के निदेशक अंकित कुमार राय, पिता प्रदीप कुमार राय, वैष्णवी रेजिडेंसी मां काली मार्ग, बाईपास रोड, बक्सर पर 47.47 लाख, भारत यादव, बाबू बाजार आरा पर 18.21 लाख, अजय कुमार, पिता शंभू शरण मोर्चा जगदीशपुर 15 लाख, मीरा देवी/पति लाल बाबू प्रसाद जगदीशपुर डीएम रोड 5.55 लाख, राहुल कुमार पिता देवेंद्र कुमार सोहरी चरपोखरी पर 7.61 लाख, शहजाद खान पिता मोकिम खान पैठान टोली जगदीशपुर पर 5.36 लाख, रघुवंश नारायण सिंह पिता हरबंस नारायण सिंह सेदहा तरारी पर 6.65 लाख रुपये का बकाया है। जिन्हें अभी नोटिस दिया गया है।

23 अगस्त को राहुल गांधी कटिहार में

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

कटिहार। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा शनिवार को कटिहार जिले में पहुंचेगी। इस मौके पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले को बैनर, पोस्टर, झंडे और होर्डिंग्स से सजा दिया है। विधायक डॉ. शकील अहमद खान ने कदवा के कुम्हरी चौक पर विशेष कार्यक्रम की तैयारी की है, जहां राहुल गांधी थोड़ी देर रुककर जनता को संबोधित करेंगे।

इस यात्रा को ताकत देने के लिए मंच पर राहुल गांधी के साथ-साथ तेजस्वी यादव, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, मुकेश सहनी और पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में कटिहार विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान ने कहा कि कटिहार में ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी।

पटना-हाजीपुर वाटर मेट्रो की प्रक्रिया में आई तेजी

जल्द चालू होने की विधायक ने जतायी उम्मीद

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पटना। कोच्चि वाटर मेट्रो की तर्ज पर हाजीपुर-सोनपुर से पटना के बीच सुगम यातायात सेवा आमजन को उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) के निदेशक के पत्र के आलोक नगर विकास एवं आवास विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. अभिलाषा शर्मा ने बुधवार 20 अगस्त को पत्र जारी कर पटना के नगर आयुक्त के अलावा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद हाजीपुर एवं नगर पंचायत सोनपुर से रिपोर्ट मांगी है। विभाग के पत्र के आलोक में यहां कार्रवाई तेज कर दी गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पटना में शहरी जल प्रणाली के विकास व सुदृढ़ीकरण हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) की ओर से कोच्चि वाटर मेट्रो की तर्ज पर हाजीपुर से बिदुपुर, सोनपुर होते हुए पटना के बीच परिवहन प्रणाली का विकास किया जाना है।

इसके लिए प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन में चेचर घाट, कोनहारा घाट, पानापुर घाट वैशाली एवं कालीघाट सोनपुर में घाटों से परिचालित होने वाले नावों की संख्या, आवागमन करने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या तथा घाटों के संपर्क पथ की स्थिति के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है। इस संबंध में बुधवार को हाजीपुर के भाजपा विधायक अवधेश सिंह ने कहा कि कोच्चि वाटर मेट्रो की तर्ज पर हाजीपुर से पटना के बीच सुगम यातायात सेवा उपलब्ध होने से इलाके लोगों को पटना आने-जाने में काफी सुविधा होगी। साथ ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह काफी सस्ती परिवहन सेवा है।

वहीं इस यातायात सेवा में लोगों को जाम की समस्या से नहीं जूझना होगा। प्रतिदिन पटना से हाजीपुर आने-जाने वाले लोगों के लिए यह सरकार की ओर प्रदान की जाने वाली सबसे सुगम यातायात सेवा होगी।

विधायक अवधेश ने कहा कि इस परियोजना पर काफी तेजी से काम चल रहा है और एक-दो माह के अंदर ही इस सेवा के चालू हो जाने की उम्मीद है।

निबंधन पदाधिकारी आर्थिक अपराध इकाई के घेरे में

करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

भागलपुर। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने शुक्रवार को भागलपुर के अवर निबंधन पदाधिकारी विनय सौरभ के तीन ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। विनय सौरभ रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के सेनुआर गांव के मूल निवासी हैं और फिलहाल भागलपुर में जिला अवर निबंधक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

ईओयू की अलग-अलग टीमों ने सासाराम, भागलपुर और पूर्णिया में एक साथ दबिश दी। हालांकि, सेनुआर स्थित पैतृक आवास से टीम को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन भागलपुर के खंजरपुर बरारी स्थित अभिनव एनक्लेव और पूर्णिया के पनोरमा सिटी स्थित आवास से भारी मात्रा में दस्तावेज और सामान जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान टीम ने बड़ी मात्रा में नकदी, आभूषण, जमीन से जुड़े दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, बैंक डिपॉजिट और बांड बरामद किए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विनय सौरभ ने अपने पद पर रहते हुए अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। ईओयू को अन्य राज्यों में भी उनकी अचल संपत्तियों के सुराग मिले हैं। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई विनय सौरभ की सभी चल-अचल संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

गुस्साये लोगों ने किया सड़क जाम

मुंगेर। प्रीतम हत्याकांड के नौ दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को गनैली के पास तीन माइल पर आक्रोशित परिजनों ने बांस-बल्ला लगाकर सड़क जाम कर दी। जाम के कारण देवघर जा रहे कांवड़ियों और निजी वाहनों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

जाम कर रहे परिजनों ने हाथों में तख्ती लेकर पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। तख्ती पर लिखा था कि पुलिस पर से विश्वास उठ चुका है। परिजनों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उन्हें फांसी की सजा दिलाने का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

मृतक प्रीतम के पिता मनोज मंडल ने बताया कि बुधवार को मुख्य आरोपी मो. अफरोज को संग्रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया।

लोगों को कश्मीर की तर्ज पर अब कैमूर में मिलेगा शिकारे का मजा, ट्रायल शुरू

24 अगस्त को होगा उद्घाटन

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

कैमूर। वो लोग जो शिकारे पर सफर के लिए कश्मीर जाने की इच्छा दिल में दबाए बैठे हैं। उनकी ये दिली हसरत बिहार में पूरी होने वाली है। वो भी उनके मन लायक मौसम में ! यहां न तो बहुत ठंड होगी और न ही दूर से आने की थकान। कैमूर जिले के दुर्गावती जलाशय का करमचट डैम अब पर्यटन के नक्शे पर उभरने वाला है। यहां पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस हाउसबोट सेवा शुरू होने वाली है। यह हाउसबोट डैम में पहुंच भी चुके हैं। इसका उद्घाटन 24 अगस्त को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार करेंगे। लेकिन लंबे ट्रायल के बाद इसे आम लोगों के लिए खोला जाएगा।

इस करमचट डैम पर हाउसबोट पर यात्रा करने वालों को प्राकृतिक की जबरदस्त सुंदरता का अनुभव होने वाला है। हाउसबोट के सफर के रास्ते में उन्हें 10-12 झरने दिखेंगे। इसके अलावा डैम के चारों ओर फैली हरियाली इस रोमांचित करने वाले सफर को और खास बनाएगी। लहरों पर यह सफर सुकून का नया ठिकाना होगा। यह जगह पर्यटकों के लिए सूकून के डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगी। जहां लोग पानी की लहरों पर रोमांचित करने वाली सुकून भरी शाम बिताने पहुंचेंगे।

अभी इस हाउसबोट का ट्रायल चल रहा है, जिसे अच्छी तरह से टेस्ट करने और सभी सुविधाओं से लैस कर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस हाउसबोट में होटल वाली तमाम सुविधा होंगी। बोट में एसी कमरे, आधुनिक बाथरूम और किचन से लैस होंगे, जिस पर 8 से 10 लोगों के लिए आरामदायक सुविधा होगी। जहां लोग पानी की लहरों पर हरी भरी प्राकृतिक वादियों के बीच खाने पीने के साथ सुकून का वक्त बिता पाएंगे।

सीएफ इकोटूरिज्म सत्यजीत कुमार ने बताया कि 24 अगस्त को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। फिलहाल ये हाउसबोट ट्रायल के चरण में हैं। हाउसबोट पर सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने और सुरक्षा मानकों के टेस्टिंग के पूरे होने के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह रोमांचित नजारा 10-12 झरनों से घिरा होगा।

हाउसबोट सेवा से इस इलाके में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कैमूर ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों से समृद्ध है। नई सुविधा से यहां आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, परिवहन और हस्तशिल्प जैसे व्यवसायों को भी रफ्तार मिलेगी। करमचट डैम अब केवल पिकनिक और प्राकृतिक नजारों का ही ठिकाना नहीं रहेगा, बल्कि यह बिहार के पर्यटन मानचित्र पर एक रोमांचक और लग्जरी अनुभव के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।

CMYK

मोदी ने वेलस्पन इंटरप्राइजेज के औंटा-सिमरिया गंगा पुल का किया उद्घाटन

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। वेलस्पन वर्ल्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर शाखा वेलस्पन एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बिहार में ऐतिहासिक औंटा-सिमरिया गंगा पुल प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें गंगा नदी पर भारत का सबसे चौड़ा एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टे ब्रिज शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह अवसर बिहार की बेहतर संपर्क व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ है। 1.8 किलोमीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा यह गंगा पुल,जो कुल 8.15 किलोमीटर लंबी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, सीधे तौर पर पटना जिले के औंटा को बेगूसराय जिले के सिमरिया से जोड़ता है, जिससे यात्रा समय में एक घंटे से अधिक की बचत होगी। 57 मीटर से 115 मीटर तक के खंडों और 70 मीटर तक फैले कैंटिलीवर आर्म्स के साथ निर्मित यह पुल भारी वाहनों के ट्रांसपोर्टेशन को आसानी से संभालने में योग्य है। यह पुल पास के 70 वर्ष पुराने राजेंद्र पुल के लिए एक आधुनिक और मजबूत विकल्प के रूप में काम करेगा। इस उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वेलस्पन वर्ल्ड के चेयरमैन बी के गोयंका ने कहा, यह प्रोजेक्ट हमारे विजन का सही प्रतीक है, जिसके तहत हम ऐसे राष्ट्रीय महत्व के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं जो क्षेत्रों में बदलाव लाए और लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। हमें गर्व है कि हमने ऐसा पुल बनाया है, जो न केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है बल्कि बिहार और उससे आगे के लिए जीवनरेखा भी है। वेलस्पन एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक संदीप गर्ग ने कहा, औंटा-सिमरिया गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी वेलस्पन एंटरप्राइजेज की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और एक्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को दिखाती है। हम बिहार सरकार, एनएचएआई और सभी पार्टनर्स के सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल है जिनकी मदत से ये प्रोजेक्ट हो सका।

बी.डी. कॉलेज में व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की मनाई गई जयंती

छात्र-छात्राओं ने प्रस्तुत किए पत्र, वक्ताओं ने कहा- परसाई आज भी बेहद प्रासंगिक

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। हिन्दी साहित्य में व्यंग्य को एक सशक्त विधा के रूप में स्थापित करने वाले प्रख्यात साहित्यकार हरिशंकर परसाई की जयंती शुक्रवार को बी.डी. कॉलेज के हिन्दी विभाग में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरूआत कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत ने परसाई जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। उन्होंने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर पैनी नजर रखने वाला साहित्यकार बताते हुए कहा कि परसाई जी की रचनाएं केवल व्यंग्य नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं। विभागाध्यक्ष डॉ. लाड़ली कुमारी ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने व्यंग्य को साहित्य की मुख्यधारा में स्थापित किया। वहीं डॉ. अमित कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उद्धृत किए जाने वाले साहित्यकारों में परसाई अग्रगण्य हैं। उनके चुटीले व्यंग्य और बेबाक अंदाज ने उन्हें व्यापक पाठक वर्ग दिया है। हिन्दी विभाग के छात्र-छात्राओं ने भी परसाई की रचनाधर्मिता पर अपने पत्र प्रस्तुत किए और उनके योगदान को आज की परिस्थितियों में प्रासंगिक बताया। कार्यक्रम में संकाय सदस्यों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी रही।

विधानसभा चुनाव में सख्त निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय ने बनाये पांच सेल

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव में सशक्त मॉनीटरिंग करने के लिए पांच अलग-अलग सेल का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इन सेल का गठित आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अंतर्गत किया गया है। इसकी जानकारी डीआईजी (आर्थिक अपराध) मानवजीत सिंह ढिल्लो ने संवाददाताओं से बात करने के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जिन पांच विशेष सेल का गठन किया गया है उसमें मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) तस्करी की रोकथाम, साइबर अपराध, सोशल मीडिया पर निगरानी, फर्जी मुद्रा (फेक करेंसी) और कैश के अवैध लेनदेन पर निगरानी रखने से संबंधित सेल शामिल हैं। चुनाव के दौरान इन तमाम अवैध गतिविधियों पर समुचित नजर रखने का दायित्व इन विशिष्ट सेल को सौंपा गया है।

सामूहिक वैश्य देव पूजन की तैयारी पूरी : डॉ अजय प्रकाश

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। सनातन संस्कृति की अद्भुत छटा पटना के इस पावन धरती पर जलान सेफ, बेलवरगंज, पटना सिटी के प्रांगण में भारत में पहली बार 24 अगस्त रविवार को आयोजित होने वाले सामूहिक वैश्य देव पूजन महाकुंभ की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस ऐतिहासिक एवं विहंगम पूजन महाकुंभ में 350 आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुजन की सेवा में उपस्थित रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए भोग का प्रसाद के साथ भंडारा प्रसाद भी उपलब्ध रहेगी, जल की आपूर्ति आदि की व्यवस्था पूरी कर ली गई है । 25 देव मूर्तियों का अद्भुत सुनहले रोशनी में दर्शन कर श्रद्धालु जन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बिहार का महान पर्व छठ, भारत की संस्कृति के अनुरूप कई प्रकार की झांकियां का प्रदर्शन प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाएगा, दूधिया रोशनी में नहाई हुई परिसर में भजन का प्रस्तुतीकरण भी होगा। समाज में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। वैश्य देव गाथा का वर्णन के साथ फोटो वितरित किया जाएगा। भगवान श्री राम, श्री गणेश, माता लक्ष्मी, सूर्य देव, शीतला माता, विश्वकर्मा भगवान सहित पच्चीस देव का पूजन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रकाण्ड विद्वान द्वारा पूजन किया जाएगा। इस महाकुंभ में हजारों महिलाएं पीला एवं लाल परिधान में दिखेंगे तथा पुरुष भारतीय परिधान कुर्ता पजामा एवं धोती कुर्ता में नजर आएंगे। उक्त बातों की जानकारी सामूहिक वैश्य देव पूजन महाकुंभ के संयोजक डॉ अजय प्रकाश ने प्रेस वार्ता में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ सर्वदेव प्रसाद गुप्त, वीणा प्रकाश, विकास कुमार मौड़ीवाल, दिलीप गुप्ता, अरूण कुमार मालाकार, लल्लू शर्मा, रघुनाथ सोनेवाल दैवज्ञ, पप्पू साह आदि उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से बिहार में 2 करोड़ से अधिक परिवार हो रहे हैं लाभान्वित

इ-पीओएस मशीन से राशन वितरण में आई पारदर्शिता और दक्षता

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बिहार सरकार खाद्य सुरक्षा की दिशा में निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वर्तमान में राज्य में 2.06 करोड़ परिवार आज राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह खाद्यान्न का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बिहार में प्रतिमाह औसतन 4,25,019 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी के 1.83 करोड़ परिवारों को प्रत्येक लाभुक को 05 किलोग्राम खाद्यान्न (1 किलोग्राम गेहूं एवं 4 किलोग्राम चावल) निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 22.81 लाख परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (7 किलोग्राम गेहूं एवं 28 किलोग्राम चावल) निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु सभी जनवितरण केंद्रों पर ई-पीओएस मशीन (ई-पॉइंट ऑफ सेल) की व्यवस्था की गई है जिसमें हर लाभुक का नाम, पहचान, वितरित खाद्यान्न की मात्रा, वितरण की तारीख एवं समय का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। प्रत्येक लेन-देन की जानकारी रियल टाइम में नियंत्रण कक्ष तक पहुंचती है जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश समाप्त हो गई है।

बंधन बैंक ने 10वीं वर्षगांठ पर लांच किया 'लिगेसी अकाउंट'

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। भारत के सबसे तेजी से बढ़ते यूनिवर्सल बैंकों में से एक, बंधन बैंक ने अपने प्रीमियम उत्पाद, लिगेसी बचत खाता को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह खाता उन धनी ग्राहकों के लिए बनाया गया है जो एक बेहतर और विशेष बैंकिंग अनुभव चाहते हैं। यह लॉन्च बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर पर हुआ है क्योंकि बैंक ने परिचालन और बैंकिंग उत्कृष्टता के 10 साल पूरे कर लिए हैं। लिगेसी बचत खाते के साथ वर्ल्ड एलीट मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड मिलता है जो घरेलू (साथी के प्रवेश सहित) और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज, ताज एपिक्योर मेंबरशिप, मुफ्त मूवी और इवेंट टिकट और चुनिंदा क्लबों में गोल्फ सेशन की सुविधा देता है। लिगेसी बचत खाता वाले ग्राहकों को और भी कई विशेष सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर, लॉकर किराए पर आजीवन छूट और यात्रा, चिकित्सा, शिक्षा, विरासत और संपत्ति नियोजन जैसी जरूरतों के लिए विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं। यह उत्पाद जीवनशैली, यात्रा और वित्तीय लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त ग्राहक असीमित मुफ्त लेनदेन का लाभ उठा सकते हैं जिसमें नकद जमा, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस शामिल हैं। लिगेसी ग्राहकों को बेहतर बीमा कवरेज भी दिया जाता है जिसमें 1 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 20 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख तक का खरीद सुरक्षा शामिल है। इस अवसर पर बोलते हुए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ पार्था प्रतिम सेनगुप्ता ने कहा जैसे ही बंधन बैंक 10 साल पूरे कर रहा है, यह वास्तव में गर्व और कृतज्ञता का क्षण है। लिगेसी बचत खाते के लॉन्च के साथ हम समावेशी और सतत विकास के अपने उद्देश्य से जुड़े रहते हुए नवीन समाधान और विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने की एक नई प्रतिबद्धता के साथ अगले दशक में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपनी आगे की यात्रा में अपने ग्राहकों के अटूट विश्वास, अपने कर्मचारियों के समर्पण और हमारे सभी हितधारकों के समर्थन की आशा करते हैं। बंधन बैंक एक मजबूत अखिल भारतीय संस्थान के रूप में उभरा है जो 30 जून, 2025 तक 1.55 लाख करोड़ की जमा राशि और 1.34 लाख करोड़ के अग्रिम के साथ 31 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है।

अब भगोड़े अपराधी भी नहीं बच पाएंगे, दूसरे राज्यों से दबोचे गए 64 कुख्यात

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बिहार में अपराध करके दूसरे राज्य भागने वाले अपराधी भी अब नहीं बच रहे हैं। इस वर्ष जनवरी से 20 अगस्त तक ऐसे 64 अपराधियों को एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुख्यात और इनामी अपराधी भी शामिल हैं। यह जानकारी एडीजी (अभियान) सह एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा 14 की संख्या में अपराधियों को दिल्ली से दबोचा गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से 9, उत्तर प्रदेश से 7, गुजरात से 7, झारखंड से 6, हरियाणा से 5, महाराष्ट्र से 4, मध्य प्रदेश से 4, हिमाचल प्रदेश से 2, पंजाब से 2 के अलावा राजस्थान, गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर औ? मणिपुर से 1-1 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी कृष्णन ने कहा कि राज्य में नक्सली हिंसा में काफी कमी आने के बाद से एसटीएफ को संगठित अपराध और इससे जुड़े अपराधियों का समूल नाश करने में लगा दिया गया है। राज्य के अंदर पनप रहे सभी तरह के संगठित अपराधों को खत्म करने में इसकी भूमिका बेहद अहम है और इसकी उल्लेखनीय उपलब्धि की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। पिछले वर्ष अपराधियों से मुठभेड़ के 8 मामले सामने आए थे। इस वर्ष इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। पिछले वर्ष 2024 में की गई कार्रवाई में 752 अपराधियों को दबोचा गया था, लेकिन इस वर्ष अब तक 857 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तरह 2024 में 44 और 2025 में अब तक 101 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले वर्ष जहां 3681 कारतूस बरामद किए गए थे। वहीं, इस वर्ष अब तक 12 हजार 176 कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष अपराधियों से 19 रेगुलर हथियार तथा इस वर्ष 32 रेगुलर हथियार बरामद किए गए हैं। एडीजी ने कहा कि एसटीएफ की विशेष टीम के स्तर पर निरंतर इनामी और कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस क्रम में 18 अगस्त को 2 लाख का इनामी अपराधी बुटन चौधरी को महाराष्ट्र के उदवंतनगर थाना से गिरफ्तार किया गया है। 5 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पहाड़गंज से अंतरराज्यीय सोना लुटेरा सुबोध सिंह, 2 लाख का इनामी विकास कुमार उर्फ जॉन राइट को गिरफ्तार किया गया था। 28 मार्च को औरंगाबाद जिला का एक लाख का इनामी नक्सली राजेश यादव को महाराष्ट्र के महार्ड (रायगढ़) क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 8 फरवरी को सीवान और गोपालगंज का 50 हजार का कुख्यात इनामी अपराधी मनीष को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। राज्य के बाहर ऑपरेशन के दौरान एसटीएफ के कई जवान भी शहीद हुए हैं। इसमें दारोगा मुकुंद मुरारी, जेसी विकास कुमार, जेसी जीवधारी कुमार, दारोगा संतोष कुमार, मिथिलेश पासवान शामिल हैं। ये लोग गुजरात के सूरत में सरकारी वाहन से एक अपराधी को गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन एनएच पर वाहन दुर्घटना के दौरान इनकी मौत हो गई थी। एडीजी ने बताया कि अवैध हथियार या गोलियों की खरीद-बिक्री के मामले की तफ्तीश एनआईए के स्तर से भी की जा रही है। इससे अपराधियों को मिलने वाली गोलियों की सप्लाइ चेन को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। हाल में हाजीपुर समेत 7 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की गई थी।

साइंस सिटी में बच्चों के लिए हो थ्री डी विज्ञान फिल्म दिखाने की व्यवस्था : कुमार रवि

सचिव कुमार रवि ने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी का किया निरीक्षण

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने शुक्रवार को निर्माणाधीन डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुमार रवि ने आदेश दिया कि यहां आने वाले बच्चों के लिए ऑडिटोरियम में थ्री डी विज्ञान फिल्म दिखाने की व्यवस्था हो। साइंस सिटी में प्रदर्श अधिष्ठापन कार्य, एट्रियम एरिया, ऑडिटोरियम, डोरमेटरी, अस्थाई प्रदर्श गैलरी सहित परीसर में चल रहे जरूरी कार्यों का बारीकी से जायजा लिया गया।

भवन निर्माण विभाग की ओर से मोईन-उल-हक स्टेडियम के पास 20.5 एकड़ में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण के लिए प्रथम गैलरी (बी ए साइंटिस्ट्स गैलरी) में प्रदर्श अधिष्ठापन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है जबकि द्वितीय गैलरी (बेसिक साइंस गैलरी) में प्रदर्श लगाने का कार्य तेजी से प्रगति पर है। साइंस सिटी में कुल पांच गैलरियों का निर्माण किया जाना है यथा- बी ए साइंटिस्ट्स गैलरी, बेसिक साइंस गैलरी, सस्टेनेबल प्लैनेट गैलरी, स्पेस एंड एस्ट्रोनोमी गैलरी तथा बॉडी एंड माइंड गैलरी। पांचों गैलरियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 7725 वर्गमीटर है और इनमें 26 थीम पर आधारित 269 विज्ञान प्रदर्श स्थापित किया जाना है। सचिव ने स्थल निरीक्षण के दौरान बचे हुए कार्यों को तेजी से पूर्ण करने का निदेश दिया। अभियंताओं एवं एजेंसी को निदेशित किया गया है कि प्रदर्श अधिष्ठापन के साथ ही फिनशिंग कार्य को भी तेजी से पूर्ण करें ताकि साइंस सिटी का उद्घाटन संभावित समय पर हो सके। एट्रियम में अब्दुल कलाम की मूर्ति, डिजिटल पैनल और म्यूरल लगाए गए हैं। बच्चों एवं आगंतुकों के लिए सेल्फी पॉइंट विकसित की गई है। इस परिसर में 500 सीटों की क्षमता वाला आधुनिक ऑडिटोरियम तथा 150 छात्रों एवं 3 शिक्षकों के लिए डोरमेटरी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी, अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

राजस्व महा-अभियान : तबादले व अनुशासनात्मक कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक

पुराने हल्के में ही रहेंगे राजस्व कर्मचारी ताकि न प्रभावित हो जमाबंदी वितरण

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वावधान में चल रहे राजस्व महा-अभियान के दौरान रैयतों को समय पर सेवा देने और शिविरों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब अभियान की अवधि में राजस्व कर्मचारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि हाल में जिन राजस्व कर्मियों का एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानांतरण हुआ है, उन्हें अभी उनके पुराने हल्के में ही प्रतिनियुक्त किया जाए। कारण यह है कि नए हल्के से परिचित न होने के कारण जमाबंदी वितरण और शिविर में आवेदन लेने में कठिनाई और देरी हो रही है। पत्र में कहा गया है कि महा-अभियान की सफलता में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए 20 सितम्बर तक कोई भी निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि परिस्थिति अत्यंत अपरिहार्य न हो। विभाग का मानना है कि इस दौरान की गई कार्रवाई से नकारात्मक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और अभियान की गति को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें। राजस्व महा-अभियान 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितम्बर तक चलेगा। इस दौरान जमाबंदी में गलती सुधार, बंटवारा नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और ऑफलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करने हेतु पंचायत में लगे शिविर में आवेदन लिया जाएगा। अपने पंचायत में जमाबंदी की प्रति के वितरण और शिविर की जानकारी अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी।

एमआईटी मुजफ्फरपुर में इंडक्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने प्रत्यय अमृत

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मुख्य सचिव नामित एवं विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत उपस्थित हुए एवं उनके साथ जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि का परिचय कराते हुए बताया कि श्री प्रत्यय अमृत 1991 बैच के कैडर अधिकारी हैं। उन्होंने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि बतौर कटिहार डीएम उनके द्वारा लागू किया गया। मॉडल तथा सारण जिले में सोनपुर मेले में स्थापित अनुशासन अद्वितीय उदाहरण हैं। उन्होंने स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग में किए गए कार्यों की भी प्रशंसा की। मुख्य अतिथि श्री प्रत्यय अमृत ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि उन्हें युवाओं से बातचीत करना बेहद पसंद है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मुजफ्फरपुर से उनका गहरा संबंध है क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रभात तारा स्कूल से प्राप्त की और पहली बार एमआईटी आने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उन्होंने होस्टल निर्माण के लिए कैबिनेट से स्वीकृति भी प्राप्त की है। उन्होंने छात्रों से कहा–यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक समय है। यदि आपका मन किसी और दिशा में है तो निडर होकर उसकी ओर बढ़ें। अपने कार्य में संतोष और खुशी मिलना सबसे जरूरी है। क्रॉसरोड पर खड़े मत रहिए, हर प्लेटफॉर्म से अवसर की शुरूआत की जा सकती है। हमेशा इस बात पर गर्व कीजिए कि आप बिहार से हैं। ग्रेड से अधिक समझ महत्वपूर्ण है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अतिरिक्त गतिविधियों में भी भाग लें। बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है और इस बैच के लिए अपार अवसर उपलब्ध हैं। बिहार की युवा आबादी देश का भविष्य बनेगी। इसलिए समस्याओं का समाधान करने वाले और विश्लेषणात्मक सोच रखने वाले बनें तथा समाज को कुछ लौटाएं।

छात्र-छात्राओं के सवाल-अर्चना कुमारी क्या बी.टेक करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी संभव है? प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि अभी इंजीनियरिंग पढ़ाई पर ध्यान दें और तीसरे वर्ष के प्रश्न पत्र पढ़ना शुरू करें। शिवम भारती अभ्यर्थियों के लिए मुख्य गुण क्या होने चाहिए? उन्होंने कहा कि सफलता की कुंजी है– साथ ही अनुशासन, जुनून और सही दृष्टिकोण भी आवश्यक हैं। विशाल कुमार मैं अच्छा वक्ता कैसे बन सकता हूं। श्री अमृत ने हंसते हुए कहा कि वह इस सवाल को इतने बड़े मंच पर नहीं पूछ पाए होते।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के साथ द्वितीय त्रैमासिक वार्ता बैठक

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मध्य पूर्वी क्षेत्र, पटना की अध्यक्षता में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के सभागार में राज्य सरकार के विभागों के साथ द्वितीय त्रैमासिक वार्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य सरकार के अनेक विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वागत भाषण श्रीमती सोनम, वैज्ञानिक द्वारा किया गया। प्रस्तावना एवं कार्य सूची के बारे में क्षेत्रीय निदेशक द्वारा जानकारी प्रदान की गई। क्षेत्रीय निदेशक द्वारा बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मध्य पूर्वी क्षेत्र, पटना द्वारा बिहार एवं झारखंड के 900 से अधिक स्थानों पर भूजल मापन किया जाता है तथा इनसे संबंधित प्रतिवेदनों को राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ साझा भी किया जाता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा पाक्षिक रूप से भूजल गुणवत्ता एलर्ट भी जारी किया जाता है जिसे राज्य सरकार के संबंधित विभागों और संबंधित जिले के जिलाधिकारी से भी साझा किया जाता है।

दादीजी मंदिर में 1100 सुहागिनों ने दादीजी का मंगल पाठ कर अखण्ड सुहाग का मांगा आशीर्वाद

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। भादो बदी अमावस्या के अवसर पर दो दिवसीय महोत्सव के पहले दिन का कार्यक्रम बैंक रोड स्थित श्री दादीजी मंदिर में पूरे धूम-धाम से हुआ। मौके पर मुख्य संस्थापक अमर अग्रवाल ने बताया कि भादोबदी अमावस्या पर्व के पहले दिन आज लाल पीली चुनड़ी में सजी 1100 महिलाओं ने अखंड सुहाग के लिए सामूहिक रूप से मंगलपाठ कर श्री दादीजी से मांगा आशीर्वाद। श्री दादीजी सेवा समिति के तत्वावधान में यह महोत्सव शनिवार 23 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम में यजमान के रूप में ओम पोद्दार ने पूजा किया। इस अवसर पर पूरे श्री दादीजी मन्दिर परिसर को रंग बिरंगे देशी एवं विदेशी फूलों से काफी अच्छी तरह से सजाया गया जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा था तथा मन को मोह रहा था। पूरा माहौल राजस्थानी संस्कृति में रचा बसा नजर आ रहा था। मौके पर संस्था के अमर कुमार अग्रवाल ने बताया कि श्री दादीजी सेवा समिति के तत्वावधान में दो दिवसीय भादो बदी अमावस्या महोत्सव आज 22 अगस्त को प्रारम्भ हुआ जो कल तक पूरी आस्था के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार 23 अगस्त को सुबह छह बजे से दादीजी की विशेष मंगल आरती होगी तथा उसके बाद जात एवं पूजन होगा तथा छप्पन भोग लगाया जाएगा। इसी दिन संध्या में छह बजे से श्री दादीजी का विशेष भजन कीर्तन शक्तिधाम महिला मंडल एवं श्री श्याम मंडल द्वारा किया जायेगा। मंगल पाठ में भाग लेने में शकुन्तला अग्रवाल, रेखा मोदी, चंदा पोद्दार, सरिता बंका, रेणु अग्रवाल ,सरिता चौधरीं , सरिता बंका, रेणु बजाज आदि प्रमुख थीं। कार्यक्रम को सफल बनाने में शक्तिधाम के अमर अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल, सूर्य नारायण, निर्मल अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, पवन भगत, ओम पोद्दार, रमेश मोदी, रौशन सर्राफ, राजकुमार अग्रवाल, हनुमान गोयल, प्रदीप पंसारी, जे पी तोदी, रमेश अग्रवाल, अजय झुनझुनवाला, लक्ष्मण टेकरीवाल, रितेश तुलसियान, सुशील मित्तल, अनिल गुप्ता, मोहन सर्राफ, घनश्याम अग्रवाल, संतोष खीरवाल, राजकुमार खेमका सहित सैकड़ों लोग लगे हुए थे।

संपादकीय

अमेरिका की धमकी के बीच भारत और चीन राइट ट्रैक पर

चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में नई सहजता देखने को मिल रही है। भारत के नजरिये से यह बेहद अहम है कि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स के निर्यात पर लगाई बंदिशों में छूट देने पर हामी भर दी है। इन दोनों ही चीजों के लिए देश आयात पर निर्भर करता है। व्यापार के लिए सीमा के कुछ रास्ते खोलने का फैसला भी स्वागत योग्य है। वांग यी ऐसे वक्त में भारत आए, जब पूरी दुनिया में समीकरण तेजी से बन-बिगड़ रहे हैं। दोनों देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का असर पड़ा है और इसी वजह से उम्मीद भी थी कि इस दौरे से कुछ सकारात्मक हासिल हो सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स आज की टेक्नॉलजी की जरूरत हैं और इन पर लगभग पूरी तरह से चीन का कब्जा है। दुनिया की जरूरत की 90 प्रतिशत सप्लाई चीन से आती है। इसमें भी 60 प्रतिशत वह खुद प्रोड्यूस करता है। भारत भी अपनी जरूरत के लगभग 80 प्रतिशत रेयर अर्थ के लिए चीन पर निर्भर है। इस साल अप्रैल में पेइचिंग ने अमेरिकी नीतियों के विरोध में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर कड़ाई कर दी थी। इससे पूरी दुनिया में ऑटोमोटिव और डिफेंस सेक्टर पर असर पड़ा। भारत भी इससे प्रभावित हुआ। इसी तरह, फर्टिलाइजर्स के मामले में भी चीन पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। 2024-25 में देश ने कुल आयात का 19.17 प्रतिशत डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) चीन से मंगाया था। भारतीय किसान यूरिया के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी खाद का करते हैं।इस दौरे की अच्छी बात यह रही कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की चिंताओं को समझा। जिन मुद्दों को लेकर हाल में आशंकाएं उठी हैं, उन पर खुलकर चर्चा हुई। भारत ने आतंकवाद और ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बांध का मामला उठाया। वहीं, ताइवान पर चीन को आश्वस्त किया कि उसकी 'वन चाइना पॉलिसी' बदली नहीं है। बाकी दुनिया की तरह उसके भी ताइवान के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध हैं।भारत और चीन का रिश्ता ऐसा है, जिसके एकदम से गर्मजोशी से भर जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। दोनों के बीच सीमा विवाद का पुराना इतिहास है, बॉर्डर पर अब भी भारी संख्या में सैनिक आमने-सामने हैं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मसला भी है। अच्छी बात यह है कि दोनों देशों में संवाद जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी 31 तारीख को चीन जाना है। एससीओ समिट से इतर उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से भी होगी। तब एक बड़ा मौका होगा, जहां दोनों पड़ोसी आपसी सहयोग को नई दिशा दे सकते हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड ऑयल और प्रोटीन मार्केट है। यहां पर डालों और तेल की भारी खपत होती है। पॉल्ट्री और डेयरी सेक्टर के लिए प्रोटीन विट की भारी डिमांड रहती है। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने दरवाजे खोले और अमेरिकी सोयाबीन यहां टैक्स फ्री आएं। लेकिन भारत ने नो एंट्री फॉर यूएस सोयाबीन साफ कह दिया। दरअसल, भारत के किसानों का सबसे बड़ा फसल आधार सोयाबीन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई राज्यों में लाखों किसान सोयाबीन उगाते हैं। अगर अमेरिका का सस्ता सोयाबीन भारत आ गया तो भारतीय किसानों की फसल बिकना मुश्किल हो जाएगी। प्राइस क्रैश हो जाएगा और छोटे किसानों की हालात खराब हो जाएगी।

भारत ने रोक डाला अमेरिका का माल

पंगा लेना ट्रंप को पड़ रहा भारी

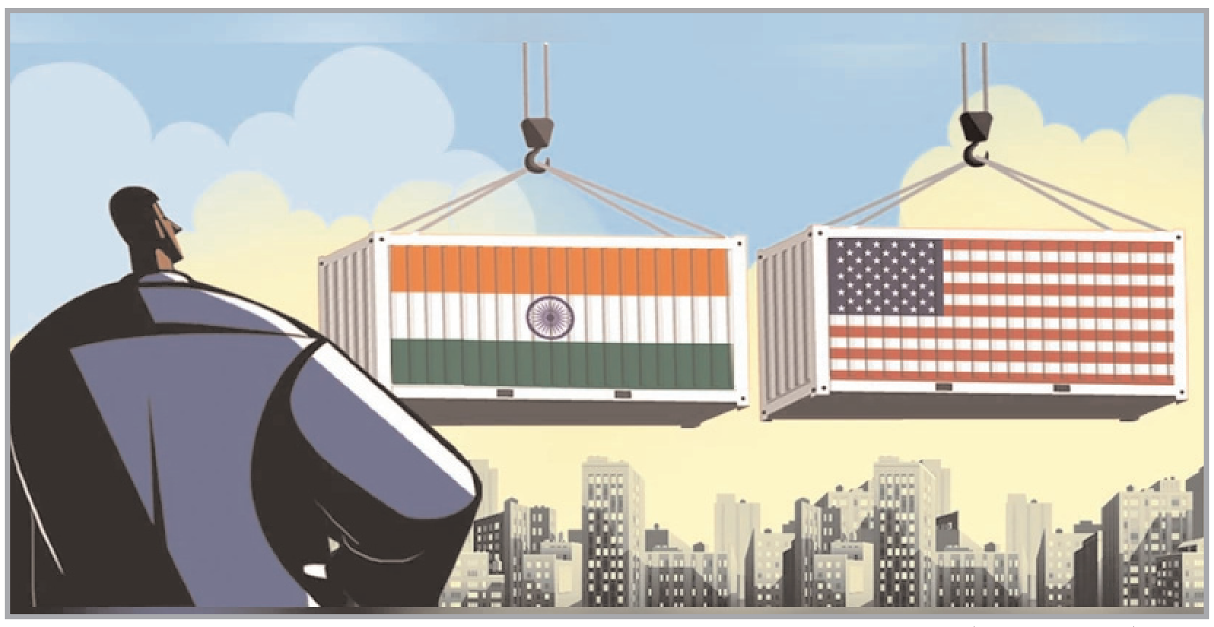

(अभिनय आकाश)

अमेरिका का सस्ता सोयाबीन भारत आ गया तो भारतीय किसानों की फसल बिकना मुश्किल हो जाएगी। प्राइस क्रैश हो जाएगा और छोटे किसानों की हालात खराब हो जाएगी। यही वजह है कि भारत ने चार रेड लाइन सोयाबीन, कॉर्न, एथनॉल, डेयरी के रूप में खीची थी।

कभी कभी कुछ फैसले जो किसान के खेत में लिए जाते हैं वो पूरी राजनीति को बदल कर रख देते हैं। आज बात सिर्फ एक बीज की नहीं बल्कि ये लड़ाई आत्मनिर्भरता बनाम विदेशी दबाव की बन गई है। जिसकी आशंका थी आखिरकार वही हुआ। अमेरिका और भारत की ट्रेड बातचीत फाइनल राउंड में थी। लेकिन अचानक रुक गई और वजह अमेरिकी सोयाबीन है। दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच अबतक पांच राउंड की ट्रेड मीटिंग हो चुकी थी। छठा राउंड अगस्त के आखिर में होना था। लेकिन अचानक खबर आई कि यूएस ट्रेड टॉक होल्ड पर चली गई है। अमेरिकी टीम जो 25 अगस्त को भारत आने वाली थी। उसने अपना दौरा रद्द कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अंतरिम ट्रेड डील फाइनल होने वाली थी। लेकिन अब वो अटक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य वजह भारत का अमेरिकी सोयाबीन को एंट्री न देना है। आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। लाखों अमेरिकी सोयाबीन उगाते हैं और वहां की बड़ी कंपनियों में इसे बेचते हैं। इन सबको नए नए बाजार चाहिए। ताकी उनका बिजनेस चलता रहे।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड ऑयल और प्रोटीन मार्केट है। यहां पर डालों और तेल की भारी खपत होती है। पॉल्ट्री और डेयरी सेक्टर के लिए प्रोटीन विट की भारी डिमांड रहती है। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने दरवाजे खोले और अमेरिकी सोयाबीन यहां टैक्स फ्री आएं। लेकिन भारत ने नो एंट्री फॉर यूएस सोयाबीन साफ कह दिया। दरअसल, भारत के किसानों का सबसे बड़ा फसल आधार सोयाबीन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई राज्यों में लाखों किसान सोयाबीन उगाते हैं। अगर अमेरिका का सस्ता सोयाबीन भारत आ गया तो भारतीय किसानों की फसल बिकना मुश्किल हो जाएगी। प्राइस क्रैश हो जाएगा और छोटे किसानों की हालात खराब हो जाएगी। यही वजह है कि भारत ने चार रेड लाइन सोयाबीन, कॉर्न, एथनॉल, डेयरी के रूप में खीची थी।

अमेरिकी सोयाबीन निर्यात परिषद (एसएसईसी) के सीईओ जिम सटर ने बीते दिनों इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक मुद्दे सुलझ सकते हैं, जिससे भारतीय पोल्ट्री उद्योग को 'स्थायी रूप से सत्यापित' अमेरिकी सोयाबीन फ़ीड उत्पादों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जबकि अमेरिका को चीन के साथ व्यापार तनाव से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई करने की अनुमति मिलेगी। सटर ने कहा कि वह भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) उत्पादों से जुड़ी नियामक चुनौतियों को गैर-शुल्क बाधा नहीं मानते, क्योंकि अमेरिकी सोया किसानों के पास भारत और अन्य जगहों पर आपूर्ति करने के लिए जीएम और गैर-जीएम, दोनों तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं। यह बात भारत में जीएम बीजों और उत्पादों से संबंधित नियामक प्रतिबंधों के बीच सामने आई है, जिन्हें संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने व्यापार में बाधा बताया है। आपको बता दें कि भारत ने शुरुआत में थोड़ा ललीचापन दिखाया था और नॉन जीम सोयाबीन व मक्का पर बात हो सकती है।लेकिन जब अमेरिका बार बार दबाव बनाने लगा तो भारत ने साफ कर दिया कि एग्रीकल्चर पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका अब टैरिफ को हथियार बनाकर भारत को झुकाना चाहता था। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जिसके बाद 6 अगस्त को ट्रंप ने एक और फैसला लिया था, जिसमें भारत पर 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया।

सरल आयकर व्यवस्था की ओर बढ़े कदम

(रामबाबू सोनी)

कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए संसद ने नया आयकर विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। इस विधेयक में प्रवर समिति की सभी 285 अनुशंसाओं को स्वीकार कर अनुपयुक्त हो चुके कई प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके कारण इसमें सेक्शन काफी कम हो चुके हैं। इसकी भाषा को यथासंभव सरल रखने के साथ ही पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। 'असेसमेंट ईयर' व 'प्रीवियस ईयर' जैसी जटिलताओं के समाप्त होने से यह समय और श्रम की भी बचत करेगा। अब टीडीएस प्राप्त करने के लिए पूरा आईटीआर दाखिल नहीं करना होगा। करदाताओं को यह सुविधा मिल सकेगी कि वे टैक्स कटने से पहले ही शून्य टीडीएस का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आय पर टैक्स नहीं लगेगा। छोटे करदाताओं द्वारा समय बीत जाने के बाद भी टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर उन्हें रिफंड मिल सकेगा। रिटर्न की प्रक्रिया में लगने वाले समय को काफी कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे रिफंड जल्दी मिल सके। कराधान विधि (संशोधन) विधेयक में स्वरोजगार वाले पेशेवरों के पेंशन हितों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। 'कंसोलिडेशन डिडक्शन' और अनुपालन को सरल करने के साथ ही अपराधों के लिए दंड भी कम किया गया है। साथ ही, आयकर अधिकारियों के अधिकारों को बढ़ाया गया है। अब आयकर अधिकारी अकाउंट बुक को जांचने के लिए 15 दिनों तक रख सकेंगे और सर्च के दौरान सभी डिजिटल उपकरणों, जैसे मोबाइल या लैपटॉप व ईमेल जैसे दस्तावेज अपने कब्जे में ले सकेंगे। कुल मिलाकर, यह आयकर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। (लेखक टिप्पणीकार है)।

साइबर युग में सम्मान ठुकराने का आनंद

(सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार)

जितने उदार दाता जी, उससे भी उदार पाता जी। पाता जी रोया कि दाता जी, इस बार तो असी को दे दो। और दाता जी का दिल पिघला। सोचने लगे, पता नहीं कब से यह दुष्ट दीन मलीन छीन हीन रो रहा है और हर सीजन में ऐसे ही रोता है कि दे दाता के नाम... तू अब मुझको दे दे। मेरी भी तू लिफ्ट करा दे। मेरे भी तू नाम लिखा दे। यह इनाम मेरे नाम करा दे। मुझको भी तू कवि बना दे। दे दाता के नाम तुझको अल्ला रखे। सो भैया जी ने दे दिया!

लेकिन जैसे ही दिया, वैसे ही पाता जी ने ठोकर मार दी कि नहीं लेता। ऐसे में, कोई दाता जी से क्यों पूछे कि महाराज! पहले दिया क्यों? क्या आपको साहित्य की 'वोक पॉलिटिक्स' की समझ नहीं थी कि इन दिनों जो आनंद ठुकराने में है, वह लेने में कहां? इन दिनों साहित्य का 'टेंपरेचर' इस कदर पलट गया है कि पहले जो सम्मानित होता था, वह गर्व महसूस करता था, बाकी उससे जलते थे, हाथ मलते थे कि हाय! दैव दुर्विपाक कि वह ले गया? हम रह गए, उसे क्यों मिला? हमें क्यों न मिला? वह भविष्य बन गया, हम अतीत हो गए।

अखबार उसके 'इंटरव्यू' लेता और वह राजकपूर बनकर कहता – मैं तो जी किसी काबिल नहीं था, जिन्होंने दिया जी, उनका आभार जी। उनकी उदारता को नमन जी। उनके बाल-बच्चों, पोते-पोतियों बीवियों को सौ-सौ बार कोर्निश जी कि उन्होंने मेरे जैसे अकिंचन को इस लायक समझा जी। वह फोटो सहित खबर बनाता। वह उद्धरणीय हो जाता। उसके भाव बढ़ जाते। वह साहित्य का अध्यक्ष, मुख्य अतिथि बनने लगता। माला, शॉल, दुशाला कमाने लगता। उसके ऐश हो जाते। वह 'अथॉरिटी' बन जाता।

लेखक जलते-कुढ़ते, उसे छोटा करने की तिकड़म करते रहते कि उसने किस-किस से पैरवी कराई, किसे-किसे दावत कराई, किस-किस के चरण चुंबन किए, तब जाकर मिला है। अरे हमसे क्या छिपा है? मगर सामने पड़ता, तो तुरत उसे नमन करते, क्योंकि अगली कमेटी में वही देने वाला बनना था।

इसे देख हम सब उसके 'फैन' बनने लगते और अपने को समझाते कि बेटा! सिर्फ लिखने से कुछ न होगा। अगर कुछ पाना है, तो कुछ खोना होगा। जैसे, अपनी शर्म को, और साहित्य के नए प्रभु की सेवा करनी होगी। इसलिए अभी से तैयारी कर। पहले यत्र-तत्र-सर्वत्र उनके भाव बढ़ा और कहीं नहीं, तो उनके मुहल्ले में ही मंत्री-संत्री बुलाकर उसका सम्मान कर और करा। सिर्फ लिखने से कुछ न होगा मूर्ख। जो होगा, भक्ति भाव से होगा।

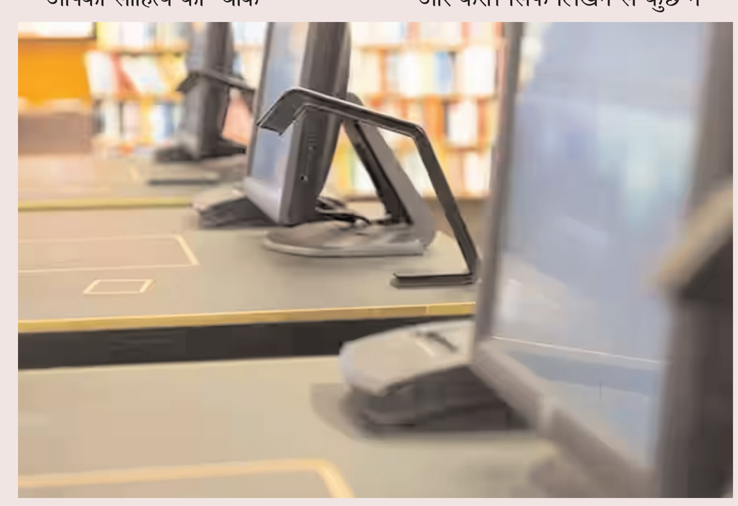

आह! वे भी क्या दिन थे, जब एक मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल जाता, तो हिंदी मात्र धन्य हो जाती या ऐसा ही कोई पंजी-दस्सी वाला पुरस्कार मिल जाता, तो लेखक का जन्म सफल हो जाता और बंदा अकादेमी से लेकर ज्ञानपीठ की ओर दौड़ लगाता दिखता, लेकिन वह साहित्य का सतयुग था, जबकि यह कलियुग है और कलियुग में भी साइबरी कलियुग है, जिसमें लेने के मुकाबले ठुकराने की 'वैल्यू' है।

आजकल जो मजा पहले हां कर, फिर ऐन टाइम पर ना करने में है, वह किसी और पुण्यकर्म में नहीं। इन दिनों 'मूल्यों' का ऐसा हेर-फेर है कि हिंदी लेखक सम्मान लेने पर शर्मिंदा होता है, जबकि ठुकराने पर गर्वित होता है, पर इस गर्व को भी खर्व (खराब) करने वाले अब मैदान में आ गए हैं। वे ठुकराने को भी शर्मिंदगी में बदल देते हैं। कारण यह कि इन दिनों इतने ठुकराने वाले हो गए हैं कि ठोकर वाला भी जोकर नजर आता है।

सिंधु की पुकार: संप्रभुता की वापसी और गौरव की बहाली'

अर्जुन राम मेघवाल

मानसून शब्द पूरे भारत में खुशी और गर्व का संचार करता है। यह नवाचार, नवीनीकरण और राष्ट्र के आर्थिक इंजन को तत्काल गति प्रदान करने का प्रतीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रचुर वर्षा के साथ मिलकर, इसकी नदियों को पुनर्जीवित करती है और देशभर में जल संसाधनों का विस्तार करती है। यह प्रगति के मौसम का प्रतीक है और स्वतंत्रता दिवस समारोहों के साथ मिला दिए जाने पर देशभक्ति की एक अनूठी भावना का संचार करता है। लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री के संबोधन ने एक बार फिर आकांक्षी नागरिकों के लिए एक ऐसा खाका पेश किया जो एक विकसित भारत के निर्माण के व्यापक लक्ष्य को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

संसद के इस विशेष मानसून सत्र की शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने इसे भारत का गौरवशाली सत्र बताया था। भारतीय सैनिकों का शौर्य, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारखानों पर निर्णायक प्रहार और सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का स्थगन—ये सब भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति के सबूत हैं और राष्ट्रीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। फिर भी, सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा के लिए सरकार के राजी होने के बावजूद, विपक्ष ने बाधा डालने का रास्ता चुना और व्यापक जनहित की कीमत पर विचार-विमर्श को राजनीतिक नौटंकी में सीमित कर दिया।

देश अरसे से स्वार्थ को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखने की कांग्रेस की पुरानी आदत का बोझ ढोता चला आ रहा है। विभाजन की दुखद विभीषिका से लेकर नेहरूवादी कूटनीति की महंगी पड़ने वाली विफलताओं तक, इतिहास गवाह है कि कैसे इन फैसलों ने भारत की मूल अवधारणा को ही कमजोर कर दिया। सिंधु जल संधि (1960) पर बारीकी से गौर करने पर, जनता और देश के विकास की कीमत पर तुष्टिकरण व अति-उदारता की एक ऐसी कहानी सामने आती है, जिसने राष्ट्रीय विकास की संभावनाओं को निरंतर बाधित किया। यह घोर विडंबनापूर्ण है कि भारत के विकास से जुड़े हितों का त्याग एक ऐसे राजनीतिक आकलन से प्रेरित थे जिसने अपने नागरिकों के कल्याण से ऊपर पाकिस्तान के हितों को तरजीह दी।

मूल रूप से, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी), सिंधु नदी प्रणाली के जल का आवंटन पाकिस्तान के पक्ष में (80–20) करती है। सिंधु नदी प्रणाली का उद्गम मुख्य रूप से भारत में है। इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी में बहने वाली सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी महत्वपूर्ण नदियों पर नियंत्रण छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिससे वैसे व्यापक जल संसाधन छिन गए जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के विशाल शुष्क एवं सूखाग्रस्त इलाकों का कायाकल्प कर सकते थे। यदि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती, तो सुव्यवस्थित जल अवसंरचना इस इलाके के संपूर्ण विकास की तस्वीर को बेहतर बना सकती थी।

हालांकि, इस महत्वपूर्ण त्याग से व्यापक कूटनीतिक लाभ मिलने की उम्मीदें भ्रामक साबित हुईं। इस संधि के प्रक्रियात्मक संचालन ने चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन इसे दो महीने बाद, नवंबर में, संसद के समक्ष रखा गया और वह भी मात्र दो घंटे की औपचारिक चर्चा के लिए। जैसे ही इस संधि से जुड़े तथ्य सामने आए, इसके विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के बाद प्रमुख समाचार पत्रों में छपी प्रतिकूल टिप्पणियां सुर्खियों में छायी रहीं। इतने महत्वपूर्ण समझौते के प्रति संसदीय स्तर पर बरते गए इस जल्दबाजी भरे व्यवहार ने लोकतांत्रिक निगरानी, पारदर्शिता और तत्कालीन नेतृत्व की दुर्भावनापूर्ण मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

इस सीमित संसदीय पड़ताल के बावजूद, सिंधु जल संधि को भारतीय संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय एक युवा सांसद थे, ने चेताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नेहरू का यह तर्क बुनियादी रूप से त्रुटिपूर्ण है कि पाकिस्तान की अनुचित मांगों के आगे झुकने से मित्रता और सद्भावना स्थापित होगी।

संसद में 30 नवंबर 1960 को हुई बहस से पता चलता है कि सभी दलों ने इस संधि की आलोचना की थी। अधिकांश सदस्यों ने सरकार की आलोचना की थी और उस पर पाकिस्तान के सामने झुकने तथा भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। राजस्थान से कांग्रेस सांसद श्री हरीश चंद्र माथुर, अशोक मेहता, ए.सी. गुहा, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद केटीके तंगमणि, सरदार इकबाल सिंह, बृजराज सिंह ने इस जल कूटनीति को लेकर स्पष्ट रूप से चिंताएं जाहिर की थी और इसके विफल होने से जुड़े नतीजों के बारे में अंदेशा जताया था। कुल मिलाकर, इस संधि को ÷एकतरफा, न कि लेन-देन पर आधारित÷ कहा जा सकता है।

इस संदर्भ में, यह विडंबना ही थी कि लोकसभा में अपने उत्तर के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने माननीय सांसदों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए और उन्हें कमतर भी आंका। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि संसदों द्वारा की गई आलोचना तथ्य और निहित विचारों से अनजान रहने पर आधारित है। उन्होंने (नेहरू) आगे कहा, ÷मुझे इस बात का दुख है कि इतने महत्वपूर्ण मामले को... एक ऐसा मामला जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य से भी जुड़ा है... इतने हल्के में और इतनी लापरवाही एवं संकीर्ण सोच के साथ लिया जा रहा है।÷

इस संधि ने भारत के हितों को कुंद कर दिया और यह पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक उपलब्धि साबित हुआ। अयूब खान ने एक सार्वजनिक प्रसारण में स्वीकार किया था कि इस संधि की वैधता और गुण-दोष पाकिस्तान के विरुद्ध थे, लेकिन इस मामले में नेहरू की कूटनीतिक विफलता ने पाकिस्तान को बढ़त दिला दी। 4 सितंबर 1960 को रावलपिंडी में अपने प्रसारण में, अयूब खान ने कहा था, ÷अब जो समाधान हमें मिला है, वह आदर्श नहीं है... लेकिन यह सबसे अच्छा समाधान है जो हमें इन परिस्थितियों में मिल सकता था, इनमें से कई बिंदु, चाहे उनके गुण-दोष और वैधता कुछ भी हों, हमारे खिलाफ हैं।÷ ये खुलासे आज भी राष्ट्रीय हित को गौण रखने के पीछे के मकसद पर सवाल खड़े करते हैं।

जैसा कि निरंजन डी. गुलाटी ने अपनी किताब ÷इंडस वाटर ट्रीटी– एन एक्सरसाइज इन इंटरनेशनल मीडिएशन÷ में लिखा है, 28 फरवरी 1961 को खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने इस निराशा को स्वीकार करते हुए कहा था– ÷मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे।÷ इस संधि के बाद के घटनाक्रम में आया तीखा अंतर इस समझौते की असमानता को और भी गहराई से रेखांकित करता है। नेहरू की ढिलाई और राष्ट्रीय हित को दरकिनार करने की प्रवृत्ति समय के साथ भारी पड़ती गई। फरवरी 1962 में, 'वाशिंगटन पोस्ट' को दिए एक साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री नेहरू ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर को ÷आगे की दिशा में एक बड़ा कदम और वास्तव में यह समझौता (कश्मीर के) क्षेत्रीय मुद्दों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण...÷ बताया।

स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद, शांति और अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति की चाहत में कांग्रेस नेतृत्व ने भारत की दीर्घकालिक जल सुरक्षा एवं समृद्धि के बजाय कूटनीतिक सुविधावाद को चुना। तुष्टिकरण की यह नीति कई मोर्चों पर राष्ट्रीय प्रगति के लिए हानिकारक साबित हुई। इस संधि से अपेक्षित मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक लाभ कभी भी साकार नहीं हुए। इसके उलट, यह युद्धों और निरंतर सीमा-पार तनावों के रूप में दुर्भाग्य लेकर आई। जल-बंटवारे की इस सख्त व्यवस्था ने सूखे से लड़ने, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करने और संवेदनशील इलाकों में कृषि को मजबूत करने हेतु अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की भारत की क्षमता को सीमित कर दिया। सत्ता-लोलुप शासकों ने आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की, जिससे भारत कमजोर हो गया। वास्तव में, यह संधि भारत के लिए जल कूटनीति की विफलता और पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक विजय थी।

अब, मोदी सरकार इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में एक और निर्णायक एवं साहसिक कदम उठा रही है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को तब तक के लिए स्थगित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अंतिम रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना छोड़ नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट आह्वान राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी है– ÷आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते; पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते।÷ यह कदम पिछली नीतियों से अलग हटकर एक साहसिक और ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह केवल एक कूटनीतिक पुनर्संतुलन भर नहीं है, बल्कि अपने संसाधनों और किसानों के हितों एवं संबंधित हितधारकों की आजीविका के अवसरों की रक्षा करने के भारत के संप्रभु अधिकार का एक दृढ़ रणनीतिक दावा है - जो पाकिस्तान की ओर से आने वाले लगातार सीमा पार खतरों के सामने ÷राष्ट्र प्रथम÷ के सिद्धांत को सर्वोपरि रखता है।

सिंधु जल संधि का स्थगन कूटनीति से कहीं आगे जाता है—यह विकासशील भारतञ्च2047 के लक्ष्य को साकार करने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। अपने जल संसाधनों पर नियंत्रण फिर से हासिल करके, भारत जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत कर सकता है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकता है—जोकि एक विकसित राष्ट्र बनने की कुंजी है। यह निर्णय पुराने समझौतों द्वारा थोपी गई सहमतियों का अंत करता है और जल संप्रभुता को प्रगति की बुनियाद के रूप में स्थापित करता है। यह एक ऐसा साहसिक कदम है, जो आत्मनिर्भरता, स्थिरता और समावेशी विकास के मिशन के साथ गहराई से जुड़ा है।

(लेखक केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

आकलन पास सहायक अध्यापकों को सहायक आचार्य नियुक्ति में शामिल न करना युक्ति संगत नहीं: सुखदेव हाजरा

गिरिडीह/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। भारतीय संविधान में वर्णित समानता का अधिकार सभी नागरिकों के लिए बराबरी का दर्जा प्राप्त है परंतु शायद झारखंड सरकार के संवैधानिक दस्तावेज में समानता का अधिकार या फिर समान संहिता कानून का जिक्र नहीं किया गया है जिसके चलते राज्य में 62 हजार सहायक अध्यापकों को समानता का अधिकार से वंचित कर सरकार के द्वारा उनके संवैधानिक हक को कुचली जा रही है माननीय उच्चतम न्यायालय का भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मी को स्थायीकरण करते हुए उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाए बावजूद राज्य के 62 हजार सहायक अध्यापकों के साथ सरकार ज्यादती कर रही है उनके वाजिब मेहनताना पर शोषण कर रही है जो बिल्कुल नाइंसाफी है 10%मानदेय में वृद्धि को लेकर आकलन परीक्षा में काफी कठिन प्रश्नों का सामना करने पर भी 31000 पारा शिक्षकों ने आकलन परीक्षा पास करके साबित कर दिया कि पारा शिक्षकों में अभी भी प्रतिभा का जुनून और कुशल शिक्षक बनने की सारी अहताएं पूर्ण करती है टेट परीक्षा पर सरकार और विभागीय अधिकारी ज्यादा मेहरबान हैं तो टेट परीक्षा आयोजित क्यों नहीं कर रही है विगत 10 वर्षो से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कर पाई है इसमें पारा शिक्षकों की क्या गलती है वैसे तो 2010 के पूर्व नियुक्त पारा शिक्षकों पर टेट लागू नहीं होता है वर्तमान में 26000 सहायक आचार्य नियुक्ति में केवल 10592 सफल शिक्षकों को 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की जा रही है तो रिक्त पदों पर आकलन पास सहायक अध्यापकों को भी सहायक आचार्य में नियुक्त होने का अवसर दिया जाना चाहिए वर्तमान में 41000 सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास कर चुके हैं। सरकार आकलन पास सहायक अध्यापकों को नियुक्ति क्या करेंगे उन्हें अब तक आकलन पास का सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया गया है जो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण और नाइंसाफी है सरकार से बिहार मॉडल पर आकलन पास सहायक अध्यापकों को समान काम का समान वेतन देने की मांग की जाती है जिस तरह बिहार के नियोजित शिक्षकों को वेतनमान के साथ साथ अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है उसी तर्ज पर झारखंड के पारा शिक्षकों को वेतनमान का लाभ दिया जाय वरना अविलंब एक बड़ा आंदोलन का आगाज निकट भविष्य में किया जाएगा जिसमें सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी विगत 25 वर्षो से झारखंड में पारा शिक्षकों ने झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं देश और समाज का नाम रौशन करने में अपनी बेहतर भागीदारी निभाने का काम किया है तो उन्हें निश्चित रूप से शिक्षकों को वाजिब मेहनताना का हक और सम्मान मिलना चाहिए राज्य के तमाम पक्ष और विपक्ष के विधायकों एवं माननीय मंत्रियों से विनम्र निवेदन है कि झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में शिक्षा का अलख जगाने वाले पारा शिक्षकों पर मेहरबानी दिखाते हुए विधान सभा सत्र के दौरान सदन में प्रमुखता से हमारी वाजिब मांगों के सवालों को उठाया जाय ताकि हम निसहाय पारा शिक्षकों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाया जा सके अगर इसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो 5 सितंबर के बाद राज्य के तमाम सहायक अध्यापक अपनी मांगों के सवालों को लेकर राजधानी रांची में अनवरत आंदोलन जारी रखेंगे चाहे इसके लिए जेल जाने की नौबत आएगी या फिर पारा शिक्षक की नौकरी से हाथ धोना पड़े हमें स्वीकार है परंतु सरकार के अधीनस्त गुलामी और शोषण की जिंदगी जीना कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं सभी सहायक अध्यापकों से अपील सभी एक मंच पर आकर आंदोलन का शंखनाद करें और अपना हक अधिकार प्राप्त करें जय हिंद जय झारखंड सहायक अध्यापक एकता जिंदाबाद अपनी चट्टानी एकता का परिचय देकर अपने स्वाभिमान और अस्मिता को महफूज रखने में सफल साबित हों।

मोना लॉ कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया शुरू

वर्मा फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, अगमकुआं, पटना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित

पटना/अगमकुआं/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। वर्मा फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, पटना द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समूह के चेयरमैन डॉ. डी.के. सिंह ने जानकारी दी कि मोना लॉ कॉलेज, अगमकुआं, पटना को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (इउक) की स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही यह संस्थान बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध है। डॉ. सिंह ने बताया कि अब संस्थान विधि शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कॉलेज में इस सत्र से एलएल.बी. तथा बी.ए. एलएल.बी. पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य छात्रों को उच्चस्तरीय कानूनी शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे समाज एवं न्याय प्रणाली के सशक्त स्तंभ बन सकें। उन्होंने कहा कि मोना लॉ कॉलेज में विधि शिक्षा के लिए अनुभवी प्राध्यापकों, आधुनिक पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, मूट कोर्ट, सेमिनार हॉल और अत्याधुनिक शिक्षण संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक दक्षता प्रदान करेगा बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास एवं व्यावहारिक ज्ञान पर भी विशेष ध्यान देगा। इस अवसर पर डॉ. डी.के. सिंह ने बताया कि नए सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक छात्र-छात्राएं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से निशुल्क नामांकन का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत योग्य छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण उपलब्ध होगा, जिसके द्वारा वे अपनी पढ़ाई निःसंकोच पूरी कर सकेंगे। डॉ. सिंह ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य है कि बिहार के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को राज्य से बाहर गए बिना गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि कॉलेज में शिक्षा, अनुशासन और अवसर—तीनों का संतुलन बनाकर विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान के शिक्षण व प्रशासनिक विभागों के सदस्य भी उपस्थित थे। सभी ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया और इसे बिहार में विधि शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया।

संक्षिप्त समाचार

अम्बेदकर लॉ कॉलेज के प्रिंसपल बने आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी पटना के डीन

पटना/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार, पटना द्वारा राज्य में विधि शिक्षा का विस्तार एवं संचालन हेतु स्कूल ऑफ लॉ एण्ड लिगल साइंस की स्थापना की गई है। जिसके अन्तर्गत पूरे राज्य में लॉ एजुकेशन का विस्तार के साथ विभिन्न संस्थानो का संचालन भी स्कूल ऑफ लॉ एण्ड लिगल साइंस के द्वारा किया जायेगा। लॉ विभाग के संचालन हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति प्रो. (डॉ.) शरद चन्द्र यादव के द्वारा डॉ. सुभाष चन्द्र यादव प्रिंसपल अम्बेदकर लॉ कॉलेज को विश्वविद्यालय डीन के पद पर नियुक्त किया गया है। अम्बेदकर लॉ कॉलेज छितनावां, दानापुर, पटना के प्रिंसपल ने 21 अगस्त 2025 को अपना योगदान विश्वविद्यालय में डीन के पद पर दिये। विदित हो कि अम्बेदकर लॉ कॉलेज के प्रिंसपल डॉ. सुभाष चन्द्र यादव को विधि के क्षेत्र में 23 वर्षो का अनुभव है। वर्ष 2008 से विधि शिक्षा के क्षेत्र में देश के विभिन्न विख्यात संस्थानों में भी अपनी सेवा दे चुके हैं तथा इन्होने विधि में डॉक्टरेट की उपाधि वर्ष 2018 में प्राप्त किया। स्कूल ऑफ लॉ एण्ड लिगल साइंस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के डीन अम्बेदकर लॉ कॉलेज के प्रिंसपल को बनाये जाने पर संस्थान के सिनीयर विद्यार्थियों एव 'शिक्षको ने अपने प्रिंसपल को शुभकामना दिया। तथा इस अवसर पर अम्बेदकर लॉ कॉलेज के चेयरमैन डॉ. के० कुमार ने अपने प्रिंसपल को शुभकामना देने के साथ ही आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के तहत पोषण वाटिका की पहल

पटना/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा हाजीपुर के सिधौली और सेन्दुआरी गाँव में पोषण वाटिका (किचन गार्डनिंग) को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 140 कृषक परिवारों को सब्जी बीज किट वितरित की गईं। कार्यक्रम का नेतृत्व निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. एन.एस. दहिया ने किया। उन्होंने किसानों को किचन गार्डनिंग, वैज्ञानिक पशुपालन एवं समेकित कृषि प्रणाली अपनाने का आह्वान किया और 'बासुमिन' खनिज मिश्रण के लाभ बताए। प्रधान अन्वेषक डॉ. वाई.एस. जादौन ने किचन गार्डनिंग को उद्यमिता से जोड़ने और पशुओं के नियमित कृमिनाशन एवं टीकाकरण की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं डॉ. कुमारी शुभा और डॉ. कविता वर्मा ने टिकाऊ खेती और जैविक पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। माननीय कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय डॉ. इंद्रजीत सिंह ने इस पहल को किसानों की आजीविका सुधार और ग्रामीण परिवारों में पोषण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्कूल बसों का निरीक्षण किया

गिरिडीह/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। निरीक्षण के क्रम में सभी बसों के फिटनेस, परमिट, बीमा, पॉल्यूशन एवं चालक-परिचालक से संबंधित अभिलेखों की स्थिति का अवलोकन किया गया जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव के निदेर्शानुसार आज जिला परिवहन पदाधिकारी, श्री संतोष कुमार ने स्कूल बसों का निरीक्षण किया, सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन का निर्देश दिया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से संत जोसेफ स्कूल, जमुआ में परिचालित बसों की जांच की। निरीक्षण के क्रम में सभी बसों के फिटनेस, परमिट, बीमा, पॉल्यूशन एवं चालक-परिचालक से संबंधित अभिलेखों की स्थिति का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी वाहनों के आवश्यक कागजात अद्यतन एवं विधिसम्मत हों तथा चालक लाइसेंसधारी और निर्धारित नियमावली के अनुरुप हों। साथ ही सभी बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, स्पीड गवर्नर, सेफ्टी लॉक एवं परिचालक की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन एवं बस मालिकों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी विद्यालय प्रबंधन को समय-समय पर वाहनों की जाँच करानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़क सुरक्षा नियमों के अनुरुप ही परिवहन सेवाओं का संचालन हो।

देवरी में शहीद मुनेश्वर की शहादत पर सहायक अध्यापकों ने दी श्रद्धांजलि

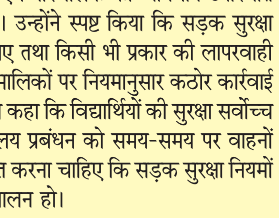

गिरिडीह/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। देवरी प्रखण्ड के उएचएस घोंसे प्रांगण में पारा शिक्षकों के वीर योद्धा शहीद मुनेश्वर सिंह की 18 वीं शहादत दिवस पर सहायक अध्यापकों ने उनकी कुबार्नी को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि बतौर जिला महासचिव सुखदेव हाजरा ने कहा कि पारा शिक्षकों के हक और अधिकार के लिए राजधानी रांची में आयोजित विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरता पूर्ण लाठी चार्ज में पारा शिक्षकों के वीर योद्धा शहीद मुनेश्वर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें घायल अवस्था में रिम्स में एडमिट कराया गया जहां इलाज के दौरान मौके पर उन्होंने दम तोड़ दिया उन्होंने कहा कि साथी मुनेश्वर सिंह सहित 26 साथियों की बलिदानी कभी बेकार नहीं जाने देंगे कहा कि जब तक राज्य के तमाम पारा शिक्षकों को संवैधानिक अधिकार के तहत समान काम का समान वेतन और सम्मानजनक हक नहीं मिलेगा तब तक सरकार के निरंकुशता और दमन के खिलाफ आन्दोलन जारी रहेगा शहीद मुनेश्वर के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना ही सभी शहीद साथियों की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से पारा शिक्षक संघ के प्रखण्ड सचिव उमेश कुमार, प्रखण्ड कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, चौधरी राणा, किशुन राम, राकेश कुमार चौधरी, मुमताज अंसारी, रामदेव विश्वकर्मा, नरेश विश्वकर्मा, कंचन चौधरी सहित अन्य सहायक अध्यापक उपस्थित थे।

असहाय और निर्दोष कैदियों के लिए भी आंदोलन करेगा माले : परमेश्वर महतो

गिरिडीह/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। झूठे मुकदमें में गिरिडीह जेल में बंद थे भाकपा माले नेता परमेश्वर महतो जमानत पर हुए रिहा,समर्थकों ने जताई खुशी कहा भाजपा पुलिस गठजोड़ की हुई हार और न्याय की हुई जीत 20 साल पुराने झूठे और फर्जी मुकदमें में भाकपा माले राज्य कमिटी के वरिष्ठ नेता परमेश्वर महतो की गुरुवार को गिरिडीह जेल से रिहाई हो गई.वे पिछले दस दिन से गिरिडीह जेल में बंद थे.उन्हें जेल से जमानत पर रिहा कराया गया है.जेल से रिहाई के समय भाकपा माले गिरिडीह विधानसभा प्रभारी व राज्य कमिटी सदस्य राजेश सिन्हा,बगोदर उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह,समाजसेवी अनूप ठाकुर,नारायण महतो,भोला स्वर्णकार, उमेश महतो,कैलाश महतो, बोधलाल महतो,रमेश कुमार महतो, कपिलदेव शर्मा,दिनेश महतो,सूरज कुमार, इंद्रजीत कुमार,कन्हाई पंडित समेत कई अन्य दर्जनों लोग उपस्थित थे बताते चलें कि भाकपा माले राज्य कमिटी नेता और बगोदर प्रखंड सचिव परमेश्वर महतो को बीस साल पुराने झूठे मुकदमें में बीते ग्यारह अगस्त को गिरिडीह कोर्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ा जब उन्हें इसके लिए लगातार तीन जरूरी वारंट दिए जाने लगे.इससे बगोदर समेत पूरे जिले में आक्रोश फैल गया था.उनकी रिहाई के लिए तेरह अगस्त को बगोदर में हजारों समर्थकों व कार्यकताओं ने बगोदर में आक्रोश मार्च निकाल कर विरोध जताया था और उनकी अविलंब बिना शर्त रिहाई की मांग की थी अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी.ठीक इसी दिन गिरिडीह जिला मुख्यालय में किसान महासभा के जिला स्तरीय कार्यक्रम में भी उनकी रिहाई की मांग प्रमुखता से उठाई थी.ज्ञात हो कि 16 जनवरी 2005 को झारखंड - बिहार के खासे लोकप्रिय नेता और बगोदर के तात्कालीन विधायक महेंद्र सिंह की साजिशपूर्ण हत्या हो गई.उनकी हत्या से लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया था.तब भाकपा माले ने उनकी साजिशपूर्ण हत्या के लिए तात्कालीन भाजपा की अर्जुन मुंडा की सरकार और गिरिडीह के बेहद बदनाम एसपी दीपक वर्मा और भाजपा मंत्री रविंद्र राय के नापाक गठजोड़ को जिम्मेवार ठहराया था और इनपर कड़ी कारवाई की मांग को लेकर बगोदर थाने में आवेदन भी दिया था.अब इससे बड़ी हास्यास्पद क्या हो सकती है जिन लोगों में जननेता महेंद्र सिंह के हत्यारों को अविलंब पकड़कर गिरफ्तार करने, उन्हें कड़ी सजा देने और उन्हें बेनकाब करने को लेकर थाने में आवेदन लोकतांत्रिक तरीके से दिया,पुलिस ने उन्हीं लोगों पर फर्जी और झूठे मुकदमें लाद दिए.इसी केस में परमेश्वर महतो को बीस साल बाद जेल जाना पड़ा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि प्रशासन फर्जी मुकदमा में फंसा कर आंदोलन को दबाना चाहती है,पर प्रशासन और माले के विपक्ष को यह पता नहीं कि माले और आगे बढ़ता जाता है,शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या करवाने वाले का आज कही नामोनिशान नहीं है और आगे भी वह इतिहास से गायब हो जाएंगे किंतु महेंद्र सिंह का नाम आज भी लोग याद करते है,सदियों तक नाम अमर रहेगा बगोदर उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जो लोग सोचते थे कि महेंद्र सिंह की हत्या कर कमजोरों और गरीबों की लड़ाई और उनकी दावेदारी को खत्म कर देंगे,उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है.भाकपा माले जनता के पक्ष में जेल जाने या शहादत देने से न कभी पीछे हटें है और न हटेंगे.भाजपा और पुलिस के गठजोड़ के खिलाफ आंदोलन और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। उपस्थित थे कन्हाई पांडेय सनातन साहू, भीम कोल्ह, सूदन कोल्ह, मोहन कोल्ह, नवीन पांडेय, रजा आलम,नौशाद आलम,रेहान ,सुकर कोल्ह, लखन कोल्ह, धनेश्वर कोल्ह, किशोर राय, पवन यादव, नारायण सिंह, राजू दास,आदि मौजूद थे।

प्रखंड सभागार में प्री रिविजन एक्टिविटी को लेकर बैठक

गिरिडीह/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रामनिवास यादव के निदेर्शानुसार आज निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 31 गांडेय और उप निर्वाचन पदाधिकारी ने गांडेय प्रखंड सभागार में प्री-रिविजन एक्टिविटी को लेकर बैठक की। बैठक में नजरी नक्शा, बीएलओ/ बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, कम्प्यूटर आपरेटर को मतदान केंद्रों के जियो फेंसिंग और नजरी नक्शा में पायी गयी त्रुटियों का निराकरण करते हुए जल्द से जल्द प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रंथू महतों ने कहा कि निर्वाचन का कार्य बहुत ही संवेदनशील होता है। आप लोगों को जो भी कार्य मिला है, जो भी डायरेक्शन मिला है, उसको अक्षरशः अनुपालन करते हुए नियमानुसार सभी कार्यों को समय पर पूर्ण करें। वहीं 31-गांडेय विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, श्री गुलाम समदानी ने सभी बिंदुओं पर विस्तार से बताया। कहा कि आप लोग अपने बीएलओ को फॉलोअप करके पारदर्शी तरीके से सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे और पूरी समयबद्धता के साथ कार्य को पूरा करेंगे।

अभिव्यक्ति फाउंडेशन एवं रेस्पोंसिबल माइका इनिशिएटिव द्वारा प्राथमिक उपचार एवं फायर फाइटिंग पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

गिरिडीह/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। अभिव्यक्ति फाउंडेशन ने रेस्पोंसिबल माइका इनिशिएटिव (रिमी) के सहयोग से गिरिडीह जिले के होटल अशोका इंटरनेशनल में 21 और 22 अगस्त को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर ऐसे स्वयंसेवकों को तैयार करना था जो आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध करा सकें और उद्योग क्षेत्र में आग लगने की स्थिति से निपटने की बुनियादी समझ विकसित कर सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में गिरिडीह, कोडरमा और बिहार के नवादा जिले से लगभग 85 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों में न केवल गाँवों के ग्रामीण स्वयंसेवक शामिल थे बल्कि माइका उद्योग से जुड़े कई प्रतिनिधि भी सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। इस मिश्रित सहभागिता ने प्रशिक्षण को और भी प्रभावशाली और व्यावहारिक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने प्राथमिक उपचार की बारीकियों को सरल भाषा और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ समझाया। प्रशिक्षण में साँप काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार, गंभीर चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने के उपाय, जलने या बेहोशी जैसी आकस्मिक स्थितियों से निपटने की प्रक्रिया, और समय रहते चिकित्सक तक पहुँचने के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीण स्वयंसेवकों को यह भी बताया गया कि तुरंत की गई सही प्राथमिक मदद कई बार किसी की जान बचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसी तरह प्रशिक्षण के दूसरे भाग में फायर फाइटिंग यानी आग बुझाने और उससे बचाव के उपायों पर भी विशेष सत्र आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को उद्योगों में आग लगने की संभावित स्थितियों, आग से बचाव के उपकरणों के प्रयोग, और सामूहिक रूप से आग पर काबू पाने की रणनीतियों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतिभागियों ने व्यावहारिक अभ्यास भी किया, जिससे उन्हें वास्तविक परिस्थिति में आत्मविश्वासपूर्वक कार्य करने की क्षमता विकसित हो सके। अभिव्यक्ति फाउंडेशन और रेस्पोंसिबल माइका इनिशिएटिव का मानना है कि गाँवों में प्रशिक्षित प्राथमिक उपचार स्वयंसेवकों का नेटवर्क तैयार करना ग्रामीण समाज के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ सीमित हैं और आपात स्थिति में चिकित्सक या अस्पताल तक पहुँचने में समय लग सकता है, वहाँ ये स्वयंसेवक तत्काल सहायता प्रदान कर सकेंगे कार्यक्रम के समापन सत्र में एक विशेष पहल के तहत 50 ग्रामीण प्राथमिक उपचार स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार किट भी प्रदान की गई। इन किटों में बेसिक दवाइयाँ, पट्टियाँ, एंटीसेप्टिक और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल थी, ताकि स्वयंसेवक अपने गाँव में आकस्मिक घटनाओं पर तुरंत कार्यवाही कर सकें। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की और साझा किया कि इस तरह का प्रशिक्षण न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि पूरे समुदाय की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है।

जलवायु सहनशील डेयरी फार्म स्कूल का आयोजन, किसानों को मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण

पटना/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना द्वारा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि परियोजना के अंतर्गत दिनांक 22 अगस्त 2025 को 'जलवायु सहनशील डेयरी फार्म स्कूल' का शुभारंभ ब्रह्मस्थान के निकट भेलुरा रामपुर गाँव में किया गया। यह कार्यक्रम दिनांक 14 नवम्बर 2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संस्थान से डॉ. उज्ज्वल कुमार, प्रभागाध्यक्ष, सामाजिक-आर्थिक एवं प्रसार; डॉ. कमल शर्मा, प्रभागाध्यक्ष, पशुधन एवं मात्स्यिकी प्रबंधन; डॉ. अनिर्बान मुखर्जी, वैज्ञानिक; डॉ. राकेश कुमार, वैज्ञानिक एवं श्री अजीत कुमार पाल, वरिष्ठ अनुसंधान फेलो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी वैज्ञानिकों ने डेयरी किसानों के साथ जलवायु परिवर्तन के डेयरी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की तथा संभावित समाधान एवं सुझाव साझा किए। उन्होंने किसानों को बताया कि बदलते मौसम पैटर्न, अत्यधिक गर्मी एवं ठंड, असमय वर्षा तथा चारे की कमी जैसे कारक सीधे तौर पर पशुओं के स्वास्थ्य एवं दूध उत्पादन को प्रभावित करते हैं। कार्यक्रम में भौगोलिक सूचना प्रणाली और फजी कॉग्निटिव मैपिंग जैसी उन्नत तकनीकों की जानकारी दी गई, जिनके माध्यम से किसान जलवायु संवेदनशील हॉटस्पॉट की पहचान कर अपने प्रबंधन उपायों को सुदृढ़ बना सकते हैं। विशेषज्ञों ने जलवायु

सहनशील नस्ल चयन, पशु आवास प्रबंधन, संतुलित आहार, हरे चारे की उपलब्धता और रोग नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम में कुल 33 डेयरी किसानों ने सक्रिय भागीदारी की और अपने अनुभव साझा किए। किसानों ने वैज्ञानिकों से विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं पर प्रश्न पूछे जिनका समाधान मौके पर दिया गया। यह पहल लघु और सीमांत डेयरी किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी तथा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल टिकाऊ डेयरी उत्पादन प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन : प्राप्त शिकायतों पर जांचोपरांत यथोचित कार्रवाई का मिला आश्वासन

गिरिडीह/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। जनता दरबार आमजन से सीधे संवाद का माध्यम है। इसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना हैल्ल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एक्स)/समाचार पत्रों से प्राप्त शिकायतों का भी समयबद्धता के साथ निराकरण सुनिश्चित कराया जाता है जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया। आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी-बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, मईया समान योजना से जुड़ी समस्याएं, दिव्यागजन हेतु ट्राई-साइकिल की मांग, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अबुआ आवास योजना, शिक्षा विभाग व विद्यालय संचालन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याएं सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनीं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आमजन को राहत मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार एवं शुक्रवार के अलावा भी आमजन अपनी समस्याओं को लेकर समाहरणालय आ सकते हैं, संबंधित विभाग को अपना आवेदन दे सकते हैं, उनके आवेदन का त्वरित निराकरण किया जायेगा। जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव ने कहा कि जनता दरबार आमजन से सीधे संवाद का माध्यम है। इसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना है। हमारा प्रयास है कि जिला प्रशासन हर नागरिक तक प्रभावी ढंग से पहुँचे और विश्वास का वातावरण बने। गौरतलब हो कि समाहरणालय में प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिलेवासी उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याएं साझा करते हैं तथा उनकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण भी किया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निष्पादन और प्रभावी समाधान करना जनता दरबार का उद्देश्य है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (एक्स)/समाचार पत्रों से प्राप्त शिकायतों का भी समयबद्धता के साथ निराकरण सुनिश्चित कराया जाता है उपायुक्त के (क्स एक्स) हैंडल और समाचार पत्रों से प्राप्त शिकायतों का भी पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ निराकरण किया जाता है। इसी क्रम में डुमरी प्रखंड में चेगडो पंचायत स्थित खुरजीयो की वृद्ध माता जी हलवा देवी को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर उपायुक्त द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक को वृद्ध माता जी को पेंशन की योजना से आच्छादित करने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया गया। जिस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए वृद्ध माता जी को पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त बिरनी प्रखंड अंतर्गत शाखाबारा पंचायत के गरायडीह मुख्य मार्ग की मरम्मती से संबंधित शिकायत के मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उक्त सड़क की मरम्मती करा दिया गया है।

पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7 प्रतिशत के करीब, आरबीआई की रिपोर्ट से अनुमान से तेजी से बढ़ी रफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 6.8 से 7 फीसदी की रफ्तार से बढ़ सकती है। यह आरबीआई के 6.5 फीसदी के अनुमान से ज्यादा है। पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े 29 अगस्त को जारी होंगे। एसबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा, पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 6.9 फीसदी के आसपास रह सकती है। सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 6.5 फीसदी अनुमानित है। यह पूर्वानुमान सांख्यिकीय रूप से पिछली तिमाहियों के आधार पर है। हालांकि, पूरे वित्त वर्ष के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 6.3 फीसदी रहने का अनुमान है और यह आरबीआई के पूरे वित्त वर्ष के 6.5 फीसदी के लक्ष्य से कम है। रिपोर्ट में वास्तविक और नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के बीच कम होते अंतर पर भी चर्चा की गई। 2022-23 की पहली तिमाही में यह अंतर 12 फीसदी अंक था, जो 2024-25 की चौथी तिमाही में 3.4 फीसदी अंक रह गया। परिणामस्वरूप पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी 8 फीसदी तक गिर सकती है।

डीआरडीओ और सरकारी रक्षा कंपनियों से मिले ऑर्डर

नई दिल्ली, एजेंसी। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में शुक्रवार को तूफानी तेजी आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर शुक्रवार को 14 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 236.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसे 25.1 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला (लोएस्ट बिडर) घोषित किया गया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को यह ऑर्डर डीआरडीओ और रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों से मिले हैं। 6 महीने में 100 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले 6 महीने में 100 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 24 फरवरी 2025 को 115.65 रुपये पर थे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 22 अगस्त को 236.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 93 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 120 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 88.10 रुपये है।

दोगुना से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का मुनाफा: अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। डिफेंस कंपनी को पहली तिमाही में 17.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को 8.4 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 46 पर्सेंट बढ़कर 133.5 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 91.2 करोड़ रुपये था। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अपने शेयर का बंटवारा कर चुकी है। डिफेंस कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी ने मई 2023 में स्टॉक स्प्लिट किया है।

महंगी गाड़ियां भी होंगी सस्ती

40 प्रतिशत जीएसटी के ऊपर उपकर लगाने की मांग की

नई दिल्ली, एजेंसी।
छोटी कारों और दोपहिया गाड़ियों के साथ-साथ बड़ी सेडान और एसयूवी गाड़ियों की कीमतों में भी भारी कमी आने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि इन पर जीएसटी रेट 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा सकता है। यह रेट लग्जरी और सिन वस्तुओं के लिए तय की गई है। लेकिन एक आशंका यह भी है कि जीएसटी काउंसिल महंगी गाड़ियों पर नया सेस लगा सकती है। कुछ राज्यों ने गुरुवार को मंत्रिस्तरीय पैनल की बैठक में 40 प्रतिशत जीएसटी के ऊपर उपकर लगाने की मांग की। अभी चार मीटर से अधिक लंबाई और एक निश्चित स्तर से ऊपर इंजन क्षमता वाली एसयूवी और सेडान पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 22 प्रतिशत सेस लगता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल की अगले महीने बैठक होगी जिसमें रेट्स के बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार कुछ सिन और लग्जरी

वस्तुओं पर बिना किसी उपकर के एक समान 40 प्रतिशत जीएसटी लगाना चाहती है।

ईवी वर्सेज पुरानी गाड़ियां

सरकारी सूत्रों ने कहा था कि सेस को हटा दिया जाएगा। इसे जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए पांच साल के लिए लगाया जाना था, लेकिन कोविड के कारण हुए नुकसान को कवर करने के लिए इसे तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था। छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर टैक्स का बोझ 29 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत होने की उम्मीद है। एसयूवी खरीदने वालों के लिए यह कमी और भी ज्यादा हो सकती है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के लिए टैक्स में कमी से इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ अंतर कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। कई लोगों का मानना है कि यह कदम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ठीक नहीं है। खासकर दोपहिया सेगमेंट कीमत के प्रति संवेदनशील है। यहां जीएसटी में अंतर 13 प्रतिशत अंक रह जाएगा जबकि वर्तमान में यह 23 प्रतिशत है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कैपिटल कॉस्ट अधिक होती है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है। प्राइस अक्सर एंट्री-लेवल बैरियर के रूप में कार्य करता है।

ग्राहकों की चिंता

हालांकि उपभोक्ताओं और सरकारी हलकों में एक चिंता यह है कि ऑटो इंडस्ट्री टैक्स में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कितनी इच्छुक है क्योंकि यहां एंटी-प्रॉफिटियरिंग नियम लागू नहीं होता है। ऑटो इंडस्ट्री पर अक्सर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया जाता है। लेकिन सरकारी सूत्रों ने कहा कि कंपनियों पर टैक्स कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का दबाव होगा। खासकर बिक्री में सुस्ती को देखते हुए मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है।

रैपिडो पर सीसीपीएने लगाया 10 लाख जुर्माना

नई दिल्ली, एजेंसी।
उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विज्ञापन देने के लिए सेंट्रल कंस्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीपीएने रैपिडो को यह निर्देश भी दिया है कि वह उन उपभोक्ताओं को पैसे लौटाए, जिन्होंने उसके 5 मिनट में ऑटो नहीं मिलने पर 50 रुपये दिए जाने वाले ऑफर का उपयोग किया, लेकिन उन्हें वादे के मुताबिक कंपनसेट नहीं किया गया। रैपिडो को यह विज्ञापन तुरंत बंद करने का निर्देश भी दिया गया।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि चीफ कमिश्नर निधि खरे की अगुवाई में सीसीपीएने रैपिडो के विज्ञापनों की जांच की, जिनमें 5 मिनट में ऑटो नहीं मिलने पर 50 रुपये दिए जाने और गारंटीड ऑटो जैसे वादे थे। सीसीपीएने पाया कि ये वादे झूठे और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले थे। सीसीपीएकी जांच में पता चला कि रैपिडो के विज्ञापनों में जो डिसक्लेमर दिए गए

थे, वे बहुत ही छोटे फॉन्ट्स में थे, जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। इनके मुताबिक, 50 रुपये देने का जो वादा किया गया था, वह असल में रुपये नहीं, बल्कि 50 रुपये तक के 'रैपिडो कॉइन' देने की बात थी। इन रैपिडो कॉइन का उपयोग केवल बाइक राइड्स के लिए किया जा सकता था और ये 7 दिनों में एक्सपायर हो गए। सीसीपीएने पाया कि गारंटी की बात विज्ञापनों में प्रमुखता से दी गई, लेकिन टर्म्स एंड कंडिशंस में कहा गया कि यह वादा इंडिविजुअल ड्राइवरों की ओर से है, न कि रैपिडो की तरफ से। मंत्रालय की नैशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन पर जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ 1224 शिकायतें आई थीं।

आंकड़ों के अनुसार, वाहनों पर लगाई गई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की कुल संख्या 20,16,32,06 है

सरकार ने एफवाय2025 तक असेट मोनेटाइजेशन के जरिए 1.42 लाख करोड़ जुटाए

नई दिल्ली, एजेंसी।
सरकार ने वित्त वर्ष 2025 तक राजमार्ग परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के अलग-अलग तरीकों से 1,42,758 करोड़ रुपये जुटाए हैं। गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि चालू वित्त वर्ष में परिसंपत्ति मुद्रीकरण से अनुमानित रूप से 30,000 करोड़ रुपये आए है। सरकार राजमार्ग परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण तीन तरीकों से करती है- टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर (टीओटी), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) और सिक्योरिटाइजेशन (एसपीवी के माध्यम से परियोजना आधारित वित्तपोषण)। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार

योजना, 2025 (योजना) पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2024 से होने के बाद से 31 जुलाई, 2025 तक 4,971 सड़क दुर्घटना पीड़ितों का इलाज किया गया है।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 (योजना) को अखिल भारतीय स्तर पर अधिसूचित किया गया है। इस योजना के तहत, मोटर वाहन के उपयोग के कारण हुई सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाले किसी भी व्यक्ति को देश भर में किसी भी निर्दिष्ट अस्पताल में दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की सीमा के अधीन, प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक के उपचार का कवर मिलेगा। इसके अलावा, एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि 12 अगस्त 2025 तक वाहन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वाहनों पर लगाई गई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों की कुल संख्या 20,16,32,06 है। मंत्री ने यह भी कहा कि 12 अगस्त, 2025 तक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) में कुल 2,76,990 वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है। टीओटी मोड के तहत, खुले बाजार से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। सड़क खंड रियायत अवधि (15-30 वर्ष) के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिए जाते हैं, जो आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना ट्रस्ट (एनएचआईटी) का गठन किया है। एनएचएआई, एनएचआईटी को उच्चतम मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए 15-30 वर्षों की रियायत अवधि देता है। एनएचआईटी के प्रस्तावित मूल्य की तुलना आरक्षित मूल्य से की जाती है। इसके बाद एनएचआईटी बॉन्ड के जरिए धन जुटाता है और सेबी के प्लेटफ़ॉर्म पर यूनिट बेचकर सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है।

103 करोड़ के ऑर्डर से रॉकेट बना रेलवे स्टॉक

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी के बीच मिड-कैप रेलवे स्टॉक टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर में 4 प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखने को मिली। कंपनी को लीप ग्रेन रेल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से 103.16 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला है। कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि यह ऑर्डर [illegible] वैगनों और [illegible]ब्रेक वैन की सप्लाई के लिए है। इस ऑर्डर को पाने के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आई। कंपनी ने 75 प्रतिशत डिविडेंड (0.75 रुपये प्रति शेयर) देने की सिफारिश की है। कंपनी की अगली 22 सितंबर, 2025 को होगी।

ड्रीम11 ने कारोबार बंद करने की तैयारी की!

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम11 अपने रियल मनी गेमिंग कारोबार को बंद करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने कर्मचारियों को यह जानकारी दी है। रियल-मनी गेम्स कारोबार से ड्रीम स्पोर्ट्स की सालाना आय का करीब 67 प्रतिशत हिस्सा आता था। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जिन ग्राहकों का पैसा ड्रीम11 के वॉलेट में हैं, वह उसे निकाल सकेंगे। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक-2025 संसद से पारित होने के बाद देशभर में संचालित रियल-मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है। इनमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और सट्टेबाजी-शैली वाले ऐप शामिल हैं। इसी के साथ इन ऐप्स के वॉलेट में गेम खेलने वालों की रकम अटकने का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं, ऑनलाइन गेमिंग मंच जूपी ने अपने भुगतान आधारित गेम बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी ने साफ किया कि उसके मुफ्त वाले गेम पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे। खासकर इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स में, जो विदेशों से संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में 700 से अधिक विदेशी ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियां सक्रिय हैं, जिन्होंने यूपीआई को भुगतान विकल्प के रूप में जोड़ रखा है। इन कंपनियों में लेनदेन में काफी उछाल आया है, लेकिन नए विधेयक में किए गए कड़े प्रावधान के बाद इन पर पूरी तरह रोक लगेगी और भुगतान रोक दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे इन ऐप्स का उपयोग करने वाले लोगों की रकम अटक सकती है। नया विधेयक आने के बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग पोर्टल और ऐप्स से गेमर्स द्वारा अपने वॉलेट से रकम निकालने की अफरा-तफरी मच गई है।

टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर नहीं, खपत-विदेशी मुद्रा भंडार बने ताकत

रेटिंग एजेंसियों का आकलन

नई दिल्ली, एजेंसी।
मूडीज, एसएंडपी और फिच जैसी प्रमुख रेटिंग एजेंसियां ट्रंप टैरिफ को भारत के लिए अल्पकालिक चुनौती मानती हैं।हालांकि, अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक परिदृश्य स्थिर और सकारात्मक बना रहेगा। एजेंसियों का आकलन है कि मजबूत घरेलू

खपत, 650 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात विविधीकरण की क्षमता भारत को इन झटकों से बचा लेगी। एजेंसियों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ का सर्वाधिक असर एल्युमिनियम, स्टील, टेक्सटाइल्स और वाहन उपकरणक्षेत्रों पर पड़ेगा, जिनकी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है। फार्मा उद्योग फिलहाल सुरक्षित है। आईटी क्षेत्र भी प्रत्यक्ष टैरिफ से बाहर है, लेकिन अमेरिकी वीजा पॉलिसी और आउटसोर्सिंग नियमों में सख्ती को विशेषज्ञ गैर-टैरिफ बाधा मान रहे हैं।इससे भारतीय आईटी कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। भारत की मध्यम अवधि में विकास दर 6.5-7 फीसदी बनी रहेगी। आधार : मजबूत खपत। जीडीपी का 55 फीसदी से अधिक हिस्सा। पीएलआई जैसी विनिर्माण प्रोत्साहन योजनाएं। फार्मा-आईटी जैसे उच्च मार्जिन क्षेत्रों पर टैरिफ नहीं। एजेंसियों का कहना है कि भारत और चीन दोनों ही अमेरिका के लिए बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, लेकिन स्थिति भिन्न है। 2024-25 में भारत-अमेरिका के बीच 191 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी 17 फीसदी रही। अमेरिका-चीन व्यापार 575 अरब डॉलर से अधिक और निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी 14 फीसदी।चीन पहले से व्यापक अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों के दबाव में है, जबकि भारत को फार्मा एवं आईटी सेक्टर में छूट मिली है। इसलिए, क्रेडिट एजेंसियों का मानना है कि भारत का व्यापारिक परिदृश्य चीन की तुलना में अधिक संतुलित है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा, टैरिफ को एशिया-अफ्रीका में नए निर्यात बाजार तलाशने के अवसर के रूप में देखना चाहिए।

सोने के भाव में तेजी, चांदी 1441 उछली

नई दिल्ली, एजेंसी। सर्राफा बाजारों में आज भी सोने-चांदी के भाव में तेजी है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 102219 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। आज 24 कैरेट सोने का भाव महज 95 रुपये चढ़ कर 99242 रुपये पर खुला है। वहीं, चांदी में 1441 रुपये प्रति किलो की उछाल आई है। जीएसटी समेत चांदी की कीमत 117348 रुपये किलो हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना सस्ता होने की उम्मीद कम है हालांकि, भाव में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। मुद्रास्फीति के दबाव, अमेरिका डॉलर में नरमी और अमेरिका में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को देखते हुये साल 2025 के अंत तक सोने में तेजी रहेगी। आइबीजेए के मुताबिक गुरुवार को चांदी बिना जीएसटी 112490 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 99147 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अब 24 कैरेट गोल्ड 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 2124 रुपये ही सस्ता रह गया है।

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 95 रुपये चढ़कर 98845 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 101810 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 87 रुपये तेज होकर 90906 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 93633 रुपये है। आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 72 रुपये बढ़कर 74432 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 76664 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 59898 रुपये पर पहुंच गया है। सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

भारत टैरिफ का महाराजा; व्हाइट हाउस के सलाहकार नवारो बोले- दोनों के रिश्ते में बढ़ रही खटास

नई दिल्ली, एजेंसी।
व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर फिर तीखा हमला किया और नई दिल्ली को टैरिफ का महाराजा करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत सस्ते रूसी तेल सौदे के जरिये लाभ कमाने की योजना चला रहा है। नवारो का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका ने ही भारत से रूस से तेल खरीदने और वैश्विक ऊर्जा बाज़ार को स्थिर करने में मदद करने का आग्रह किया था। नवारो ने यह भी आरोप लगाया कि भारत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नजदीक जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ रही है, खासकर तब से जब राष्ट्रपति

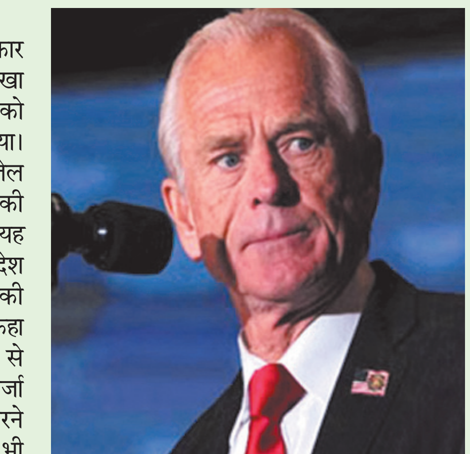

डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ दोगुना कर 50 प्रतिशत तक कर दिया। नवारो ने अमेरिका में संवाददाताओं से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत ने लगभग कोई रूसी तेल नहीं खरीदा था। यह उनकी कुल जरूरत का लगभग 1 प्रतिशत था, लेकिन अब यह बढ़कर 35 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया कि भारत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ा रहा है। नवारो ने कहा कि रूस के रियायती कच्चे तेल की खरीद, इसे परिष्कृत करने और वैश्विक स्तर पर प्रीमियम पर उत्पादों को बेचने में संलिप्त भारत क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट के रूप में काम कर रहा है। रूसी तेल खरीदने के लिए तीखी आलोचना के बावजूद नवारो ने गुरुवार (स्थानीय समय) को भारत के नेतृत्व की प्रशंसा भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता बताते हुए कहा, शांति का मार्ग नई दिल्ली से होकर गुजरता है। नवारो ने तर्क दिया कि भारत को रूसी तेल की ज़रूरत नहीं है, और बताया कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण से पहले, भारत रूस से अपने तेल का 1 प्रतिशत से भी कम आयात करता था। हालांकि, अब वह लगभग 35-40 प्रतिशत आयात करता है।

नवारो ने तीन दिन पहले भी रूस से तल खरीद पर उठाए थे सवाल: यह नवारो का भारत पर कुछ दिनों में दूसरा बड़ा हमला है। तीन दिन पहले भी उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखकर भी भारत की रूस से तेल खरीद पर सवाल उठाए थे। उनका कहना है कि भारत का यह तर्क गलत है कि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूसी तेल चाहिए।

नवारो ने कहा कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है और फिर पेट्रोल-डीजल जैसे परिष्कृत उत्पाद यूरोप, अफ्रीका और एशिया को महंगे दामों पर बेचता है। यह पूरी तरह से भारतीय रिफाइनिंग उद्योग द्वारा मुनाफाखोरी है।

नवारो ने आगे कहा, भारत के साथ हमारे व्यापार का अमेरिकियों पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ता है टैरिफ के मामले में भारत महाराजा है। भारत की ओर से ऊंचे टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं हैं। अमेरिका का भारत के साथ भारी व्यापार घाटा है। इसका अमेरिकी कामगारों और कंपनियों पर बुरा असर पड़ता है।

नवारो ने भारत पर ये भी आरोप लगाया

नवारो का आरोप है कि भारत जो पैसा कमाता है, उसी से रूस से और तेल खरीदता है। फिर रूस उस पैसे से हथियार बनाता है और यूक्रेन पर हमला करता है। इसके बाद अमेरिकी करदाताओं को अपनी सरकार के जरिये यूक्रेन की मदद के लिए और अधिक पैसे और हथियार देने पड़ते हैं। उन्होंने इसे पागलपन करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस युद्ध में अपनी भूमिका मानना नहीं चाहता और इस पूरे कामकाज को उन्होंने

ईपीएफओ ने दी बड़ी राहत, मृत्यु पर मिलेंगे 15 लाख

नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। संगठन ने अपने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष में मिलने वाली एकमुश्त राशि बढ़ा दी है। अब यह राशि 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। यह राशि उस कर्मचारी के नॉमिनी या कानूनी वारिसों को दी जाएगी, जिसकी सेवा के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। इस भुगतान को स्टाफ वेलफेयर फंड से किया जाएगा। ईपीएफओ ने यह जानकारी 19 अगस्त, 2025 के एक सर्कुलर में दी है। इसके साथ ही एक और राहत की खबर यह है कि इस राशि में हर साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी। इसका मकसद है महंगाई और बढ़ती लागत के साथ कदम मिलाकर चलना। साल 2025 में ईपीएफओने अपने सदस्यों के लिए कई सुधार किए हैं ताकि प्रक्रियाएं आसान बन सकें। मसलन, मृत्यु के बाद दावे की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में भुगतान के लिए अभिभावकत्व प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी।

20 से 26 अक्टूबर तक सिकंदराबाद नहीं जायेगी ट्रेनें

नवबिहार टाइम्सस संवाददाता

धनबाद। धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलने वाली दरभंगा-सिकंदराबाद, सिकंदराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस तथा रक्सौल-हैदराबाद व हैदराबाद-रक्सौल स्पेशल ट्रेन 20 से 26 अक्टूबर के दौरान चर्लपल्ली तक जाएंगी और वापसी में वहीं से चलेंगी। सिकंदराबाद स्टेशन पर होनेवाले अपग्रेडेशन कार्यों के कारण अस्थायी रूप से चर्लपल्ली तक चलाया जाएगा। धनबाद से कोयंबटूर एवं बरौनी से धनबाद होकर पोत्तनूर (कोयंबटूर) तक चलने वाली साताहिक स्पेशल ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग गुरुवार से शुरू हो गई।

धनबाद से कोयंबटूर की ट्रेन आठ सितंबर से एक दिसंबर व कोयंबटूर से धनबाद के बीच पांच सितंबर से 28 नवंबर तक चलेगी। बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल ट्रेन नौ सितंबर से दो दिसंबर तथा पोत्तनूर-बरौनी स्पेशल ट्रेन छह सितंबर से 29 नवंबर तक चलेगी। धनबाद से बेंगलुरु यशवंतपुर के लिए साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा हो गई है। धनबाद से गोमो, गया, डीडीयू होकर चलने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इस ट्रेन से बेंगलुरु पहुंचने में 48 घंटे 45 मिनट लगेंगे।

झारखण्ड में 37 किमी बिछेगी नई रेल लाइन

- भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर, राशि आवंटित
- फरवरी 2017 में मिली थी योजना की स्वीकृति

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

देवघर। संताल परगना के विकास की रफ्तार तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कारण संताल का चहुंमुखी विकास हो रहा है। रेल की परियोजनाएं बढ़ती ही जा रही है। पीएम गति शक्ति योजना के कारण बासुकीनाथ-चितरा जोड़ामो लाइन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। बासुकिनाथ-चितरा जोड़ामो रेल लाइन पर एक हजार करोड़ खर्च होगा। और 37 किलोमीटर के इस रेल परियोजना की पूरी राशि केंद्र सरकार देगी।

सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने कहा कि बासुकिनाथ-चितरा जोड़ामो रेल लाइन परियोजना जो राज्य सरकार द्वारा राशि नहीं देने के कारण बंद हो गयी थी उसे प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के पैसे से बनाने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री संताल परगना, अंग प्रदेश खासकर गोड्डा लोकसभा को दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा का लगातार तोहफा दे रहे हैं।

सांसद ने कहा कि संताल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रतिबद्ध हैं। रेल मंत्री ने सांसद को पत्र लिखकर यह जानकारी दी कि यह प्रोजेक्ट स्वीकृत है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। जानकारी हो कि इस प्रोजेक्ट के लिए 267 करोड़ रुपया भूमि अधिग्रहण मद में पहले ही केंद्र सरकार ने आवंटित कर दिया था। जिसमें कार्य भी हुआ और शेष कार्य चल रहा है।

बासुकीनाथ-चितरा रेल लाइन का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने फरवरी 2017 में स्वीकृत किया था। परियोजना से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक तरफ चितरा से कोयला ढुलाई की समस्या जड़ से समाप्त होगी। जो अभी सड़क मार्ग से जामताड़ा जा रहा है। दूसरा चितरा के रास्ते बासुकीनाथ और उधर जोरामो से कनेक्शन होगा। जो देवघर-दुमका रेल लाइन और दूसरी ओर दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन को कनेक्ट करेगा।

तब यात्री ट्रेन से क्षेत्र के लोगों को सुलभ और सस्ता रेल यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यह प्रोजेक्ट 800 करोड़ का था जो एक हजार करोड़ का हो गया। यह तय नहीं हो सका कि राज्य सरकार 50-50 के कास्ट शेयरिंग पर कितना देगी। जबकि राज्य सरकार ने सितंबर 2017 में अपना कंसेंट दे दिया तब भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हुआ।

पूर्व रेलवे ने भूमि अधिग्रहण में 300 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2022 में झारखंड सरकार को एमओयू करने के लिए आग्रह पत्र भेजा। लेकिन एमओयू नहीं हो सका । परियोजना अटक गया था। एक साल से लगातार सांसद डॉ. निशिकांत दुबे प्रयासरत थे। वह लगातार रेल मंत्री से इस प्रोजेक्ट पर मिलते रहे। इसके साथ साथ नई रेल परियोजना पर चर्चा करते रहे।

जब राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया तब पीएम गति शक्ति योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को लिया गया।

महिला ने लगाया एएसआई पर दुष्कर्म का आरोप

दागदार हुई वर्दी, त्वरित न्याय की मांग

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

जामताड़ा। फतेहपुर थाना में पदस्थापित एएसआई विरंची भोक्ता पर एक महिला ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि आरोपी एएसआई ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा मारपीट कर जबरन दुराचार किया।

महिला की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष जामताड़ा में बयान के लिए प्रस्तुत किया। वहीं, पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

आमजन के बीच चर्चा जोरों पर है कि जिस पुलिस पर नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, यदि वही कानून की सीमा लांघ दे तो आम जनता किस पर भरोसा करें।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाली है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आम लोगों का विश्वास पुलिस पर कायम रह सके। वहीं, कुछ लोग इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।

इधर जिला पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपों की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। यदि जांच में एएसआई दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पुलिस विभाग भी अपराधियों को संरक्षण नहीं देगा।

विकास के नाम पर 3500 पेड़ों पर संकट

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बेरमो। कोल इंडिया की मेगा प्रोजेक्ट कारो ओपन कास्ट परियोजना (ओसीपी) को लेकर क्षेत्र में तनाव और विवाद बढ़ता जा रहा है। सीसीएल बीएंडके एरिया के इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 226 हेक्टेयर वनभूमि पर बड़े पैमाने पर कोयला खनन की तैयारी हो रही है।

यहां लगभग 62 मिलियन टन कोयले का भंडार होने का अनुमान है। प्रबंधन ने पहले चरण में लगभग 3500 पेड़ काटने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से कई पेड़ पहले ही गिरा दिए गए हैं। ग्रामीण लगातार पेड़ कटाई का विरोध कर रहे हैं।

बड़ा प्रश्न यह है कि एक पेड़ के बदले छह पेड़ लगाने की सहमति के बावजूद आज तक एक भी पौधा नहीं लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि पौधारोपण के लिए राशि वन विभाग को सौंप दी गई है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई पहल नहीं दिखी है।

इस स्थिति में परियोजना क्षेत्र का पर्यावरणीय संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। वन विभाग के अनुसार सीसीएल ने क्षतिपूर्ति राशि दे दी है। जमीन चिन्हित नहीं है। तीन साल में पौधारोपण किया जाना है।

कारो ओसीपी परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया वर्ष 2006 में शुरू हुई थी। लंबी पत्राचार प्रक्रिया के बाद वर्ष 2018 में स्टेज-वन की मंजूरी मिली। लगभग 19 वर्ष बाद 2025 में स्टेज-टू की स्वीकृति दी गई, जिसके बाद कोयला उत्पादन का रास्ता साफ हो गया।

प्रबंधन का दावा है कि इस खदान से अगले 16 वर्षों तक हर साल 10 से 12 लाख टन कोयला निकाला जा सकेगा। पिछले वर्ष 12 दिसंबर को तत्कालीन डीएफओ रजनीश कुमार ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था। इसके बाद पेड़ों की नंबरिंग और कटाई की प्रक्रिया शुरू हुई।

विभाग ने हाल ही में पेड़ कटाई की अनुमति भी जारी कर दी। योजना के अनुसार परियोजना क्षेत्र के पांच किलोमीटर दायरे में 6250 पौधारोपण की व्यवस्था होनी थी, लेकिन अब तक कोई असर नहीं दिखा है।

प्रबंधन की योजना के अनुसार आने वाले दिनों में लगभग 35 हजार पेड़ काटे जाएंगे। इनमें से 10,200 पेड़ों की कटाई का टेंडर जारी हो चुका है। यह कार्य शशि प्रताप सिंह जेबी कंपनी को मिला है, जिसने अब

चिकित्सकों की लापरवाही से गयी प्रसूता की जान

अस्पताल में परिजनों ने काटा बवाल

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

जामताड़ा। जामताड़ा मेमोरियल अस्पताल में शुक्रवार को लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। ऑपरेशन के बाद गलत इलाज के कारण एक प्रसूता की मौत हो गई। वह पिछले तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती थी।

मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने एक डॉक्टर को अस्पताल में ही बंधक बना लिया, जबकि अन्य डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जामताड़ा मेमोरियल अस्पताल बिना किसी मान्यता के वर्षों से चल रहा है। यहां मरीजों को उचित इलाज देने के बजाय फजीर्वाड़ा कर इलाज किया जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण यह अस्पताल खुलेआम संचालित हो रहा था।

मौके पर मौजूद एक डॉक्टर ने खुद को पीएचसी मधुपुर का पदस्थापित डॉक्टर बताया। उसने कहा, मैं पीएचसी मधुपुर में पदस्थापित हूं, लेकिन यहां 24 घंटे रहता हूं। इस बयान ने परिजनों और आम जनता के बीच आक्रोश को और बढ़ा दिया। लोगों ने सवाल उठाया कि जब डॉक्टर की पदस्थापना किसी अन्य जगह है तो वह जामताड़ा में निजी अस्पताल में 24 घंटे कैसे मौजूद रहता है।

शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग पर विपक्ष ने भी जतायी सहमति

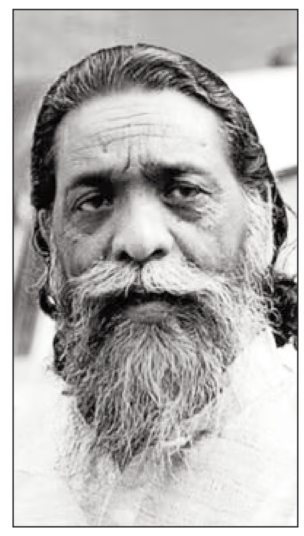

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रांची। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होते ही गरमा गया। सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक सदन से बाहर प्रदर्शन करते हुए भाजपा पर हमलावर नजर आए। सत्ता पक्ष ने एसआईआर के मुद्दे और हाल ही में संसद से पारित 130वें संविधान संशोधन बिल का विरोध किया।

प्रदर्शन के दौरान झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित करने की जोरदार मांग उठाई।

नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड की अस्मिता और अलग राज्य की लड़ाई में जीवनभर योगदान दिया है, इसलिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी सहमति जताई। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी भारत रत्न की मांग का समर्थन किया, जिससे सदन में दुर्लभ सहमति देखने को मिली।

सत्ता पक्ष के विधायकों ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शिबू सोरेन की जीवनी को शामिल करेगी, ताकि नई पीढ़ी उनके संघर्ष और योगदान से परिचित हो सके।

नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू, माले विधायक अरूप चटर्जी और अन्य विधायकों ने भाजपा पर जनता को गुमराह करने और मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया।

वहीं, भाजपा नेता सूर्या हांसदा ने सत्ता पक्ष पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और निर्दोष लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानसून सत्र की शुरूआत से ही जिस तरह का माहौल बना है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा देखने को मिलेगा। एसआईआर और 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर दोनों पक्षों के बीच टकराव और बढ़ सकता है।

पांच वर्षों में 109 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रांची। माओवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने व राज्य को माओवाद से मुक्त करने के लिए लाई गई राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति को शत प्रतिशत लागू कराने में सरकार के अधिकारी ही शिथिल पड़े हुए हैं।

जिला पुनर्वास समिति की ससमय नहीं हो रही बैठकों के चलते आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को इस नीति के तहत प्रस्तावित वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य को माओवादियों से मुक्त कराने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर हैं।

उन्होंने पूर्व में विधि व्यवस्था संबंधित बैठकों में अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि राज्य सरकार की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति से आच्छादित वैसे सभी माओवादियों को, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्हें उसका शीघ्र लाभ दिलाएं।

वर्तमान में स्थिति यह है कि हजारीबाग स्थित खुली जेल में बंद 63 माओवादी हैं। इनमें 55 पुरुष व आठ महिला माओवादी हैं। इन 63 माओवादियों में सिर्फ आठ ही ऐसे हैं, जिन्हें जमीन मिली।

घर बनाने का पैसा किसी को नहीं मिला। बच्चों की शिक्षा व अन्य व्यवस्था की दिशा में भी अधिकारियों की उदासीनता रही है। परेशान आत्मसमर्पित माओवादियों ने राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय से पत्राचार कर अपना हक मांगा है और उनके किए गए वादों को याद दिलाया है।

मिली जानकारी के अनुसार किसी भी माओवादी के परिवार का सामूहिक बीमा नहीं हुआ है। बच्चों की निश्शुल्क शिक्षा व निश्शुल्क कानूनी सेवा भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जिन आठ माओवादियों को जमीन मिली, उनमें प्रेमशिला, रिमिल, संतोष भुइयां, कान्हूराम मुंडा, ऐनुल मियां, खुदी मुंडा, रामकुमार भोग्ता व फोगरा मुंडा शामिल हैं।

सरकार की पुर्नवास नीति लागू कराने में अधिकारी विफल

एक जनवरी 2020 से अब तक राज्य में 109 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जिनपर गंभीर मामले दर्ज हैं, उन्हें सामान्य जेल में रखा गया है। वैसे माओवादियों को सरकार की ओर से ही निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है, जो उनके पक्ष को न्यायालय में रख सकें।

मुख्य धारा में लौटने वाले सभी माओवादियों को उनपर दर्ज कांडों में जमानत मिलने के बावजूद सुरक्षा के ख्याल से उन्हें खुली जेल में रखा जाता है। यहां वे अपने परिवार के साथ रह सकते हैं।

वैसे माओवादी जिन्हें जमानत मिलने के बावजूद किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, उन्हें उनके गांव जाने दिया जाता है।

राज्य में सबसे पहले 18 फरवरी 2009 को माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण नीति लागू हुई थी। तब से लेकर अब तक करीब 300 से अधिक माओवादियों ने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाया।

2009 की आत्मसमर्पण नीति को और बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2015 व उसके बाद वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था। संशोधित नीति में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए आकर्षक योजनाएं लागू हुईं थीं।

कुंदन पाहन, शंकर यादव, महाशय सोरेन, प्रीशिला, प्रेमशिला, पक्कू टुडू, सिद्धू मरांडी, उमेश गंझू, बलवीर महतो, देवीलाल हांसदा, नुनूलाल हांसदा, रिमिल हेम्ब्रम, राजेंद्र राय, जीवन पतरस कंडुलना, नकूल यादव, राधेश्याम कुमार, सुरेश मुंडा, राकेश मुंडा, सूरज सरदार गजू सरदार, गीता गांगुली, महाराज प्रमाणिक, मुकेश गंझू, भवानी भुइया, बिलोन सरदार, चांदनी सरदार, सोमवारी कुमारी, मिथिलेश सिंह, जयराम बोदरा, सरिता, नागेश्वर गंझू, अमन गंझू, दशरथ उरांव, इंदल गंझू, संतोष भुइया, अमरजीत यादव, नीरू यादव, सहदेव यादव, संटू भुइया, कान्हूराम मुंडा, बिमल लोहरा, विजय यादव, कुलदीप गंझू, एनुल मियां, खुदी मुंडा, नुनू चंद महतो, चंद्रमोहन, अमन बोइपे, नीरज सिंह खेरवार, राम कुमार भोग्ता, मनोहर परहिया, रामदयाल महतो, जितेंद्र नगेसिया, रामजीत नगेशिया, विष्णु दयाल नगेसिया, सूरज नाथ खेरवार, जतरू खेरवार, सुनीता मुरमू, बासुदेव हजाम, लोदरो लोहरा, बोयदा पाहन, फोगरा मुंडा, मदन यादव व औदेश गंझू।

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को उस पर इनाम की पूरी राशि उसे देय है। इसके अलावा जोनल कमांडर व उससे उपर वाले के लिए पुनर्वास अनुदान छह लाख रुपये, जिसमें दो लाख रुपये तत्काल व चार लाख में दो लाख एक वर्ष पर व दो लाख दो वर्ष के बाद विशेष शाखा की रिपोर्ट पर दिए जाते हैं। जोनल कमांडर से नीचे रैंक वालों के लिए पुनर्वास अनुदान तीन लाख है, जिसमें एक लाख रुपये तत्काल व दो लाख में एक लाख एक वर्ष व दूसरा एक लाख दूसरे वर्ष पर देने का प्रविधान है।

अधिकतम चार डिसमिल जमीन व मकान बनाने के लिए 40 हजार रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तों वालों को उसका लाभ दिलाना है।

माओवादी व उसके परिवार वालों को निश्शुल्क चिकित्सा, माओवादियों के बच्चों को स्नातक स्तर तक निश्शुल्क शिक्षा या अधिकतम 40 हजार रुपये वार्षिक प्रत्येक तिमाही में देय है। माओवादी का पांच लाख तक का बीमा व परिवार का एक लाख का बीमा दिया जाता है।

रांची के 19 बालू घाटों की निलामी होगी जल्द

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रांची। झारखंड में बालू के अवैध कारोबार पर लगाम कसने और सरकारी खजाने को मजबूत करने के लिए हेमंत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब रांची जिले में 19 बालू घाटों की ई-नीलामी की जाएगी। इस कदम से न सिर्फ बालू माफियाओं की कमर टूटेगी, बल्कि राज्य सरकार को सालाना करोड़ों रुपये का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। जिला खनन कार्यालय द्वारा जारी इस सूचना के बाद से खनन क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय झारखंड बालू खनन नियमावली, 2025 के तहत लिया गया है, जिसे हाल ही में लागू किया गया है। नियमावली के अनुसार, चिह्नित किए गए 19 घाटों को कैटेगरी-2 में रखा गया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ताकि कोई भी इसमें गड़बड़ी न कर सके। खनन के इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, ई-बोली की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रणाली सरकार को पूरी प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम बनाएगी, जिससे भ्रष्टाचार और कालाबाजारी खत्म होगी।

यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में घाटों की नीलामी पारदर्शी तरीके से की जा रही है। नीलामी के लिए चुने गए घाटों में कांछी, रारु, पाकरो, सुवर्णरेखा, चट्टी और सपही जैसी प्रमुख नदियों के किनारे स्थित घाट शामिल हैं : कांची नदी : लोहातु, चुरगी, चिलुटीकर, सरजामडीह, अनरेदीह, करम्बू, पांगुरा, बरेदीह, तुनजू, एरकिया, सुमंडीह, सुतिलौंग, बादला, गोमियाडीह, हराडीह, दारूआरा, सोमाडीह। रारु नदी : श्यामनगर, बिरदीडीह, करेयाडीह, इचाहातु। पाकरो नदी : बसंतपुर। स्वर्णरेखा नदी : श्यामनगर, चोकेसेरंग, डुमरबेरा, सुंदील। चट्टी नदी : लपरा। सपही नदी : चूरी व राय। अधिकारियों ने बताया कि ई-नीलामी का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा।

राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 51 कैदियों को रिहा करने पर बनी सहमति

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक में राज्य की जेलों में बंद आजीवन कारावास के 51 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। इस बैठक में कुल 103 कैदियों से संबंधित मामलों की समीक्षा में यह निर्णय लिया गया।

इन 103 कैदियों में रिहाई से संबंधित 37 मामले नए थे, जबकि 66 कैदी वैसे थे, जिनका मामला पूर्व में भी पर्षद की बैठक में गया था, लेकिन अस्वीकृत हो गया था। प्रत्येक 103 कैदियों की एक-एक फाइल पर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप से 51 कैदियों को छोड़ने पर सहमति बनी।

विचार-विमर्श के दौरान कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति, न्यायालय की टिप्पणी व आदेश, संबंधित जिलों के एसपी, जेल अधीक्षक की टिप्पणी, प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य को देखा गया व उसका अध्ययन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को हर हाल में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में राज्य की विभिन्न जेलों में 14 वर्ष या इससे अधिक समय तक सजा काट चुके वैसे कैदी, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है तथा जेल में उनका आचरण अच्छा है, उन्हें रिहा किया जाता है।

रिहा हो रहे ऐसे कैदियों को बेहतर सामाजिक जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करें। रिहाई से संबंधित अनुशंसित मामलों में कुछ ऐसे मामले भी हैं, जिसमें कैदियों के बीमार होने तथा कुछ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आई है।

ऐसे कैदियों को शारीरिक व मानसिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। ऐसे कैदियों की चिकित्सा के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि वह अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत कर सके।

बैठक में मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में सहमति के बाद वर्ष 2019 से अब तक राज्य की विभिन्न जेलों से 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। इनमें 558 कैदियों का विभाग ने भौतिक सत्यापन किया है। अब भी 61 बंदियों का भौतिक सत्यापन शेष है।

वर्ष 2019 से अब तक रिहा हुए 619 में से 470 कैदियों को सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा ईश्रम कार्ड आदि से जोड़ा है।

रिहा हुए वैसे कैदी जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ने का कार्य प्रक्रियाधीन है। जल्द ही सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उन्हें भी आच्छादित किया जाएगा।

आदिवासी बच्चे सरकारी योजना के लाभ से वंचित

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बिरनी । बिरनी अंचल के प्रसबनी में प्रस्तावित आवासीय आदिवासी उच्च विद्यालय है। इस स्कूल के करीब एक हजार बच्चों के लिए विडंबना है कि दो दशक से छात्र-छात्राओं को सरकार की तरफ से एमडीएम, साइकिल, पोशाक व किताबें नहीं मिलती, इसकी न कोई सुध लेने वाला है और न कोई जवाब देने वाला। जनप्रतिनिधि भी बच्चों को सरकारी लाभ दिलाने के प्रति उदासीन बने हुए हैं।

विद्यालय में कक्षा एक से लेकर 10वीं कक्षा तक कि पढ़ाई होती। यह स्कूल सरकार व विभाग से मान्यता प्राप्त है। इस विद्यालय में करीब 1000 हजार बच्चों का नामांकन है। सत प्रतिशत बच्चे प्रतिदिन उपस्थित होते है। स्कूल को सरकार व विभाग से हर साल अनुदान राशि मिलती है।

इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को एमडीएम, किताब, साइकिल, पोशाक नहीं मिलता। इस पर किसी भी जनप्रतिनिधियों व विभाग के अधिकारियों ने अब तक ध्यान नहीं दिया। जबकि सरकार का निर्देश है कि कोई भी स्कूल के बच्चे एमडीएम से वंचित नहीं रहे।

विद्यालय कक्षा एक से लेकर आठवीं के बच्चे को दोपहर में एमडीएम भोजन तो दूर अतिरिक्त पौष्टिक आहार में अंडा व फल भी नसीब नहीं हो रहा है। स्कूल के बच्चे सुधीर यादव , रोशन वर्मा, अजय यादव , विक्रम यादव, सचिन वर्मा , आफताब अंसारी, पप्पू यादव आदि ने कहा प्रतिदिन स्कूल आते है। पढ़ाई अच्छी होती है। सरकार की ओर से मिलने वाला सारी सुविधा से वंचित है।

शिक्षा विभाग से समय-समय पर जांच करने अधिकारी पहुंचते हैं। उनसे भी कहते है कि सरकार से मिलने वाले सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अधिकारी आश्वासन देकर निकल जाते हैं। जबकि स्कूल को हर साल करीब सात लाख अनुदान राशि मिलती है।

व्यवसायी के घर से 16 लाख नगदी सहित आभूषणों की चोरी

नींद की दवा स्प्रे कर घटना को अंजाम देने की आशंका

नवबिहार टाइम्मस संवाददाता

सरिया (गिरिडीह)। सरिया थाना क्षेत्र के पेठियाटांड़ में एक किराना व्यवसायी के घर गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने लगभग 16 लाख रुपया व 10 लाख के जेवरात की चोरी कर ली।

किराना व्यवसायी कैलाश मंडल ने बताया कि अन्य दिनों की भांति अपनी दुकान को बंद कर ऊपर मकान में खाना खाने के बाद सोने के लिए चले गए। वहीं बगल के दो बंद कमरों से अज्ञात चोर दुकान के गोदाम में बने दरवाजे को तोड़कर घुसे। गोदरेज, अलमारी, बक्से आदि में रखें व्यवसाय के लिए 16 लाख रुपया नगदी, 10 सोने की अंगूठी दो डायमंड रिंग समेत कई सामान लगभग 26 लाख की संपत्ति चोरी कर चलते बने।

चोरी के वक्त परिवार के अन्य सदस्य घर के अगल-बगल के ही कमरे में सो रहे थे। लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं लग सकी।

ऐसा प्रतीत हुआ की चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चोरों ने नशे या नींद की दवा का स्प्रे किया हो ।इस कारण चोरी की घटना का जानकारी नहीं हो सका। सुबह सभी लोग जब सो के उठे तो घर के दरवाजे खुले व सामान बिखरा देखकर इसकी जानकारी हो पाई।

घटना की तत्काल सूचना सरिया पुलिस को देने के बाद सुबह-सुबह पुलिस जाकर निरीक्षण करने के पश्चात चली गई ।

वहीं घटना की सूचना पाकर दर्जनों की संख्या में स्थानीय लोग विभिन्न पार्टी के नेता सामाजिक कार्यकर्ता पीड़ित के घर पहुंचकर इस घटना की निंदा की। सरिया पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल लोग उठाए।

लोगों का कहना था कि लगभग एक से डेढ़ माह पूर्व इसी गांव के लगभग चार से पांच घरों में चोरी की इसी प्रकार की घटना घटी थी।सरिया पुलिस इन घटनाओं का खुलासा अभी तक नहीं कर पाई है ।

इधर,चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कई लोग सरिया पुलिस की कार्यशैली के विरुद्ध सड़क को जाम कर दिया है

विमेंस वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बदलाव

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से छिन गई विश्व कप मैचों की मैजबानी, आईसीसी ने बदला वेन्यू

बेंगलुरु में होने वाले मैच मुंबई में खेले जाएंगे, ओपनिंग मैच भी शामिल

दुबई (एजेंसी)। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने 30 सितंबर से भारत में होने वाले विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बदलाव किया है। गुरुवार को जारी नए शेड्यूल के अनुसार, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैचों को नवी मुंबई स्थित डी वाई पाटिल स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है। इनमें भारत और श्रीलंका के बीच ओपनिंग मैच और दूसरा सेमीफाइनल जैसे मैच शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने वहां के स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) को मैच कराने की मंजूरी नहीं दी। आरसीबी की विक्ट्री सेरेमनी में मची भगदड़ के बाद जांच करने वाले जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोग ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए ठीक नहीं माना था। इससे पहले 11 अगस्त से शुरू होने वाली घरेलू टी-20 लीग महाराजा ट्रॉफी को मैसूर शिफ्ट कर दिया गया। इससे विमेंस वर्ल्ड कप के मैचों और 2026 में यहां आईपीएल मैचों की मेजबानी पर भी सवाल खड़े हो गए। जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोग ने कहा था-32,000 दर्शकों की क्षमता वाला एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो सिर्फ 17 एकड़ में फैला है, बड़े आयोजनों के लिए ठीक नहीं है। आयोग ने सलाह दी थी कि ऐसे मैचों को ज्यादा जगह और बेहतर सुविधाओं व पार्किंग वाले स्थानों पर कराया जाए।

विरुद्ध	डेट	टाइम	वेन्यू
श्रीलंका	30 सितंबर	3:00 PM	गुवाहाटी
पाकिस्तान	5 अक्टूबर	3:00 PM	कोलंबो
साउथ अफ्रीका	9 अक्टूबर	3:00 PM	विशाखापट्टनम
ऑस्ट्रेलिया	12 अक्टूबर	3:00 PM	विशाखापट्टनम
इंग्लैंड	19 अक्टूबर	3:00 PM	इंदौर
न्यूजीलैंड	23 अक्टूबर	3:00 PM	नवी मुंबई
बांग्लादेश	26 अक्टूबर	3:00 PM	नवी मुंबई
सेमीफाइनल-1	29 अक्टूबर	3:00 PM	कोलंबो/ गुवाहाटी
सेमीफाइनल-2	30 अक्टूबर	3:00 PM	नवी मुंबई
फाइनल	2 नवंबर	3:00 PM	कोलंबो/ नवी मुंबई

डी वाई पाटिल स्टेडियम को 5वां वेन्यू बनाया – आईसीसी ने मुंबई को वर्ल्ड कप की मेजबानी का 5वां वेन्यू बनाया है। पहले बेंगलुरू 5वां वेन्यू था। टूर्नामेंट में 28 लीग और 3 नॉकआउट मैच होंगे। संशोधित शेड्यूल के अनुसार, मुंबई, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और कोलंबो में खेले जाएंगे। वहीं, पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में (पाकिस्तान के पहुंचने पर निर्भर) और दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को मुंबई में होगा। फाइनल 2 नवंबर को नवी मुंबई या कोलंबो में खेला जाएगा।

पाकिस्तान के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल पर होंगे - पाकिस्तान के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल पर श्रीलंका में खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के बीच हुए हाइब्रिड समझौते के अनुसार, पाकिस्तान की टीम अपने सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू कोलंबो में खेलेगी। इनमें बांग्लादेश (2 अक्टूबर), इंग्लैंड (15 अक्टूबर), न्यूजीलैंड (18 अक्टूबर), दक्षिण अफ्रीका (21 अक्टूबर) और श्रीलंका (24 अक्टूबर) के खिलाफ मैच शामिल हैं।

बेंगलुरु में हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी - चिन्नास्वामी स्टेडियम मे जून में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के आसपास हुई भगदड़ ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। इस हादसे में 11 लोगों की जान गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

बीसीसीआई का निर्देश-दलीप ट्रॉफी में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को शामिल करें

- **स्टेट एसोसिएशन को लिखा पत्र, साउथ जोन की टीम में सिराज-राहुल का भी नाम नहीं**

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दलीप ट्रॉफी जैसे प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में सेंट्रली-कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को शामिल करने का सख्त निर्देश जारी किया है। यह कदम तब उठाया गया जब साउथ जोन ने केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और साई सुदर्शन जैसे बड़े खिलाड़ियों को अपनी दलीप ट्रॉफी टीम में नहीं चुना। यह टूर्नामेंट 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होने वाला है।

बीसीसीआई की ओर से भेजा गया पत्र – पिछले हफ्ते, बीसीसीआई के जनरल मैनेजर (क्रिकेट ऑपरेशंस) अभय कुरुविला ने सभी राज्य क्रिकेट संघों को एक ईमेल भेजा। इसमें उन्होंने दलीप ट्रॉफी को सम्मान देने और इसकी प्रतिस्पर्धा को उच्च स्तर पर बनाए रखने की बात कही। कुरुविला ने लिखा, दलीप ट्रॉफी के रुतबे को बनाए रखने के लिए, सभी उपलब्ध भारतीय खिलाड़ियों को उनकी जोनल टीमों में चुना जाना जरूरी है। जोनल संयोजकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी उपलब्ध भारतीय खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी के लिए चुने जाएं।

- **साउथ जोन का फैसला और असमंजस** – साउथ जोन ने 27 जुलाई को सबसे पहले अपनी दलीप ट्रॉफी टीम की घोषणा की थी, जिसमें तिलक वर्मा को कप्तान बनाया गया। उस समय बीसीसीआई का यह निर्देश नहीं आया था। अब यह साफ नहीं है कि कुरुविला के ईमेल के बाद साउथ जोन अपनी टीम में बदलाव करेगा या नहीं।
- **कौन-कौन खेलेगा दलीप ट्रॉफी** – इस बार दलीप ट्रॉफी में शुभमन गिल (टेस्ट कप्तान), यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव, आकाश दीप, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी-अपनी जोनल टीमों के लिए खेलते नजर आएंगे।
- **बीसीसीआई के नियम क्या कहते हैं** – कुरुविला ने अपने ईमेल में यह भी स्पष्ट किया कि सभी कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को बीसीसीआई के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने लिखा, सभी खिलाड़ी, चाहे कॉन्ट्रैक्टेड हों या नहीं, जो भारतीय टीम के लिए चयन के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा।

पीकेएल-12 -12 गुजरात जायंट्स के कप्तान मोहम्मदरेजा ने कहा

यह सीजन मेरे लिए अलग, इरानी खिलाड़ी गुजरात की कप्तानी करेगा

नईदिल्ली (एजेंसी)। प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन की शुरुआत 29 अगस्त से होगी। इससे पहले, जियोस्टार द्वारा आयोजित पीकेएल प्री-सीजन मीडिया डे पर गुजरात जायंट्स के कप्तान मोहम्मदरेजा शादलू और बंगाल वॉरियर्स के कोच नवीन कुमार ने मीडिया से बातचीत की। शादलू ने कहा, यह सीजन मेरे लिए अलग है क्योंकि मैं इस बार टीम का कप्तान हूं। हमारी टीम तैयार है और हमारे खिलाड़ी मोटिवेट हैं और वे यह खिताब जीतना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम यह खिताब जीत पाएंगे।इस ईरानी खिलाड़ी ने आगे कहा, मैंने यहां के खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा है। मुझे इस देश में नए दोस्त मिले हैं। शादलू को 12वें सीजन के लिए हुए ऑक्शन में गुजरात जायंट्स ने 2.23 करोड़ रुपए में खरीदा था।

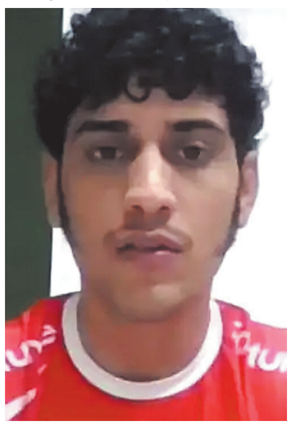

हमने इस सीजन में एक युवा टीम बनाई- नवीन –नवीन कुमार ने कहा, हमने इस सीजन में एक युवा टीम बनाई है और कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया है। नवीन ने कहा, हमने देवांक दलाल को ज्यादा कीमत में खरीदा है और वह हमारे टीम लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। सीजन-11 के बेस्ट रेडर रहे देवांक को बंगाल ने इस सीजन के लिए 2.205 करोड़ रुपए में खरीदा था। उन्होंने आगे कहा, खेल पर होम ग्राउंड और फैंस का सपोर्ट काफी असर डालता है। किसी खिलाड़ी और टीम को जितना ज्यादा समर्थन मिलता है, वे उतने ही ज्यादा प्रेरित होते हैं। एक खिलाड़ी तभी अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सकता है जब उसके फैंस उसके साथ हों, उसका उत्साहवर्धन करें और उसे प्रेरित करें।

पटना ने सबसे ज्यादा 3 खिताब जीते –प्रो-कबड्डी लीग की शुरुआत जुलाई 2014 में हुई। जयपुर पिंक पेंथर्स टीम ने नवनीत गौतम की कप्तानी में पहले सीजन का खिताब जीता। दूसरे सीजन में अनूप कुमार की कप्तानी वाली यू मुंबा चैंपियन बनी। तीसरे सीजन में पटना पाइरेट्स ने खिताब उठाया और टीम ने लगातार 3 फाइनल जीतकर खिताबी हैट्रिक बनाई।

दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका 277 रन पर ऑलआउट

ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने 5 विकेट लिए

मैकाय (एजेंसी)। मैकाय में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम 49.1 ओवर में 277 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से मैथ्यू ब्रिट्जके ने 88 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 74 रनों की पारी खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 89 रनों की अहम साझेदारी की। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी 10 ओवरों में वापसी की। एक समय 233/5 के स्कोर से साउथ अफ्रीका ने 31 रन जोड़ते हुए 5 विकेट गंवाए। टीम पूरे 50 ओवर भी बैटिंग नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। एडम जम्पा ने 3 विकेट लिए, जबकि ट्रैविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने मिलकर 2 विकेट झटके। नाथन एलिस ने भी 2 विकेट हासिल किए। तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने शुरुआती झटके दिए और कप्तान ऐडन मार्करम को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा।

ब्रिट्जके ने लगातार चौथा अर्धशतक लगाया

साउथ अफ्रीका के लिए ब्रिट्जके ने लगातार चौथा अर्धशतक लगाया और वह चार मैचों के बाद वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वहीं स्टब्स ने 16 पारियों के बाद पहली बार पचास का आंकड़ा छुआ। अंतिम ओवरों में खराब शॉट सिलेक्शन और लगातार विकेट गिरने से साउथ अफ्रीका बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका गंवा बैठा। ब्रिट्जके ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 89 रनों की साझेदारी की।

- **आखिरी 10 ओवरों में स्पिनर्स ने पकड़ बनाई** – ऑस्ट्रेलिया के स्पिनरों ने आखिरी 10 ओवरों में पकड़ बनाई और साउथ अफ्रीका को 280 से नीचे रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिनमें से 3 स्पिनर थे। एडम जम्पा, ट्रैविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने मिलकर 17 ओवर में 94 रन दिए और 5 विकेट लिए।
- **नाथन एलिस को 2 विकेट** – नाथन एलिस सबसे सफल तेज गेंदबाज रहे। उन्होंने 46 रन देकर 2 विकेट लिए। जेवियर बार्टलेट ने बेन ड्वार्शुइस की गैरमौजूदगी में अच्छी गेंदबाजी की। अपने तीसरे ह्ष्ट्ढ में खेलते हुए बार्टलेट ने नई गेंद संभाली। उन्होंने स्टैंड-इन कप्तान ऐडन मार्करम को चौथी ही गेंद पर मिडविकेट पर कैच करा दिया। वे शून्य के स्कोर पर पवेलियन लौटे। बतौर कप्तान मार्करम का औसत 24.28 रहता है, जबकि कप्तान न होने पर 40.63 का है। टेम्बा बावुमा की चोट (हैमस्ट्रिंग) से वापसी के बाद उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उन्हें आराम दिया गया है। रायन रिकेल्टन भी बार्टलेट और जोश हेजलवुड के सामने टिक नहीं सके और बार्टलेट की गेंद पर आउट हो गए।

बीसीसीआई ने क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के लिए आवेदन मंगाया

सीनियर मेंस, विमेंस और जूनियर मेंस लिए पोजिशन खाली ; एस शरत को हटाया जा सकता है

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को मेंस सीनियर क्रिकेट टीम सिलेक्शन कमेटी के सदस्य के दो पद के लिए आवेदन मंगाए हैं। बीसीसीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बीसीसीआई ने इकसे अलावा विमेंस टीम सिलेक्शन कमेटी के लिए चार और जूनियर मेंस के लिए एक पद के लिए आवेदन मंगाया हैं। आवेदन भरने की आखिरी तारीख 10 सितंबर है।

एस शरत को हटाया जा सकता है – रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है। फिलहाल, सिलेक्शन कमेटी में अगरकर, एसएस दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरत शामिल हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में होने वाली एनुअल जरनल बॉडी मीटिंग के बाद सीनियर सिलेक्शन कमेटी में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। शरत सितंबर 2021 में जूनियर सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे और जनवरी 2023 में सीनियर सिलेक्शन कमेटी में प्रमोट हुए थे।

मेंस सीनियर सिलेक्शन कमेटी- आवेदन करने के लिए ये योग्यता जरूरी

- 7 टेस्ट मैच खेले हो।
- 30 फर्स्ट क्लास मैच खेले हो।
- या 10 वनडे और 20 फर्स्ट क्लास मैच का अनुभव हो।
- आवेदन करने वाले खिलाड़ी के संन्यास को कम से कम पांच साल का समय बीत गया हो।
- विमेंस सिलेक्शन कमेटी- आवेदन करने के लिए ये योग्यता जरूरी
- पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय विमेंस नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
- संन्यास को कम से कम पांच साल का समय बीत गया हो।
- बीसीसीआई की किसी भी क्रिकेट कमेटी का 5 सालों से सदस्य न हो।
- जूनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी- आवेदन करने के लिए ये योग्यता जरूरी
- कम से कम 25 फर्स्ट क्लास मैच खेले हो।
- कम से कम 5 साल पहले खेल से संन्यास लिया हो।
- बीसीसीआई की किसी भी क्रिकेट कमेटी का 5 सालों से सदस्य न हो।

फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए करुण नायर, बड़े टूर्नामेंट से हो सकते है बाहर

नईदिल्ली (एजेंसी)। अनुभवी भारतीय बल्लेबाज करुण नायर को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि बीसीसीआई ने उन्हें केएससीए महाराजा टी20 ट्रॉफी में भाग लेने से रोक दिया है। 34 वर्षीय इस खिलाड़ी को सीओई से फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला है इसलिए उन्हें अपनी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया जारी रखनी होगी।

नायर केएससीए महाराजा टी20 ट्रॉफी के आगामी सीजन में मैसूर वॉरियर्स के लिए खेलने वाले थे और टीम के साथ मैसूर भी गए थे। लेकिन अब वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वापस लौटेंगे और बीसीसीआई से फिटनेस क्लियरेंस मिलने तक रिहैबिलिटेशन करेंगे।

नायर को इंग्लैंड के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में समाप्त हुए एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवे और अंतिम टेस्ट के दौरान उंगली में गहरी चोट लगी थी। इस बल्लेबाज की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप बिना स्पॉन्सर के खेलेगी !

बीसीसीआई सचिव ने कहा अगर यह जायज नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे

नईदिल्ली (एजेंसी)। आगामी पुरुष एशिया कप में टीम इंडिया पर बिना लोगो वाली जर्सी पहनने का खतरा मंडरा रहा है। यह स्थिति 'ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक' के पारित होने के बाद उत्पन्न हुई है। हाल ही में पारित इस विधेयक में ड्रीम11 जैसे सभी प्रकार के ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स और जुआ प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एशिया कप 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है। ड्रीम11 जुलाई 2023 से भारत का प्रमुख प्रायोजक है। शुरुआती अनुबंध के तहत इस ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के पास तीन साल के लिए प्रायोजन अधिकार थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अभी तक ड्रीम11 के साथ अपने भविष्य के जुड़ाव के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, अगर यह जायज नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बीसीसीआई केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई देश की हर नीति का पालन करेगा।

शुक्रवार को ड्रीम 11 ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि भारतीय संसद में विधेयक पारित होने के बाद नकद खेल और प्रतियोगिताएं बंद कर दी गई हैं। गौर हो कि ऑनलाइन पैसे वाले खेलों और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक ने अब ऐसे खेलों के प्रचार और वित्तपोषण को अपराध घोषित कर दिया है, जिसके तहत अपराधियों को 5 साल तक की जेल हो सकती है। स्पोर्टस्टार के अनुसार सरकारी आंकड़े बताते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ने 45 करोड़ लोगों से सालाना 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर की ठगी की है।

श्रुति, सारिका और काजल का शानदार प्रदर्शन, अंडर-20 विश्व कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंचीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। श्रुति ने महिलाओं के 50 किग्रा भारवर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में वायलेटा बिरियुकोवा पर 5-4 की जीत से शुरुआत की और फिर पोलैंड की अन्ना यात्स्केविच पर 4-0 की शानदार जीत दर्ज की।

भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन जारी रखा जिसमें पहलवान श्रुति, सारिका और काजल ने गुरुवार को अपने भार वर्गों के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। ग्रीको रोमन पहलवान सूरज ने 60 किग्रा वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बनाई लेकिन प्रिंस (82 किग्रा) क्वार्टर फाइनल में हार गए। श्रुति ने महिलाओं के 50 किग्रा भारवर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में वायलेटा बिरियुकोवा पर 5-4 की जीत से शुरुआत की और फिर पोलैंड की अन्ना यात्स्केविच पर 4-0 की शानदार जीत दर्ज की।

सारिका ने 53 किग्रा भारवर्ग में दबदबा बनाया। उन्होंने सेवल केयर को तकनीकी श्रेष्ठता (12-2) से हराया। इसके बाद सारिका ने चीन की तियानयु सुन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में एक भी अंक नहीं गंवाया और 8-0 से जीत हासिल की। अब उनका मुकाबला यूक्रेन की अनास्तासिया पोल्स्का से होगा। काजल ने 72 किग्रा वर्ग में तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर एमिली मिहाइलोवा अपोस्टोलोवा को 15-4 से हराकर शानदार जीत हासिल की।

यूएस ओपन 2025: सबालेंका को रायबाकिना से मिल सकती है चुनौती, गॉफ और स्विएटेक एक ही ग्रुप में

पोलैंड (एजेंसी)। पोलैंड की इगा स्विएटेक ने लिंडनर फैमिली टेनिस सेंटर में वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के सेमीफाइनल मैच के बाद कोको गॉफ को बधाई दी। न्यूयॉर्क में होने वाले 2025 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए विमेंस के सिंगल्स ड्रॉ की घोषणा गुरुवार को की गई। मौजूदा चैंपियन एरीना सबालेंका को इस बार खिताब बचाने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका ड्रॉ काफी मुश्किल दिख रहा है। पिछले साल सबालेंका ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को फाइनल में हराकर अपना पहला यूएस ओपन खिताब जीता था। इसके साथ ही वह आठ साल बाद पहली ऐसी महिला बनीं, जिन्होंने एक ही सीजन में दोनों हार्ड-कोर्ट ग्रैंड स्लैम (ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन) जीते।

गॉफ और स्विएटेक एक ही ग्रुप में – कोको गॉफ और इगा स्विएटेक एक ही ग्रुप में हैं। दोनों ही यूएस ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी स्विएटेक पहले राउंड में कोलंबिया की एमिलियाना अरांगो से भिड़ेंगी। तीसरे राउंड में उनकी मुलाकात 29वीं वरीयता प्राप्त अन्ना कालिन्सकाया से हो सकती है, जबकि चौथे राउंड में 13वीं वरीयता प्राप्त एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा चुनौती पेश कर सकती हैं।

- **सबालेंका को टूर्नामेंट में दूसरी सीड दी गई है** – बेलारूस सबालेंका को टूर्नामेंट में दूसरी सीड दी गई है। वह अपने खिताब बचाव की शुरुआत स्पेन की रेबेका मासारोवा के खिलाफ करेंगी। तीसरे राउंड में उनकी भिड़ंत 2021 की फाइनलिस्ट लेलाह फर्नांडिस से हो सकती है, जो हाल ही में सिटी ओपन में चैंपियन बनी थीं और 31वीं वरीयता प्राप्त हैं। अगर सबालेंका चौथे राउंड तक पहुंचती हैं, तो उनका सामना नौवीं वरीयता प्राप्त कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना से हो सकता है। रायबाकिना ने पिछले हफ्ते सिनसिनाटी ओपन में सबालेंका को सीधे सेटों में हराया था। क्वार्टर फाइनल पार करने पर सेमीफाइनल में सबालेंका की टक्कर फिर से जेसिका पेगुला से हो सकती है। पेगुला पहला राउंड मिस्त्र की मायार शरीफ के खिलाफ खेलेंगी और उनकी क्वार्टर फाइनल में पांचवीं वरीयता प्राप्त मिर्रा एंड्रीवा से भिड़ंत हो सकती है।

संक्षिप्त समाचार

बस-एम्बुलेंस की टक्कर में छह लोगों की मौत, मुख्यमंत्री मरियम ने जताया शोक

लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले में एक यात्री बस और एम्बुलेंस की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चार रेस्क्यू कर्मी शामिल हैं। गुरुवार को हादसा तब हुआ जब बस ने एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में सामने से आ रही रेस्क्यू वाली गाड़ी 1122 एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। चार रेस्क्यू कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए। दो घायलों की हालत गंभीर है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने हादसे पर दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की।

डेल्टा और यूनाइटेड एयरलाइंस पर धोखा देने का केस

न्यूयॉर्क, एजेंसी। इस हफ्ते न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने खिड़की वाली सीट बताकर यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूले, जबकि कई सीटों के पास खिड़की थी ही नहीं सिर्फ दीवार थी। यह मुकदमे न्यूयॉर्क की एक कानून फर्म ने दर्ज किए हैं और ये सामूहिक मुकदमे हैं, यानी कोई भी यात्री जिसने ऐसी सीट बुक की हो, इस केस का हिस्सा बन सकता है। कानून फर्म ने कहा कि हमें बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस केस से जुड़ना चाहते हैं। जब लोग खिड़की के लिए पैसे देते हैं, तो उन्हें खिड़की मिलनी भी चाहिए। डेल्टा और यूनाइटेड दोनों एयरलाइंस ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है क्योंकि केस कोर्ट में चल रहा है।

शट्टा वेले अमेरिकी धोखाधड़ी केस की जांच में गिरफ्तार, बाद में मिली जमानत

अक्रा, एजेंसी। घाना के मशहूर सिंगर शट्टा वेले को अमेरिका में चल रहे एक धोखाधड़ी मामले से जुड़े जांच के सिलसिले में हिरासत में लिया गया। यह मामला उनकी 2019 मॉडल की लग्जरी कार लेम्बोर्गिनी उरुस से जुड़ा हुआ है। घाना की आर्थिक और संगठित अपराध कार्यालय ने बताया कि शट्टा वेले खुद बुधवार को पूछताछ के लिए पेश हुए थे। यह पूछताछ अमेरिका सरकार की ओर से आए अनुरोध पर हो रही है। उन्हें गुरुवार को जमानत पर छोड़ दिया गया। जांच एक 4 मिलियन डॉलर (करीब 33 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी से जुड़ी है, जो अमेरिका में कुछ घानावासियों द्वारा की गई थी। इस धोखाधड़ी में कमाई गई रकम से खरीदी गई चीजों का पता लगाया जा रहा है। इस केस का मुख्य आरोपी नाना क्वाबेना अमुआह है, जिसे 2023 में अमेरिका की अदालत ने 7 साल की सजा दी थी। उस पर आरोप था कि उसने लेक्सिंगटन, केंटकी शहर को गैर-लाभकारी संगठनों के नाम पर धोखा देकर पैसे ठग लिए।

फलस्तीनी गुटों ने हथियार सौंपने की प्रक्रिया शुरू की, लेबनानी सेना को सौंपी पहली खेप

बेरूत, एजेंसी। बेरूत के पास एक फलस्तीनी शरणार्थी कैंप में मौजूद कुछ फलस्तीनी गुटों ने गुरुवार को अपने पास रखे हथियार लेबनानी सेना को सौंपने की शुरुआत की। यह कदम उन योजनाओं का हिस्सा है जो तीन महीने पहले घोषित की गई थी, जिसके तहत इन कैंपों से हथियार हटाए जाने हैं। पहले दिन एक छोटी सी शुरुआत हुई, एक पिकअप ट्रक कैंप से निकला जिसमें बैगों में बंद हथियार रखे थे। कुछ बैगों से मशीन गनों के पिछले हिस्से और रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स झांकते हुए दिखाई दिए। इस योजना की घोषणा मई में उस समय हुई थी जब फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने लेबनान का दौरा किया था। उन्होंने और लेबनान के राष्ट्रपति जोसफ आउन ने मिलकर कहा था कि हथियारों का नियंत्रण अब लेबनानी सरकार के पास होगा। लेकिन अभी तक सभी फलस्तीनी गुट इस फैसले से सहमत नहीं हैं। हमास और उससे जुड़े गुट पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

कोलंबिया में एयरबेस के पास ट्रक में ब्लास्ट

कोकीन की खेती नष्ट करने जा रहे पुलिस हेलिकॉप्टर पर भी ड्रोन हमला; अबतक 18 की मौत

बोगोटा, एजेंसी। कोलंबिया में गुरुवार को दो अलग-अलग हमलों में 18 लोगों की मौत हो गई। कोलंबिया के कैली शहर में गुरुवार को एयर बेस के पास एक ट्रक में बम विस्फोट हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 71 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका मार्को फिदेल सुआरेज सैन्य एविएशन स्कूल के पास हुआ। इससे कुछ घंटे पहले, कोकीन की फसलों को खत्म करने के लिए जा रहे पुलिसकर्मियों के हेलिकॉप्टर पर ड्रोन से हमला हुआ। जिसमें 12 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने कहा कि इन हमलों के पीछे विद्रोही संगठन एफएआरसी के गुटों का हाथ है। एफएआरसी का मकसद कोलंबियन सरकार को उखाड़ फेंकना है। हालांकि, 2016 में एक शांति समझौते के बाद ये संगठन भंग हो गया था, लेकिन कई इलाकों में ड्रग्स सप्लाई में ये अभी भी एक्टिव है।

शहर में बड़े ट्रकों के एंट्री पर रोक लगी: कैली के मेयर ने हमले की निंदा की और जिम्मेदार लोगों की जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की। प्रत्यक्षदर्शी ने एएफपी न्यूज को बताया कि एयर बेस के पास किसी चीज के फटने की तेज आवाज आई। घटना के बाद आसपास के कई इमारतों और स्कूलों को खाली करा लिया गया है। साथ ही मेयर ने शहर में बड़े ट्रकों के एंट्री पर रोक लगाने की घोषणा की है।

रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने विस्फोट को आतंकवादी हमला बताया और इसके लिए नार्को कार्टेल (ड्रग्स तस्करी करने वाला गिरोह) ग्रुप गल्फ क्लान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, राष्ट्रपति और सैन्य नेतृत्व ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आज एक विशेष बैठक बुलाई है।

कोकीन उगाने में कोलंबिया सबसे आगे: कोलंबिया में ड्रग्स की खेती, खासकर कोका की खेती होती है। कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश है, जो वैश्विक कोकीन आपूर्ति का लगभग 60-70प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है। कोकीन का पौधा कोलंबिया के दूरदराज और गरीब इलाकों जैसे नारीनो, काउका, पुटुमायो, और कैकेटा में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। 2023 में, कोलंबिया में कोका की खेती 2.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई, जो 2022 की तुलना में 10प्रतिशत अधिक है। कोलंबिया के ग्रामीण इलाकों में गरीबी, बुनियादी ढांचे की कमी और सरकारी उपस्थिति का अभाव कोका की खेती को बढ़ावा देता है। यह स्थानीय किसानों के लिए एक स्थिर आय का माध्यम है, क्योंकि कोका की फसल दूसरी पारंपरिक फसलों (जैसे कॉफी) की तुलना में ज्यादा लाभकारी और कम मेहनत वाली होती है।

मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकते हैं लोग? 800 लोगों ने दिखाई उम्मीद

वाशिंगटन , एजेंसी। मौत एक अंतिम सत्य है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान अब इस धारणा को भी चुनौती देने लगा है। एक ऐसी तकनीक जो मरने के बाद भी जीवन की उम्मीद देती है – इसे कहते हैं क्रायोनिक्स । आज दुनिया भर में कई वैज्ञानिक और निजी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। उनका दावा है कि अगर किसी इंसान या जानवर के शरीर को बेहद ठंडे तापमान पर सुरक्षित रखा जाए, तो भविष्य में नई तकनीकों से उसे फिर से जीवित किया जा सकता है। इस तकनीक में 800 से ज्यादा लोग अब तक आवेदन कर चुके हैं।

क्या है क्रायोनिक्स तकनीक?: क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्लिनिकली मृत व्यक्ति (यानि जिसका दिल और दिमाग काम करना बंद कर चुका हो) के शरीर को -196एंट तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रक्रिया का मकसद है शरीर की कोशिकाओं को सड़ने या टूटने से बचाना। इसमें शरीर के टिश्यू से पानी को निकालकर उसमें क्रायोप्रोटेक्टेंट भरा जाता है, ताकि वह बर्फ में न बदले बल्कि ग्लास-जैसी अवस्था में बदल जाए। इसके बाद शरीर को स्टील कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अनिश्चितकाल तक स्टोर किया जाता है। आशा यह है कि भविष्य में जब टेक्नोलॉजी और मेडिसिन काफी विकसित हो जाए, तब ऐसे शरीरों को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा।

दिमाग को अलग से क्यों स्टोर किया जाता है?: कुछ लोग सिर्फ अपने मस्तिष्क (ब्रेन) को फ्रीज करवाते हैं। इसका कारण यह मान्यता है कि इंसान की स्मृति, चेतना और व्यक्तित्व दिमाग में ही बसते हैं। भविष्य में यदि सिर्फ दिमाग को किसी कृत्रिम शरीर या डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जा सके, तो व्यक्ति को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को किया गया गिरफ्तार, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एक्शन

कोलंबो , एजेंसी। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को कोलंबो में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है, जब वह अपनी पुराने एक भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए सीआईडी के ऑफिस पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शुक्रवार को एफसीआईडी के सामने पेश हुए थे। यहां पर वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। अधिकारियों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। बता दें कि विक्रमसिंघे जुलाई 2022 में गोटाबाया राजपक्षे के शेष कार्यकाल के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे। कथित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के विरोध में महीनों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने अपना पद छोड़ दिया था।

बताया जाता है कि श्रीलंका में साल 2022 में देश में आए सबसे बुरे वित्तीय संकट के लिए राजपक्षे को ही जिम्मेदार माना जाता है। विक्रमसिंघे सितंबर में अपनी पुनः चुनावी बोली हार गए थे।

हमास के लिए खुलेगा नरक का दरवाजा, इजरायल ने कब्जा करने को लेकर दी फाइनल वॉर्निंग

येरूसलम, एजेंसी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि अगर हमास निरस्त्रीकरण, फिलिस्तीनी क्षेत्र में बचे हुए सभी बंधकों को रिहा करने और तेल अवीव की शर्तों पर युद्ध खत्म करने पर सहमत नहीं हुआ तो वह गाजा शहर को तबाह कर दिया जाएगा।

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब इजरायल इस क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ÷जल्द ही गाजा में हमास के हत्यारों और बलात्कारियों के सिर पर नरक के द्वार खुल जाएंगे - जब तक कि वे युद्ध समाप्त करने के लिए इजरायल की शर्तों पर सहमत नहीं हो जाते, मुख्य रूप से सभी बंधकों की रिहाई और उनका निरस्त्रीकरण।÷

गाजा को बना देंगे राफा: उन्होंने कहा, ÷अगर वे सहमत नहीं होते हैं तो हमास की राजधानी गाजा, राफा और बेत हनून बन जाएगी।÷ उनका इशारा गाजा के उन दो शहरों की ओर था, जो पिछले इजरायली अभियानों के दौरान बड़े पैमाने पर नष्ट हो गए थे।

उनकी यह टिप्पणी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सेना को गाजा शहर पर कब्जा करने का अधिकार देंगे। नेतन्याहू ने गाजा में बचे हुए सभी बंधकों को छुड़ाने के लिए तत्काल बातचीत का आदेश दिया है।

गाजा पर कब्जा करने के लिए बुलाए रिजर्व सैनिक: इस सप्ताह की शुरुआत में इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने गाजा शहर पर कब्जा करने में मदद के लिए लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की इजाजत दी थी। नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा, ÷ये दोनों मामले - हमास को हराना और हमारे सभी बंधकों को रिहा करना - एक साथ चलते हैं।÷ आधाकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमास के हमले में 1219 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे।

अमेरिका में 5.5 करोड़ वीजा पर लटकी तलवार ! ट्रक ड्राइवरों पर भी लग सकता है बैन

वाशिंगटन , एजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली है, तब से वह लगातार अवैध अप्रवासी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है।

दरअसल, अमेरिका ने सभी विदेशी ट्रक ड्राइवरों के लिए वीजा जारी करना तुरंत बंद कर दिया है। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी।

21 अगस्त को एक पोस्ट में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने लिखा कि हम तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए वर्कर वीजा जारी करने पर रोक लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फैसले के पीछे की वजह अवैध रूप से अमेरिका गया हरजिंदर सिंह है, जिसकी एक गलती से एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई।

अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्या कहा?: एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री ने लिखा कि हम तत्काल प्रभाव से वाणिज्यिक ट्रक चालकों के लिए श्रमिक वीजा जारी करना रोक रहे हैं। अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक चालकों की आजीविका को प्रभावित कर रही है।

ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी विदेश मंत्री की ये घोषणा अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) द्वारा हरजिंदर सिंह के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के तुरंत बाद आई है। बता दें कि डीएचएस ने फ्लोरिडा राजमार्ग सुरक्षा एवं मोटर वाहन विभाग के हवाले से बताया कि सिंह नामक एक अवैध विदेशी ने 12 अगस्त को केवल आधिकारिक उपयोग वाले प्रवेश बिंदु से अवैध रूप से यू-टर्न लेने का प्रयास किया, जिससे उसके ट्रक ने राजमार्ग की सभी लेन अवरुद्ध कर दीं और परिणामस्वरूप दुर्घटना हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई।

बता दें कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल के अंत में एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, अमेरिका में संचालित सभी वाणिज्यिक ट्रक ड्राइवरों को अंग्रेजी में दक्ष होना अनिवार्य किया गया था। वहीं, द हिल ने व्हाइट हाउस के एक आदेश का हवाला देते हुए बताया कि ट्रक चालकों को ट्रैफिक संकेतों को पढ़ने और समझने, ट्रैफिक सुरक्षा सीमा गश्ती, कृषि चौकियों और कार्गो भार-सीमा स्टेशन अधिकारियों से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए।

चीन में पलक झपकते ही ढह गया विशाल पुल का हिस्सा

कम से कम 7 की मौत वीडियो में दिखी तबाही

बीजिंग, एजेंसी। चीन में एक अंडर कंट्रक्शन पुल का बड़ा हिस्सा गिर जाने के बाद कई लोगों के मौत की खबर है।चीन की सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक निर्माणाधीन पुल की रस्सी टूट गई। हादसे में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 9 अन्य लोग लापता हो गए हैं। बता दें कि यह पुल हुआंगनान तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के जियांझा काउंटी और चीन के किंघई प्रांत के हैदोंग में हुआलोंग के बीच की सीमा पर स्थित है। पुल चीन के किंघई प्रांत को येलो रिवर से जोड़ता है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार हादसा तड़के लगभग तीन बजे हुआ। इस समय पुल पर 15 मजदूर और एक मैनेजर भी मौजूद थे। पलक झपकते ही पुल भड़भड़ाकर गिर पड़ा जिससे लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विशाल पुल का एक हिस्सा पानी में गिरता नजर आ रहा है। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नदी में गिरे लोगों की तलाश के लिए एक टास्क फोर्स को मौके पर भेजा गया है। खोज और बचाव अभियान के लिए सैकड़ों बचावकर्मियों को तैनात किया गया है। चीनी अधिकारियों ने बताया है कि घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। पीपुल्स डेली के अनुसार, सिचुआन-किंघई रेलवे पर बना यह पुल दुनिया का सबसे बड़ा डबल-ट्रैक स्टील ट्रस आर्च ब्रिज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह येलो रिवर पर बना चीन का पहला रेलवे स्टील ट्रस आर्च ब्रिज भी है, जो देश का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है।

भारतीय की लापरवाही से हुई दुर्घटना, अमेरिका ने सभी विदेशी ट्रक ड्राइवरों का वीजा रोका

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सरकार ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों को वीजा देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया। दरअसल अमेरिका में एक भारतीय ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद अमेरिका में विदेशी ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ माहौल बन गया है और इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है।

विदेशी ट्रक ड्राइवरों को वीजा जारी होने पर लगी रोक: मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों को जारी होने वाले वीजा पर रोक लगाई जाती है। अमेरिका की सड़कों पर विदेशी ट्रक ड्राइवरों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये ट्रक और ट्रेलर चालक अमेरिकी लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं और साथ ही अमेरिकी ट्रक चालकों की आजीविका में भी सेंध लगा रहे हैं। भारतीय ट्रक ड्राइवर की

लापरवाही से हुआ हादसा दरअसल फ्लोरिडा के राजमार्ग पर एक भारतीय ट्रक ड्राइवर ने गलत तरीके से यू-टर्न लिया, जिससे एक कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। आरोपी ट्रक ड्राइवर की पहचान हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो मेक्सिको के जरिए अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुआ था। संघीय अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ट्रक ड्राइवर अंग्रेजी परीक्षण में भी असफल रहा। अमेरिका में इस मामले की काफी चर्चा हो रही है क्योंकि यह घटना फ्लोरिडा में हुई, जो सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ है। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी का अवैध अप्रवासियों पर रुख सख्त रहा है।

इस मुद्दे पर गरमाई अमेरिकी राजनीति: अब आरोपी भारतीय ट्रक ड्राइवर को अमेरिका से निर्वासित करने की तैयारी हो रही है। इस मामले में राजनीति होने की वजह ये है कि हरजिंदर सिंह को ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस कैलिफोर्निया से मिला, जो कि डेमोक्रेट पार्टी का गढ़ है। अब ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम, हरजिंदर सिंह को ड्राइविंग लाइसेंस देने के जिम्मेदार हैं। हालांकि न्यूसम ने ट्रंप की संघीय सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।

जनता दरबार का किया गया आयोजन, डीडीसी ने सुनी जनता की समस्याएं

जनता दरबार में विभिन्न विभागों के मामले सुने गए-

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार द्वारा दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों एवं अन्य सभी आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना गया। इस दौरान अपर समाहर्ता मो मुमताज अंसारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष उपस्थित थे। मौके पर ही कई मामलों निष्पादन किया गया। उक्त जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखा। मामलो के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियो से मांगे गए प्रतिवेदन।

मौके पर ही कई मामलों का किया गया निष्पादन

जिला मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान अबुआ आवास, स्वास्थ्य, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीएसएल क्षेत्र से संबंधित शिकायतें, चौकीदार नियुक्ति मामला, विस्थापितों के मामले आदि कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त सभी आवेदनों पर सुनवाई करते हुए अधिकांश शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों के आवेदन को संबंधित विभागों को शीघ्र निष्पादन हेतु भेजा गया।

बधाई हो, बेटी हुई है कार्यक्रम के तहत बेटियों का जन्मोत्सव मनाया गया

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। जिला समाज कल्याण विभाग के आदेश पर बाल विकास परियोजना गोमिया द्वारा आज बधाई हो, बेटी हुई है कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया के मातृशिशु वार्ड में आयोजन किया गया। मौके पर बीडीओ गोमिया महादेव महतो, अंचल अधिकारी सह सीडीपीओ गोमिया मो. आफताब आलम, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गोमिया डॉ बलराम मुखी, महिला पर्यवेक्षिका समेत अन्य उपस्थित थे। सबसे पहले अंचल अधिकारी सह सीडीपीओ गोमिया मो. आफताब आलम, बीडीओ गोमिया महादेव महतो, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गोमिया डॉ बलराम मुखी, महिला पर्यवेक्षिका व अन्य के द्वारा नवजात बेटियों के अभिभावकों को क्रमवार उनके घर बेटी होने की उन्हें बधाई दी गई तथा बेटी के जन्म की इस खुशी को साझा करते हुए सभी पदाधिकारियों ने अभिभावकों को मिठाई खिलाई उनका मुंह मीठा कराया गया। इसके साथ ही प्रसव के पश्चात आवश्यक मेडिकल किट और बच्चों से संबंधित किट प्रदान किए गए।

जन्म पर उनके अभिभावकों को बधाई दें तथा मिठाई खिलाया

कार्यक्रम में अंचल अधिकारी सह सीडीपीओ गोमिया मो. आफताब आलम, बीडीओ गोमिया महादेव महतो, ने कहा कि बेटी के जन्म को बोझ नहीं समझे, अपने आपको सौभाग्य समझें। साथ ही कहा कि अब जमाना बदल गया है बेटियों के जन्म को खुशी और उल्लास से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में मानसिक स्तर पर बेटियों को लेकर समानता का भाव नहीं आएगा, तब तक असल बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने सभी अपने-अपने क्षेत्रवासियों से आह्वान किया कि समाज में बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में समान अवसर दें। साथ ही, अपने आस पास बेटियों के जन्म पर उनके अभिभावकों को बधाई दें तथा मिठाई खिलाएं। प्रखंड विकास पदाधिकारी गोमिया महादेव महतो ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना जैसे कार्यक्रम में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का ही एक माध्यम है। यह आवश्यक है कि अभिभावक अपनी बेटियों को आगे बढ़ने की पूरी आजादी दें और उनको प्रोत्साहित करें। मौके पर कई चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं परिजन उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

बाइक चोरी गैंग का पर्दाफाशः तीन अभियुक्त गिरफ्तार

धनबाद/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। नगर पुलिस अधीक्षक ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि बाइक चोरी मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इनके पास से पांच मोटरसाइकिल बरामद की गई

हैं, जिनमें से दो को बेचने के लिए तैयार थे और तीन छुपा कर रखे गए थे। पुलिस ने बताया कि ये बाइकें धनबाद और आसपास के क्षेत्रों से चोरी की गई थीं और इन्हें बेचने के लिए चेचिस नंबर और इंजन नंबर बदल दिए जाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में दो तीसरा थाना क्षेत्र और एक बलियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने फुटबॉल मैदान काशी टांड़ से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का सरगना सोनू सिन्हा है, जो पहले से ही आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। सोनू सिन्हा का मोटरसाइकिल चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने का इतिहास रहा है।

रोजगार मेला में 17 अभ्यर्थियों को मिला नियोजन

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। अवर प्रादेशिक नियोजनालय, बोकारो द्वारा आईटीआईआई परिसर, चास में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। उक्त मेला में निजी क्षेत्र के कुल 12 प्रतिष्ठानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, जिसमें रोजगार मेला में 17 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। 26.2 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। उक्त बात की जानकारी नियोजन पदाधिकारी,

अवर प्रादेशिक नियोजनालय प्रत्यूष शेखर ने दी है। मौके पर नियोजनालय कार्यालय के कर्मचारियों किशोर कुमार सिन्हा, काशी नाथ हाँसदा, सुनील कुमार, संतोष कुमार, जयदेव कुमार, जयप्रकाश, चन्दन दास, अशोक कुमार, राधेश्याम पासवान एवं मुरारी पासवान ने मेला के सफल आयोजन में सहयोग किया।

तेज रफ्तार वरना कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसी

गिरिडीह/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। गिरिडीह में आज एक बड़ा हादसा हुआ है, यंहा गिरिडीह - देवघर मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करणपुरा के पास एक तेज रफ्तार वरना कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसी. कार के तालाब में घुसने के बाद आस - पास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे ओर मामले की जानकारी बेंगाबाद थाना पुलिस को दी. सूचना मिलने के तुरंत बाद बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे ओर तालाब में छलांग लगा दी. कड़ी मशक्क्तत के बाद कार का शीशा तोड़कर एक युवती को बाहर निकाला ओर सीधे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जंहा चिकित्सकों नें युवती कि स्थिति को गंभीर देखते हुए सीधे आईसीयू में भेज दिया जंहा इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया. मृतका कि पहचान पचम्बा के बोड़ो (टीवी सेंटर) के समीप निवासी संजय सिन्हा कि पुत्री कोमल कुमारी के रूप में कि गयी. इधर घटना कि सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में लोगों कि भीड़ सदर अस्पताल पहुंच गयी, इस दौरान परिजनों के चित्कार से पुरा माहौल गमगीन हो गया रांची में रहकर यूपीएससी कि तैयारी कर रही थी कोमल घटना के बाद सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों नें बताया कि कोमल रांची में रहकर यूपीएससी कि तैयारी कर रही थी. कुछ दिन पहले ही वह गिरिडीह अपने घर आई थी ओर आज शाम अपने एक साथी के साथ वरना कार में बैठकर बेंगाबाद से गिरिडीह लौट रही थी. इसी दौरान इनकी कार अनियंत्रित होकर तालाब में घुस गयी. इधर पुलिस कार पर सवार युवक कि तलाश में जुटी हुई है, साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि कार कोई ओर चला रहा था या फिर कोमल खुद कार ड्राइव कर रही थी. पुलिस हर एंगल से घटना कि जांच में जुटी हुई है.

ठेका श्रमिकों को अगस्त महीने के वेतन के साथ बोनस का भी भुगतान किया जाए : प्रेम कुमार

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय सेक्टर 4जी में बोकारो स्टील प्लांट में कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता असंगठित क्षेत्र के अध्यक्ष रामा शंकर शर्मा ने की। संचालन पी सी झा ने किया। सभी श्रमिकों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। संघ के महामंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि मजदूरों के हितों कि रक्षा की जाएगी।, बी एस एल प्रबंधन को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनाना होगा। ठेका श्रमिकों को बोनस कम से कम 25 हजार रुपया सितम्बर माह के पहले सप्ताह में देना होगा। ई एस आई सी के मेडिकल सुविधा का मापदंड को बढाकर 35 हजार रुपए करना होगा ताकि सारे मजदूरों को मेडिकल कि सुविधा मिल सके ' सभी कामगारों को एक सुनिश्चित मापदंड के तहत प्रमोशन देना होगा। सुरक्षा की पूरी सामग्री समय पर दिया जाय ' खाली पड़े आवास को ठेका कंपनी के माध्यम से ठेका श्रमिकों को दिया जाय। शहर मे ही ई एस आई सी का हॉस्पिटल पूरी व्यवस्था के साथ चालू किया जाय। बैठक मे मुख्य रूप से संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश कुमार, उपाध्यक्ष सत्यनारायण ठाकुर, अमित कुमार सिन्हा,कॉक ओवन के शाखा सचिव अमीर प्रवेज,हेमंत कुमार, संजय शर्मा, जगनाथ नपित, जय प्रकाश यादव,जीतेन्द्र पासवान, सुनील कुमार, नागेंद्र कुमार,कामता कुमार,योगेंद्र पासवान, धन बिहारी यादव, उमेश शर्मा, प्रताप कुमार ठाकुर,आदि उपस्थित रहे।

उप निर्वाचन पदाधिकारी, रंथू महतो ने की सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स के साथ बैठक

गिरिडीह/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। उप निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रंथू महतों ने एनआईसी सभागार में सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने नजरी नक्शा नक्शा, प्री रिविजन एक्टिविटी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की एवं निर्वाचन संबंधी कार्यों में तेजी लाने और समयबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही मतदाता पहचान-पत्र एवं मतदाता सूची बनाने के लिए जरूरी निदेशों व आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों को पूरी तत्परता के साथ करें और अपने वरीय अधिकारियों से समन्वय बनकर कार्य करें। जिससे कि पूरी पारदर्शिता के साथ निर्वाचन संबंधी कार्यों को पूरा किया जा सकें। बैठक में सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स समेत अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

75 खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती सम्पन्न

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। समाहरणालय स्थित सभागार में अपर समाहर्त्ता मो मुमताज अंसारी की अध्यक्षता में बोकारो जिला की कुल 75 खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती कुल 33 समूहों में ई-लॉटरी के माध्यम से ऑनलाईन विधि द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष-2025-26 की शेष अवधि के लिए सम्पन्न कराई गई। मौके पर सहायक आयुक्त उत्पाद उमा शंकर सिंह, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी धरंजय कुमार सहित सभी अधिनस्थ उत्पाद पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थिति थे।

बोकारो जिले से राज्य सरकार को कुल 125,13,46,059/- रुपए से अधिक उत्पाद राजस्व की होगी प्राप्ति- सहायक आयुक्त उत्पाद उमा शंकर सिंह ने बताया कि उक्त बन्दोबस्ती प्रक्रिया में कुल 546 आवेदक सम्मिलित हुए, जिसमें कुल-75 (पचहत्तर) खुदरा उत्पाद दुकान आवंटित की गई, जिससे राज्य सरकार को कुल 125,13,46,059/- (एक अरब 25 करोड़ 13 लाख 46 हजार 59 रुपए) रुपए से अधिक उत्पाद राजस्व की प्राप्ति होगी। यह खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती माह 01 सितम्बर 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए की गई है।

बीएसएल प्रबंधन ने टू-टैंक गार्डन को धरना स्थल के रूप में चिह्नित किया

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बीएसएल प्रबंधन द्वारा विभिन्न संगठनों एवं संघों की ओर से की जाने वाली धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों के लिए एक निश्चित जगह चिन्हित किया गया है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए बीएसएल प्रबंधन की ओर से टू-टैंक गार्डन को धरना स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी, चास सुश्री प्रांजल ढांडा के द्वारा भी एक आदेश निर्गत करते हुए इस धरना प्रदर्शन स्थल की जानकारी सार्वजनिक करने हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बीएसएल प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई है कि टाउनशिप सर्विस स्टेशन, गरगा डैम, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं ऐसे ही अन्य स्थल के आसपास के क्षेत्र संरक्षित स्थान घोषित हैं। ऐसे में सार्वजनिक सुरक्षा एवम विभिन्न संगठनों तथा संघों के प्रदर्शनकारियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से बीएसएल प्रबंधन द्वारा टू-टैंक गार्डन को धरना प्रदर्शन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है।

सिविल सर्जन कार्यालय की कार्यप्रणाली से एएनएम परेशान

जानबूझ कर परेशान करने का लगाया जा रहा है आरोप

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बोकारो जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में एनआरएचएम के तहत काम करने वाली लगभग 65 एएनएम को सिविल सर्जन कार्यालय के द्वारा अनुभव और स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। जबकि उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई वैकेंसी में आवेदन करने के लिए अब कुछ दिन बचे हुए हैं। जिस कारण एएनएम सिविल सर्जन कार्यालय के चक्कर लगा रही है। सिविल सर्जन कार्यालय में शाम 6 बजे तक बैठी एएनएम का दर्द साफ झलक रहा था। मीडिया से बात करते हुए कई एएनएम रो पड़ी। एएनएम का कहना है कि हम लोग पिछले 14 से 17 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रहे हैं। लगातार नियमित करने की मांग सरकार से कर रहे थे। अब हम लोगों के लिए नियमित बहाली निकली है तो सिविल सर्जन कार्यालय के द्वारा अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र के लिए हम लोगों को दौड़ाया जा रहा है। सिविल सर्जन कार्यालय में अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर गोमिया और पेटरवार से आई एएनएम रोने को मजबूर हो गई। इनका कहना है कि हमें अपने प्रमाण पत्र के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। इनका कहना है कि हम लोग घरों में बच्चों को छोड़कर आए हैं। बुधवार को कागज जमा किया गया। शुक्रवार को आने को कहा गया लेकिन शाम हो गई है। लेकिन हम लोगों का काम नहीं हुआ। कार्यालय के कर्मी हम लोगों का काम नहीं कर रहे हैं सिविल सर्जन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

ई-रिक्शा निबंधन के लिए डीटीओ ऑफिस में लगेगा विशेष कैम्प

धनबाद/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। ई-रिक्शा के निबंधन के लिए जिला परिवहन कार्यालय में विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि 23 से 30 अगस्त तक जिला परिवहन कार्यालय में विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ आकर ई-रिक्शा वाहन स्वामी अपने ई-रिक्शा का निबंधन करा लें तथा ड्रेस कोड का पालन करें। 30 अगस्त के उपरांत सरकार के निर्देशों का उलंघन पाये जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत उनपर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा ई-रिक्शा (टोटो) चालकों हेतु नीले रंग का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। पूर्व में भी परिवहन विभाग द्वारा दैनिक समाचार पत्र एवं जागरूकता के माध्यम से ड्रेस कोड के पालन हेतु अनुरोध किया गया। परंतु प्रायः यह देखा जा रहा है कि ई-रिक्शा चालकों द्वारा ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही यह सूचना मिल रही है कि कई ई-रिक्शा वाहन चालकों द्वारा बिना निबंधन के वाहन का परिचालन किया जा रहा है। बिना निबंधन का परिचालन मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन एवं राजस्व क्षति का मामला है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पशु प्रेमियों ने किया स्वागत

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स को भोजन और देखभाल का अधिकार दिया गया है, पशु अधिकार कार्यकताओं ने इस कदम का जोरदार स्वागत किया है। शंभू प्रसाद फाउंडेशन की सचिव सह अधिवक्ता प्रीति प्रसाद और सहयोगिनी के निदेशक गौतम सागर ने इस फैसले को "सकारात्मक और प्रगतिशील" बताया है। जानवरों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को दशार्ता है। इस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्ट्रीट डॉग्स भी अपने प्राकृतिक आवास में रहने और भोजन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिक भी स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, और इस काम को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रीति प्रसाद ने अपने बयान में कहा, "यह फैसला न केवल स्ट्रीट डॉग्स के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि इंसान और जानवर एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। यह हमें एक अधिक संवेदनशील और दयालु समाज की ओर ले जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जो जानवरों की देखभाल करते हैं और अक्सर समाज के विरोध का सामना करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गौतम सागर ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह एक मील का पत्थर है। यह दशार्ता है कि कानून जानवरों के कल्याण के प्रति गंभीर है। यह फैसला उन सभी भ्रांतियों को दूर करता है कि स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना एक अपराध है।" उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला सभी के लिए एक सबक है कि जानवरों के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट डॉग्स और मनुष्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना है। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि स्थानीय निकाय स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने के लिए उचित स्थान तय किए जाने चाहिए, ताकि स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। बोकारो के पशु अधिकार कार्यकताओं जिसमें निश्चित कुमार, सुशांत दुबे, अभिजीत कुमार,दीपमाला अग्रवाल, सुष्मिता दास, बबीता कुमारी आदि का मानना है कि यह फैसला देश सहित बोकारो के लिए एक मिसाल बनेगा और स्ट्रीट डॉग्स के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा।

राजगंज में दस दिवसीय एनसीसी कैंप का आयोजन

राजगंज/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बड्स गार्डेन स्कूल, दलूडीह, राजगंज में 10 दिवसीय एनसीसी कैंप का झारखंड बटालियन एनसीसी यूनिट, धनबाद" द्वारा आयोजित किया गया है। इस शिविर में मुख्य रूप से धनबाद ,दुमका, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह ,साहिबगंज, जामताड़ा जिले के अलावे राजगंज, बड्स गार्डेन स्कूल आदि के लगभग 550 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें लगभग 450 गर्ल्स कैडेट शामिल है। कैंप के आयोजन में कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल, कुमार रंजय सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। जबकि मुख्य सहयोगी के रूप में स्कूल के प्राचार्य, प्रमोद चौरसिया है। कैंप के आयोजन में प्रशिक्षण देने में सूबेदार राजेंद्र प्रसाद सैनी , सूबेदार ,भवानी सिंह ,सूबेदार ,जगदीप सिंह, सूबेदार, नरेंद्र जी, नायक सूबेदार , श्याम सिंह , कंपनी हवलदार मस्त बहादुर , नजीर असिस्टेंट , नरेंद्र जी, हवलदार साम सिंह, हवलदार, जोध सिंह, हवलदार फिलिप्स मरांडी, सी टी ओ,मोहम्मद अली हुसैन, जीसीआई, प्रियंका सिंह आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम, खेलकूद, योग,शूटिंग,सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण ,अभ्यास आयोजन किया जा रहा है। आज एनसीसी द्वारा वन विभाग के सहयोग से स्कूल परिसर में "एक पेड़ मां के नाम" योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाया गया, एवं कल दिनांक 24 अगस्त को विद्यालय में "ब्लड डोनेशन कैंप" का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कैंप में सम्मिलित बच्चे रक्तदान भी करेंगे। विद्यालय में आयोजित इस कैंप में कल अग्निशमन विभाग द्वारा आपातकालीन आग बुझाने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिए गए। कैंप में शामिल कैडैटस को प्रतिदिन फायरिंग की अभ्यास भी विद्यालय परिसर में ही कराई जाती है, साथ ही विशेष कक्षाओं का आयोजन कर बच्चों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रमुख बातें एवं देश सेवा से जुड़ी बातों को सिखाया जा रहा है। बड्स गार्डेन स्कूल , राजगंज में एनसीसी प्रशिक्षण पूर्व से ही दिए जा रहे थे, जबकि फिलहाल विद्यालय में लगभग 30 बॉयज कैडेट एवं 80 गर्ल्स कैडेट एनसीसी में शामिल है। इस शिविर के आयोजन होने से विद्यालय के बच्चों में भी उत्साह का माहौल है ,एवं विद्यालय में अध्यनरत अन्य बच्चे भी इस प्रशिक्षण को देखकर देश वह समाज के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो रहे हैं। विद्यालय में ही लगभग 5:30 सौ कैडैट्स और 50 प्रशिक्षकों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है।

दीपावली में पटाखा दुकान के लिए हर अंचल में चिह्नित किए जाएंगे एक-एक ग्राउंड

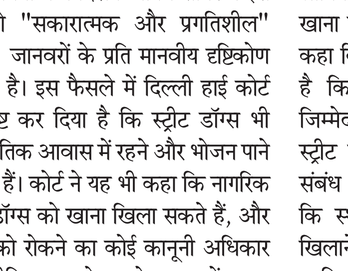

धनबाद/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। दीपावली में पटाखा दुकान लगाने के लिए हर अंचल में एक-एक ग्राउंड चिन्हित किए जाएंगे। वहीं जो दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखा बेचते पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित बैठक में दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पटाखा बिक्री के लंबित आवेदनों की समीक्षा की। साथ ही दीपावली के अवसर पर पटाखा विक्रेताओं को अस्थाई लाइसेंस देने पर चर्चा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने मैगजीन हाउस की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को मैगजीन हाउस का निरीक्षण कर प्लॉट सख्या की जांच तथा विशेष रूप से पत्थर एवं अन्य खदान में फायर सेफ्टी नियमों की जांच करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने आर्म्स लाइसेंस, जिले में लाइसेंसी हथियार की संख्या, नए आवेदन, रद्द हुए आवेदन इत्यादि की समीक्षा की। इसके बाद उपायुक्त ने जिला टेलीकॉम समिति के साथ बैठक कर जिले में स्थित मोबाइल टावरों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को सरकारी जमीन पर स्थापित टावर की जांच कर किराया निर्धारित करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित करने तथा बिना अनुमति सरकारी भूमि पर लगे टावरों को हटाने का निर्देश दिया।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक कमल किशोर द्वारा डी.बी. कॉर्प. लि. के लिए भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, गोविंदपुर मेन रोड, अशोक नगर, केजी आश्रम, धनबाद (झारखंड) से मुद्रित तथा प्लांट नंबर-31, कॉपरेटिव कॉलोनी, बोकारो स्टील सिटी, जिला बोकारो (झारखंड) से प्रकाशित। संपादक कमल किशोर, नवबिहार टाइम्स (दैनिक), सत्येंद्र नगर, औरंगाबाद (बिहार), स्थानीय संपादक : मनोज विशाल
फोन नंबर- 9431145665 8210783623
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या : JHAHIN/2017/72655
E-mail- nbtimesbihar@gmail.com

CMYK